शहर, ग्रामीण प्रवासी और शहरी गरीब:

हिंसा और सामाजिक न्याय के मुद्दे

अनुसंधान संक्षेप

के साथ

नीति क्रियान्वयन

रकाशित द्वारा: महानिर्बन कलकत्ता रिसर्च ग्रुप
जी.सी-४५ , सेक्टर - III, पहली मंज़िल
साल्ट लेक सिटी
कोलकाता -७००१०६

मुद्रित: ग्राफिक इमेज
न्यू मार्केट, न्यू कॉम्प्लेक्स,
वेस्ट ब्लॉक
द्वितीय तल, कमरा नंबर ११५ ,
कोलकाता -८७

यह प्रकाशन 'शहरों, ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों' परियोजना का एक हिस्सा है। हम सभी शोधकर्ताओं, चर्चाकर्ताओं और अन्य लोगों को इस परियोजना में शामिल होने और परियोजना से संबंधित कार्यक्रमों में धन्यवाद देते हैं। हम उनके समर्थन के लिए एम.सी.आर.जी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन का समर्थन कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते है।

शहर, ग्रामीण प्रवासी और शहरी गरीब: हिंसा और सामाजिक न्याय के मुद्दे

अनुसंधान संक्षेप
के साथ
नीति क्रियान्वयन

प्रकाशित द्वारा: महानिर्बन कलकत्ता रिसर्च ग्रुप
जी.सी-४५ , सेक्टर -III, पहली मंज़िल
साल्ट लेक सिटी
कोलकाता -७००१०६

मुद्रित: ग्राफिक इमेज
न्यू मार्केट, न्यू कॉम्प्लेक्स,
वेस्ट ब्लॉक
द्वितीय तल, कमरा नंबर ११५ ,
कोलकाता -८७

यह प्रकाशन 'शहरों, ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों' परियोजना का एक हिस्सा है। हम सभी शोधकर्ताओं, चर्चाकर्ताओं और अन्य लोगों को इस परियोजना में शामिल होने और परियोजना से संबंधित कार्यक्रमों में धन्यवाद देते हैं। हम उनके समर्थन के लिए एम.सी.आर.जी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन का समर्थन कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते है।

शहर, ग्रामीण प्रवासी और शहरी गरीब: हिंसा और सामाजिक न्याय के मुद्दे

अनुसंधान संक्षेप
के साथ
नीति क्रियान्वयन

विषय-सूची

प्रस्तावना..... 1-4

भाग एक: अनुसंधान संक्षेप

धारा 1 : कलकत्ता..... 7-25

1. शहर में शरण लेना: पोस्ट-भाग कलकत्ता में प्रवासित जनसंख्या और शहरी प्रबंधन

कौस्तुभ मनी सेनगुप्ता

2. समकालीन कोलकाता में शहरी नियोजन, सेटलमेंट प्रैक्टिस, और न्याय के मुद्दे

ईमन कुमार मित्रा

3. प्रवासी श्रमिक और समकालीन कोलकाता में अनौपचारिकता

ईमन कुमार मित्रा

4. कलकत्ता में महिलाओं और प्रवासी बच्चों का अध्ययन

देबारती बागची और साबिर अहमद

5. समकालीन कोलकाता में देखभाल अर्थव्यवस्था और महिलाओं का प्रवासन

माधुरीलता बासु

धारा 2 : दिल्ली 28-38

1.राजधानी शहर: कानून और नीति की भ्रामक विसंगति

अमित प्रकाश

2. साम्राज्य का टेरा फर्मा: प्रवासी श्रम का भूमि, अधिग्रहण और बनाना

मिथिलेश कुमार

3. दिल्ली के 'सर्विस' गांवों में काम करने और प्रवासी श्रमिकों के जीवन के 'क्षणिक' रूप

इशिता दे

धारा 3 : मुंबई..... 41- 54

1.मुंबई में बेघर प्रवासियों: शहरी जगह में जीवन और श्रम

मनीष झा और पुष्पेंद्र

2. समकालीन मुम्बई में एक समस्या चित्रा के रूप में प्रवासी के उदय: हिंसा का इतिहास और न्याय के मुद्दे

सिमप्रीत सिंह

3. खतरनाक कामकाज: मुंबई शहर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में मौत और वृद्धावस्था

मौलेश्री व्यास

4. प्रवासियों, सतर्कता और हिंसा: मुंबई में सुरक्षा गार्ड का एक अध्ययन

ऋतम्भरा हेब्बार और महुआ बंद्योपाध्याय

धारा 4 : सिलीगुड़ी और बिहार का कोसी क्षेत्र 57-64

1.उत्तर बंगाल में एक ट्रांजिट टाउन: वैश्वीकरण के समय में सिलीगुड़ी
समीर कुमार दास

2. कोसी से दिल्ली: प्रवासियों के जीवन और श्रम
पुष्पेंद्र और मनीष झा

प्रस्तावना

पिछले दो वर्षों में, कलकत्ता रिसर्च ग्रुप (सी.आर.जी) शहरी गरीबों की, शहरीकरण की उपस्थिति की गतिशीलता और सामाजिक न्याय के संबंधित मुद्दों और हिंसा से संरक्षण के रूप में ग्रामीण प्रवासियों की शर्तों पर शोध कर रही है। परियोजना का शीर्षक हैं 'शहरी, ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों: हिंसा और सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं' मुख्यतः, यह अध्ययन दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, सिलीगुड़ी में एक छोटे से शहर में प्रवास के अनुभवों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कोसी क्षेत्र, भारतीय महानगरों में प्रवास के सबसे उद्धृत स्रोतों में से एक है। यह शोध संक्षिप्त इन अध्ययनों के एक स्निपेट दृश्य प्रदान करता है जिसमें भारतीय शहरों में श्रमिक प्रवास के संबंध में विभिन्न शहरी नीतियों और नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

संक्षेप में चार वर्गों में विभाजित किया गया है: पहले तीन क्रमशः कोलकाता, दिल्ली और मुंबई पर लघु निबंध शामिल हैं दूसरी तरफ, चौथे भाग में प्रवासन की सीमाओं के निर्माण पर दो निबंध शामिल होंगे, अर्थात् छोटे शहर और प्रवासी मजदूरों का एक बाढ़ग्रस्त स्रोत। बड़े शहरों पर निबंध शहरी नीति, शासन, श्रम के रूपों, प्रवासन, शहरी किराया, और नवउदारवाद के बीच अंतर-लिंक पर ध्यान देंगे, क्योंकि भारत में शहरीकरण की राजनीतिक विचारधारा है। निष्कर्षण और संचय की सीमाओं के विवरण के साथ चौथे खंड में, स्थानिक और गैर-स्थानिक विचार (विभाजन और बाढ़ जैसी राजनीतिक और पर्यावरणीय आपदाओं सहित) की गतिशीलता का पता लगाया जाएगा कि दोनों सूत्रों और प्रवासन स्थलों को बनाने और बनाने में मदद मिलती है।

परियोजना की अवधारणा और बाद में अनुसंधान संक्षिप्त जानकारी के अनुसार, भारत की कहानी सीमलेस हाइपर-शहरीकरण में से एक नहीं है, हालांकि संसाधनों के संदर्भ में शहरीकरण का प्रभाव और रोजगार के अवसरों में जानकार वृद्धि (विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों) आधिकारिक आंकड़े बताते हैं की तुलना में कहीं ज्यादा है। शहर की दो छवियों के बीच आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और इसके निवासियों के बीच बातचीत के लिए एक अपर्याप्त नागरिक स्थान के बीच एक गहरे बैठा विरोधाभास भी है। आजकल विरोधाभास बहुत अधिक है क्योंकि 1990 के दशक में नव-उदार सुधारों के फैलने के बाद भारतीय शहरों को निरंतर विखंडन और सभ्यता के रूप में दिखना शुरू हो गया है।

इस प्रकार के शोध संक्षिप्त रूप से पेश करने का प्रस्ताव है तीन उद्देश्यों: पहला मुद्दा यह है कि प्रवासी को नव-उदारवादी समय में शहर के केंद्र में बैठता है; एक अनंतिम सैद्धांतिक रूपरेखा का सुझाव देने के लिए दूसरा, जो कि प्रवासी मजदूर के आंकड़े को शहर के परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में एक किराये के आउटलेट में समायोजित कर सकते हैं, साथ ही साथ निष्कर्षण की जगह भी। तीसरे उद्देश्य पर जोर देना है कि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या विचार करते हैं - समकालीन समय में शहरी विकास पर आधिकारिक और अन्य दोनों प्रवचनों में प्रवासी की अदृश्यता। जैसा कि एक नोटिस होता है, अधिकांश निबंधों ने कड़वा सच्चाई को उजागर किया है कि प्रवासी की आकृति, शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी, उनके बस्तियों, जीवन और काम की स्थिति आदि सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतियों में स्पष्ट रूप से उपेक्षित हैं। पिछले कुछ वर्ष। इतना ही नहीं, शहर के एक स्वच्छ, समृद्ध, सौहार्दपूर्ण दृष्टि बनाए रखने के लिए इन मुद्दों को दूर करने का एक सतत प्रयास किया गया है। एक यह तर्क दे सकता है कि यह रवैया श्रम और शहरी अंतरिक्ष के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, नव-उदार शहर के उद्भव में मौलिक समस्याग्रस्त है। यह आधुनिक शहर की आबादी को औद्योगिक उत्पादन की एक साइट के रूप में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के एक स्थल के रूप में दर्शाता है, जो मानव-पूंजी के स्थानीयकृत सांद्रता के अलावा ज्ञान-आधारित समर्थन के लिए जगह-आधारित सेवाओं का एक जटिल स्थान है। अर्थव्यवस्था।

शहरीकरण के सिद्धांतकारों (हेनरी लेफ्ब्वेरे, डेविड हार्वे और सस्किया सासेन, सबसे प्रभावशाली नाम रखने के लिए) मुख्य रूप से अंतरिक्ष निर्माण और वास्तुशिल्प नियोजन के विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राज्य की नीतियों और शहरीकरण के कार्यक्रमों की विशेषता और समर्थन करते हैं, शायद ही इन स्थानिक कार्य

का उत्पादन पक्ष दूसरी तरफ, नए और उभरते श्रमिकों (इस क्षेत्र में नवीनतम हस्तक्षेप में से एक के रूप में कल्याण सान्याल के पुनर्निर्माण पूंजीवादी विकास) पर अध्ययन अक्सर इन जगहों के कार्य को प्रभावित करते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं के द्विआधारी में पकड़े जाते हैं , पूंजी के बाहर एक 'शुद्ध' की कल्पना की ओर अग्रसर है यहां तक कि इन अध्ययनों का सबसे अधिक प्रजनन शहर में परिजनों, नीतियों के हस्तक्षेप और श्रम के अनौपचारिकता के बीच संबंधों को देखने में विफल रहे हैं। स्थानिक और श्रम प्रजनन की भौतिक स्थितियों को अग्रसारित करके और बुढ़ापे, किराए, मजदूरी के रूप और विशिष्टता जैसे विशिष्ट मुद्दों के साथ अपने कनेक्शन पर प्रकाश डालने से, इस शोध के संक्षिप्त अध्ययन में यह पता चलता है कि प्रवास की घटना इन सामग्रियों के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और समकालीन शहरीकरण के उदाहरणों में एक मौलिक ऑपरेटिव सिद्धांत के रूप में उभर आता है। जैसा कि यह खड़ा है, श्रम शक्ति का आंदोलन नव-उदार नीति के हस्तक्षेपों के आंकड़ों के साथ अलगाव में अध्ययन नहीं किया जा सकता; और, साथ ही, अंतरिक्ष निर्माण की प्रतिनिधित्वशील गतिशीलता को शहरी और अर्ध-शहरी बुनियादी ढांचे के उत्पादन और संचलन के भौतिक स्थितियों से जुड़ा होना चाहिए।

कोलकाता का पहला खंड (जिसे कलकत्ता कहा जाता है) में पांच अध्ययन शामिल हैं। कौस्तुभ मनी सेनगुप्ता द्वारा पहला अध्ययन, ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद और 1947 में भारत की आजादी के प्रारंभिक दौर में कलकत्ता के शहर के विकास के पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के पुनर्वास के इतिहास को जोड़ता है। अध्ययन के दौरान, वह सरकार की पुनर्वास योजनाओं का मूल्यांकन करती है जिस तरह से शरणार्थियों को उनकी पृष्ठभूमि और पिछली व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया गया था और इस तरह के अभ्यास का क्या परिणाम था। इमन मित्रा का दूसरा अध्ययन शहरीकरण की घटना और समकालीन कोलकाता में ग्रामीण-से-शहरी उत्प्रवास की बात पर केंद्रित है और शहरीकरण के व्यापक और निकटवर्ती प्रवचनों में 'प्रवासी मजदूर' की श्रेणी की जांच करता है। मित्रा दर्शाता है कि 'प्रवासी' की श्रेणी में शहरी नियोजन और नीति बनाने के स्तर पर विभिन्न विचार-विमर्श के माध्यम से, विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में बस्तियां (झुग्गी बस्तियों) के संबंध में कानूनों और नीतियों के संदर्भ में उत्पादन किया जाता है। । तीसरे अध्ययन - फिर से मित्रा - कलक प्रबंधन के क्षेत्र में श्रमिकों के जीवन का पता लगाने और कोलकाता के निर्माण उद्योग का प्रयास करता है। नव-उदारवाद और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के संयोजन के दौरान अपने अध्ययन का पता लगाते हुए, मित्रा यह दर्शाता है कि इन दोनों क्षेत्रों में कार्यकर्ता जगह के किराये की अर्थव्यवस्था के उत्पादन में योगदान करते हैं । देबारती बागची और साबिर अहमद के चौथे अध्ययन क्रमशः दो प्रवासी समुदायों को ध्यान में रखते हैं - कोलकाता में महिलाओं के कचरा लेने वालों और रेलवे प्लेटफार्मों पर रहने वाले प्रवासी बच्चों का ध्यान। दोनों अध्ययन, हालांकि विभिन्न नृवंशविज्ञान स्थलों पर आधारित हैं और अध्ययन के विभिन्न विषयों से निपटने से शहरी नीतियों के संदर्भ में आवास या निपटान के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, बगची बताती हैं कि कचरा उठा लेने की जड़ें वाले प्रश्नों को आवास की स्थानिकता के साथ संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अक्सर हमारी समझ से पहले की समझ में शामिल है कि कचरा बीमारियों को प्रवासियों के लिए होना चाहिए क्योंकि वे शहर की औपचारिक व्यवस्था में शामिल नहीं हैं, अहमद अध्ययन से पता चलता है कि रेलगाड़ी बच्चों की 'बचपन' को कॉस्मेटिक नीति की सिफारिशों से नहीं बदला जा सकता है, बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने और बाकी सभी समाजों से उन्हें जोड़ने का एक निरंतर तरीका शुरू कर दिया जा सकता है। माधुरीलता बासु द्वारा इस खंड में पांचवां अध्ययन समकालीन पूंजीवाद के तहत श्रम के एक गिनेदार डोमेन की जांच करता है, अर्थात, देखभाल, कोलकाता में अयाहों और नर्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है - उनकी नौकरी की प्रकृति और गतिशीलता के पैटर्न - क्षेत्र के आधार पर - कोलकाता में और आसपास स्थितियां उनके शोध के अनुसार, प्रवासी नर्स कोलकाता को दूसरे 'अधिक विकसित' क्षेत्रों और शहरों और अया के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में देखते हैं जो पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से प्रवास करते हैं । दिल्ली के दूसरे खंड में तीन अध्ययन हैं अमित प्रकाश का पहला अध्ययन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के शासन के लिए मौजूदा नीति और कानूनी ढांचे के पीछे वैचारिक परिसर की जांच करता है। शहरी नियोजन और विकास के विघटनकारी आधिपत्य, जो कि दिल्ली के प्रशासन के ढांचे को बताता है, वह तकनीकी, नौकरशाही नियंत्रण, केंद्रीकरण और विश्व स्तरीय सुंदर शहर की बुर्जुआ की आकांक्षाओं से प्रेरित है। इस

विचारधारात्मक फ्रेम में, सामाजिक न्याय के मुद्दे गरीब और हाशिए वाले लोगों के अदृश्य होने के एक विशिष्ट प्रयासों के कारण पिछली सीट लेते हैं। इशिता डे द्वारा दूसरे अध्ययन में तीन जगहों पर कई आंतरायिक चरणों में अपने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर दिल्ली के एक सेवा गांव में प्रवासियों के एक मानवविज्ञान का विवरण प्रदान किया गया है: गुड़गांव, नई दिल्ली में गौतमपुर पुनर्वसन कॉलोनी और फरीदाबाद में एक डेरा। डे का तर्क है कि इन साइटों में होने वाली कथाओं को समझने में उनकी सहायता करती है कि महिलाओं को एक महिला कम्गर, घरेलू कंमगर (घरेलू कार्यकर्ता) के लिए इसका मतलब है और सरकार से किसी भी सहायता की अनुपस्थिति में उनके जीवन के जीवन में अन्य कामकाजी परिस्थितियों के अनुकूल होने का भी मतलब है। काम की अधिक सुरक्षित स्थितियां और आजीविका के साधन हैं मिथिलेश कुमार के तीसरे अध्ययन में पहले विचारकों और शिक्षाविदों के लेखन में 'आदिम संचय' की अवधारणा पर चर्चा की गई है और भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और बसने और श्रमिकों की पहचान के स्थानांतरण की हिंसक प्रक्रियाओं के दिल में एक ही अवधारणा के बारे में उनकी समझ को प्रस्तुत करता है। दिल्ली के हवाई अड्डा शहर के नजदीक और आस-पास कार्यबल की संरचना में विस्थापन और परिवर्तन के बीच संबंध बनाकर, कुमार बताते हैं कि हवाईअड्डा अर्थव्यवस्था के निजीकरण के शासनकाल के तहत प्रवासी श्रमिक समय की अवधि में मजदूर बन जाते हैं।

मुंबई के तीसरे खंड में चार अध्ययन शामिल हैं। मनीष झा और पुष्पेंद्र का पहला अध्ययन, मुंबई के नव-उदारवादी विचारों की वैश्विक प्रक्रियाओं की बड़ी प्रक्रियाओं में प्रवासियों के बेघर लोगों के अनुभवों का पता लगाने के साथ-साथ शहर में प्रवासियों की बेघरता के अनुभवों की जांच करता है श्रम के अनौपचारिकरण, और विस्थापन और अपर्याप्त पुनर्वास, जिसके परिणामस्वरूप किफायती आवास, सेवाओं, कार्यस्थल और सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबंधित पहुंच होती है। यह बेघर प्रवासियों के रोजमर्रा की मुठभेड़ को उकसाए, अपमान और असुरक्षा के अनुभवों के माध्यम से संरचनात्मक हिंसा से उजागर करता है: आवास दावों की अवैधता, अनौपचारिकता और कार्य की शुद्धता, आश्रय, शोषण और राज्य एजेंसियों द्वारा दमन और अन्य अन्य परतों पर अपमान बेघर अनुभव ने संरचनात्मक और प्रणालीगत उपकरण और हिंसा के संचालन को दर्शाया है और यह दर्शाता है कि कैसे बेघर प्रवासियों पर संरचनात्मक हिंसा के इन उदाहरणों को सामान्य, प्राकृतिक और यहां तक कि वांछनीय माना जाता है।

सिंप्रीत सिंह का दूसरा अध्ययन, आधिकारिक प्रवचन और आम भाषा में मुम्बई में प्रवासियों के स्पष्ट आंकड़े के निर्माण पर केंद्रित है। उनका अध्ययन 'प्रवासी' के समकालीन मुंबई में एक समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में उभरने की गति को देखने का प्रयास करता है जिसमें अभिनेता, सेनाओं और इसके पीछे के कारणों का अध्ययन किया जाता है और शहर की आर्थिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की खोज की जा रही है। एक सर्विस सेंटर में विनिर्माण केंद्र मोलेश्री व्यास के तीसरे अध्ययन ने यह पाया कि कैसे मुंबई में प्रवासी-विरोधी राजनीतिक माहौल एक भ्रमित सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक माहौल पैदा कर रहा है जहां प्रवासी मजदूरों के निर्माण और सेवा के प्रावधान, और काम करने में सक्षम होने के लिए अनिवार्य है, शहर में शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थान पर कब्जा कर रहे हैं। उनके अध्ययन ने इस विरोधाभास को दो घटनाओं के बारे में प्रवासी मजदूरों के अध्ययन के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया - दो अलग-अलग व्यवसायों में अनौपचारिक कार्यबल में बुजुर्गों के रोजगार, अर्थात संरक्षण कार्य और सुरक्षा उद्योग। महुआ बांदोपाध्याय और रितम्हारा हेब्बर का चौथा अध्ययन उन प्रवासियों के जीवन की खोज करता है जो सुरक्षा गार्ड या संरक्षक के रूप में काम करते हैं, जो कि उनके खिलाफ हिंसा की राजनीति के लिए जाना जाता है। इन पहलुओं के माध्यम से शहर में सुरक्षा और कामकाज के अनुभव को तलाशने में शोधकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों की शुद्धता की रैखिक और वर्णनात्मक समझ से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जो अक्सर 'प्रवासी' वर्ग के लिए निर्दिष्ट निर्धारण और सुरक्षा की सरल समझ हिंसा के जटिल और विवादास्पद मुद्दे को शामिल करता है जो कि प्रवासियों द्वारा स्वयं को प्रेरित करता है और तर्क देता है कि यह कुछ संरचनात्मक हिंसा का एक टकराव वाला पहलू दर्शाता है जो सुरक्षा गार्ड के रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। इस पहलू में, शोधकर्ताओं ने बताया कि मीडिया में हिंसा के कृत्य के प्रभावों को नाटकीय रूप से लागू करने और बढ़ाने के लिए मीडिया और संबद्ध प्रवचनों में अक्सर नजर डाले जाते हैं।

चौथे और अंतिम खंड में दो अध्ययन हैं, पुष्पेंद्र और मनीष झा के पहले अध्ययन ने उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ढांचे और पदानुक्रम के बारे में बताया और प्रवास के घटनाक्रम के साथ उनके संबंध। प्रवासियों के गंतव्य पर भी प्रवासियों के जीवन को देखते हुए, यह उठता है और कोसी के बाढ़ के तबाह क्षेत्र से प्रवासन की प्रकृति के कुछ उचित सवालों के जवाब देने का प्रयास करता है, तात्कालिक चिंताओं से कि प्रवास प्रभावित होता है, निर्भरता का स्तर श्रम ठेकेदार पर (स्थानीय तौर पर मेथ के रूप में जाना जाता है), विचार जो एक विशेष स्थान या व्यवसाय की पसंद का निर्धारण करते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जाति और अन्य सामाजिक संबंधों की भूमिका। समीर कुमार दास के दूसरे अध्ययन ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक छोटे से शहर सिलीगुड़ी के संक्रमण का नक्शा दिखाया है, जो कि प्रवासियों के निवास स्थान से शहर तक की पहचान में बदलाव का अध्ययन करके राज्य में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पारगमन में, 'आसपास के चाय बागानों और पड़ोसी इलाकों को उच्च उगने के निर्माण के लिए गब्बलिंग करना, चाय मजदूरी में बड़े पैमाने पर अपदस्थ करना, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाना । इस तरीके से, शहरी-से-ग्रामीण प्रवास शीलुगुड़ी के शहरीकरण की विशिष्ट विशेषताओं में से एक बन गया है, जो नई श्रेणी के श्रमिकों को जन्म देते हैं जो गेट वाले परिसरों में आते हैं और निवास करते हैं और देखभाल के लिए अनौपचारिक श्रम की मांग, घरेलू कार्य, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, बिजली के काम और नलसाजी जैसी सेवाओं आदि सहित अपशिष्ट निपटान ।

इन सभी अध्ययनों ने समकालीन समय के शहरी नीति के प्रवचनों में प्रवासियों के आंकड़े की केंद्रीयता की एक विस्तृत और अधिक सूक्ष्म समझ को एक साथ उठाया। वे प्रवासियों की पहचान के निर्माण के आधार-स्तर की प्रथाओं का अध्ययन करने और नगरीय हिंसा से संबंधों का अध्ययन करने का एक नया तरीका भी पेश करते हैं जो शहर में प्रवासी श्रमिकों के संख्यात्मक महत्व या अप्रासंगिकता से पीड़ित नीति निर्माताओं द्वारा अपनी लापरवाही में योगदान देता है। यहां तक कि शहरीकरण पर मौजूद मौजूदा साहित्य जनगणना के आंकड़ों के मैक्रोवेवल विश्लेषण को शामिल करके और प्रवासन की बढ़ती या गिरती दर पर टिप्पणी करते हुए इस मुद्दे का भंडार नहीं ले पाई है। जैसा कि हमने अपने शोध के दौरान देखा है, वहां इन आंकड़ों और शहरी संस्कृति और सुरक्षा और हिंसा की प्रथाओं को बनाने और बनाने में एक संरचनात्मक संबंध मौजूद है। एक स्थूल दृष्टिकोण के साथ समस्या भी पहचान और हितों की बहुलता से पूछताछ करने में अक्षम है, जो कि प्रवासी मजदूरों की श्रेणी के गठन में योगदान करती हैं। हिंसा के दो रूप यहां काम पर हैं: एक ही चूक की हिंसा है जो सामाजिक न्याय की वास्तविक अनिवार्यता को भेदभाव के कृत्यों को अनदेखा कर देता है; और दूसरी श्रेणीगत हिंसा है जो शोषणकारी और निष्कर्षकारी तंत्रों की गठजोड़ के माध्यम से उत्पादित समरूपता के मौजूदा कथानकों को चुनौती देने पर विफल है। इस दृष्टिकोण के साथ विरोधाभासी में, यह शोध संक्षेप में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मार्करों जैसे लिंग, जाति, वर्ग, उम्र, मूल स्थान, भाषा आदि आदि के मामले में प्रवासी मजदूरों की एकवचनी श्रेणी को बिखराने की कोशिश करता है। शहरीकरण के उत्पादन और समकालीन भारत में श्रम के अनौपचारिकता के बीच संरचनात्मक संबंध। विभिन्न मुद्दों और संदर्भों को कवर करने के बावजूद इस शोध के अध्ययन में एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ में, हम आशा करते हैं कि वे प्रवासन और शहरी नीति के बीच के संबंधों पर एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करेंगे और भारत में श्रम और शहरीकरण पर मौजूदा नीतियों के साथ गंभीर रूप से संलग्न होने के लिए आवश्यक एक अद्वितीय अनुसंधान एजेंडे को चित्रित करेंगे।

अनुसंधान संक्षेप
धारा 1: कोलकाता

शहर में शरण लेना: पोस्ट-भाग कलकत्ता में प्रवासित जनसंख्या और शहरी प्रबंधन
-कौस्तुभ मनी सेनगुप्ता

यह अध्ययन ब्रिटिश भारत के विभाजन के शुरुआती दशकों में पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों के पुनर्वास और कलकत्ता के शहर के विकास के दशकों के इतिहास को ढंकने की कोशिश करता है। शरणार्थी पूरे पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में फैले हुए हैं। लेकिन एक बड़ा एकाग्रता कोलकाता क्षेत्र में था, जहां कई 'कॉलोनियों' आया। पूर्वी बंगाल के शुरुआती शरणार्थियों में से अधिकांश ऊपरी या मध्यम जाति समूह के थे। वे शहरी केंद्रों की ओर बढ़ रहे थे, खासकर कलकत्ता के लिए। शहर की आबादी में भारी वृद्धि ने शहरी बुनियादी ढांचे पर अपना टोल लिया। 1940 के दशक और 1950 के दशक के दौरान शहर में तीव्र भोजन संकट, औद्योगिक गड़बड़ी, काले बाजार की गतिविधियों और राजनीतिक आंदोलन थे। असंतोष के इस कड़ाही में, शरणार्थियों को बचाना पड़ा।
सरकार ने पलायन के पैमाने पर पहले से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन 1950 तक स्थिति की महत्ता का एहसास हुआ और राहत की अब तक की नीति को पुनर्वास के व्यापक कार्यक्रम में स्थानांतरित किया जाना पड़ा। एक तरफ, यह जनसंख्या का भारी बोझ के रूप में देखा, परन्तु दूसरी तरफ , इस असुविधाजनक गुच्छा की नैतिक जिम्मेदारी को वास्तव में नहीं हिला सकता था। यह विस्थापित व्यक्ति के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करने वाले दो ध्रुवों के बीच पकड़ा गया था- जिसके लिए धन और जमीन की आवश्यकता थी- और इसके गहन पांच-वर्षीय योजना के साथ राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम की। 1950 के बाद पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों की कक्षा और जाति की रचना को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया। शिविर-निर्वासित शरणार्थियों, जो सरकारी डोल पर निर्भर थे, इन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्य थे। पुनर्वास योजना का एक आधारशिला उनके पिछले व्यवसायों के मामले में शरणार्थी आबादी को वर्गीकृत करना था। इस प्रकार, कृषिविदों को भूमि में बसाना था, यदि पश्चिम बंगाल में उपलब्ध नहीं तो अन्य राज्यों में भी। इस फैलाव की नीति को जन्म दिया लोगों को अन्य राज्यों या अंडमान द्वीप समूह में भेजा गया पश्चिम बंगाल में, विभिन्न कृषि कालोनियों की स्थापना की गई थी। पुनर्वास रिपोर्ट और विभिन्न सरकारी पत्रिकाओं ने इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों को समाज में श्रमिक योगदानकर्ता होना चाहिए।

लेकिन सरकार के ये प्रयास पूरी शरणार्थी आबादी को संबोधित नहीं कर सके। शहर में, दो प्रकार के शरणार्थी समूह थे। सबसे पहले, प्रारंभिक प्रवासियों में ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवारों ने शरणार्थी कॉलोनियों की स्थापना की थी, जबकि दूसरे समूह में दलितों के दौरान भागने वाले दलित लोगों की संख्या शामिल थी और सियालदह स्टेशन पर या शहर में विभिन्न बस्तियों में आश्रय लिया था। सरकार के लिए इस बाद के समूह का पुनर्वास मुख्य चिंता का विषय था। उन्हें शहर के बाहर विभिन्न शिविरों में भेजा गया। लेकिन बहुत से निराश हालत के कारण शिविरों को छोड़ दिया गया और शहर में वापस अपना रास्ता मिल गया। प्रवासियों के एक बड़े हिस्से ने शहर में छोटी नौकरियां लीं। उपलब्ध जनशक्ति में अचानक वृद्धि के साथ, शहर में परिवार को बनाए रखने के लिए वास्तविक आय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं था।

सरकार की नीतियों ने पुनर्वास और विकास के दो मुद्दों को विलय के महत्व पर जोर दिया। यह आवश्यक था क्योंकि शरणार्थियों और राज्य के पूर्वी निवासियों के बीच संघर्ष जल्दबाजी था। शरणार्थियों के पुनर्वास का अध्ययन अक्सर राज्य के निवासी आबादी के गरीब वर्ग की स्थिति को उजागर करने के लिए याद किया जाता है। यदि हम राज्य की मुस्लिम आबादी की स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो मामले अधिक जटिल हो जाते हैं। ग्रामीण-शहरी, निवासी-शरणार्थी एकीकरण के लिए तर्क दिया जा सकता है और एक व्यापक योजना में डाल दिया जा सकता है। लेकिन इन तकनीकी उपायों ने अक्सर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान को ध्यान में नहीं रखा

है। अक्सर संघर्ष शरणार्थी और निवासियों के बीच नहीं था, लेकिन हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम निवासियों के बीच। पेपर के अगले भाग में इस समस्या का समाधान होता है। यह हमें प्रवासियों और निवासी गरीबों के बीच के संबंध की झलक दिखाएगा; यह हिंसा और सामाजिक न्याय के विचारों के बीच संघर्ष को रोशन करेगा। विभाजन के तर्क ने भारत में मुसलमानों की स्थिति बनायी। मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे हैं और फिर पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं इस क्षेत्र की एक आवर्ती विशेषता बन गई है। इन वर्षों में मुस्लिम आबादी और शरणार्थियों के बीच तनाव काफी स्पष्ट थे। विभाजन और शरणार्थियों की आबादी के साथ, मुस्लिम आबादी, विशेष रूप से गरीब खंड, जो कि उनके जीवन और जीविका को बनाए रखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अधिकांश लोग इस बदलाव की स्थिति को नहीं खपत कर सकते थे, और अपने वंशानुगत व्यापारों में परिवर्तन और उनके साथ जुड़े स्थिति के साथ उनके व्यवसाय में तेज बदलाव आया था। कुछ लोगों ने स्वयं के लिए शिक्षा पाने और नौकरी पाने के लिए प्रबंध किए जाने की कोशिश की। लेकिन ऐसी स्थिति में बचाना आसान नहीं था और 1947 की छाया उनके जीवन में बड़ी हुई थी।

भूमि विधेयक, 1951 के अनधिकृत व्यवसाय में व्यक्तियों के निर्वासन की शुरूआत के दौरान शरणार्थियों और मुसलमानों के बीच संघर्ष में भारी राहत मिली। 1950 में कलकत्ता के दंगों ने शहर के सामाजिक आकृति विज्ञान में बड़े बदलाव देखा। मुस्लिम आबादी के बड़े वर्गों को छोड़ दिया गया या उन्हें अपने घर छोड़ना पड़ा और 'मुस्लिम' क्षेत्रों में शरण ली जाहिरा तौर पर, नया विधेयक उन जमींदारों की संपत्ति को पुनर्स्थापित करना था जिन्हें अवैध रूप से 'शरणार्थियों' के रूप में पेश करने वाले व्यक्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। विधेयक का दूसरा उद्देश्य उन शरणार्थियों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करना था जिन्होंने रिक्त या अप्रतिबंधित रिक्त स्थान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विधेयक को कभी भी सशक्त शरणार्थियों को उखाड़ने का इरादा नहीं था; बल्कि उन बेईमान व्यक्तियों को बेदखल करना था जिन्होंने प्रांत की अराजक स्थिति का फायदा उठाया और अवैध रूप से खाली भूमि या घरों पर कब्जा कर लिया जिससे मालिकों को उनके दावे दावों को नकार दिया गया। विधानसभा में कम्युनिस्ट नेताओं ने विधेयक के प्रावधानों में शरणार्थियों के खिलाफ सरकार की भयावह योजना देखी। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य असाधारण शरणार्थियों के खर्च में बड़े भू-हितधारकों और पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करना है। हालांकि, समय की राजनीति इस विधेयक के धार्मिक कोण पर वर्ग युद्ध का घूंघट नहीं डाल सकती थी। अगर, जैसा कि कम्युनिस्ट मांग रहे थे, कोई वास्तविक शरणार्थियों को हटाया जाना नहीं था, और जैसा कि सरकार कुछ मामलों में भी इसी बात को गड़बड़ कर रही थी, जनसंख्या के कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया जाना था। विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों ने संपत्ति, विस्थापन और नागरिकता के अधिकार के बारे में नए सवाल उठाए। हिंदू शरणार्थियों ने दंगों और उत्पीड़न के भय के कारण मुस्लिमों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन और घर छोड़ दिए। मुसलमानों के स्वामित्व वाले संपत्तियों के मुताबिक संपत्ति के स्वामित्व वाले नागरिकों का क्या होगा, उन्होंने मुस्लिम सदस्यों से पूछताछ की। मुस्लिम किरायेदारों का क्या होगा? उनके पास कोई भूमि या घर नहीं था ये शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गरीब मुस्लिम थे। सांप्रदायिक दंगों और बहुसंख्यक समुदायों के सामान्य डराने ने उन्हें अपने घरों को बेदख़ल करने और पार्क सर्कस, मेटियाब्रुज़, राजा बाजार जैसे कुछ इलाकों में पार्क या होव्ल्स में शरण लेने के लिए मजबूर किया। कलकत्ता के बाद के विभाजन को अपने सामाजिक संरचना के संदर्भ में काफी बदल दिया गया। शरणार्थियों की आड़ अधिक दिखाई दे रही तस्वीर है। हम मुसलमानों की आबादी के स्थिर हाशिए पर निर्भर रहना भूल जाते हैं।

मुस्लिम आबादी की तरह, इन वर्षों के दौरान शरणार्थी परिवारों की महिलाओं को भी बदली हुई स्थिति का सामना करना पड़ा। शिविर और कॉलोनी जीवन कैदियों पर कठोर थे। यह पुरुषों के साथ ही महिलाओं को 'बाहर आना' और एक नौकरी की तलाश में धकेल दिया। कालोनियों में, कई महिलाएं नव-स्थापित स्थानीय कॉलोनी स्कूलों में सिखाना शुरू कर चुकी हैं। शिक्षक होने के अलावा, महिलाओं ने व्यावसायिक कार्यालयों से विभिन्न प्रकार के पेशेवर रिक्त स्थान में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। शिविरों में महिलाओं के लिए, स्थिति अलग थी उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने और फिर नौकरी पाने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर होना था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि शिविरों के कैदियों को वर्गीकृत और पुनर्गठित किया गया था ।

शरणार्थी महिलाओं के वर्ग के चरित्र ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमता निर्धारित की। साथ ही, विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के प्रस्ताव और शिक्षा के विषय में जिन विषयों की सूची प्रकट होती है, उन्हें पता चलता है कि जब भी विभाजन के दौरान सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था के कारण महिलाओं को अर्जित करने के लिए मजबूर किया जाता था, तब भी उन्हें 'प्रभावी' यौन विभाजन का पालन करना पड़ा समाज में प्रचलित श्रमिकों की यह मुक्ति की कथा के सशक्त उत्सव को जटिल बनाती है और हमें सूक्ष्म तरीके से देखने के लिए उकसाता है जिसके माध्यम से प्रमुख सामाजिक मानदंडों को जारी रखा गया है। लेकिन एक यह जोड़ सकता है कि जब उनकी उपस्थिति शहर के सार्वजनिक जीवन, कार्यालयों, सड़कों पर, भीड़ वाली बसों और ट्राम में, राजनीतिक रैलियों में, उनकी भागीदारी की शर्तों को भी बदलना शुरू हो गया है । भीड़ भरे सड़कों पर कूच करने वाले मध्यवर्गीय शरणार्थी महिला का आंकड़ा सहानुभूति के स्वर को प्रशस्त करता है; लेकिन शायद यह भी सामाजिक न्याय की सम्मानजनक शर्तों को सुनिश्चित किया।

विभाजन के बाद कलकत्ता तेजी से बदल गया। 1940 के दशक के दौरान कलकत्ता पहले ही युद्ध, अकाल और दंगों के साथ कष्टप्रद वर्षों से गुजर रहा था। शहर की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हुई । आजादी के प्रारंभिक वर्षों में हैजा के गंभीर झुकाव से चिह्नित किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मामलों की एक दयनीय स्थिति में थी। सियालदह स्टेशन, जहां शरणार्थियों ने किसी भी अन्य विकल्प की कमी में आश्रय लिया था, को 'पृथ्वी पर एक वास्तविक नरक' के रूप में वर्णित किया गया था 1943 में अकाल का चित्र बार-बार अखबारों में लागू किया गया था। उस स्थिति से बचने के लिए कुछ किया जाना आवश्यक था। शहर में शरणार्थी कॉलोनियों और शिविरों के साथ नई संरचनाएं आईं। मुसलमानों के साथ शहर के कुछ इलाकों में धांधली के साथ धार्मिक घटे बनते थे। कलकत्ता निगम और कलकत्ता सुधार ट्रस्ट को इन वर्षों में शहरीकरण के कुछ दृश्य बहाल करने में एक कठिन काम था। शहर भी गहरी राजनीतिक प्रतियोगिता का थिएटर बन गया, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दलों, विशेष रूप से कम्युनिस्ट, जनता के ध्यान और समर्थन के लिए दांव लगाना था। साम्यवादियों ने आंदोलन की एक अलग तरह की राजनीति की शुरूआत की जिसमें राज्य के शहरी राजनीतिक परिवेश का आकार था। विद्वानों द्वारा कम्युनिस्टों और शरणार्थी आबादी के बीच गहरी कड़ी का पता लगाया गया है आजादी के पहले दो दशकों के दौरान शहर के आबादी के सामान्य आवास और घनत्व के मुद्दों पर चर्चा करते हुए हमें पता चलता है कि कलकत्ता की हालत पर कई लेखन, 1960-60 से कलकत्ता सुधार ट्रस्ट [सीआईटी] के अध्यक्ष सैबल कुमार गुप्ता ने बार-बार आवास, मलिन बस्तियों, और शहर में आबादी की सामान्य उच्च घनत्व के मुद्दों पर वार किया। इन सुविधाओं ने शहरी प्रबंधन प्रणाली में अत्यधिक कठिनाई खड़ी की। शहर के भीतर क्षेत्र में जमीन की कमी ने प्रशासकों को पड़ोसी जिलों में देखने के लिए मजबूर किया। कल्याणी जैसी नई बस्ती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई थी। ग्रीनबेल्ट या सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा स्वतंत्र भारत की नई नियोजन व्यवस्था का हिस्सा थी, चंडीगढ़ का मुख्य उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मॉडल कल्याणी या दुर्गापुर के साथ किया गया था। लेकिन उन्हें देरी और विलंब के विभिन्न उदाहरणों के साथ उनकी समस्याएं थीं। लेकिन प्रवासियों-न केवल पूर्व पाकिस्तान से, बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों से - शहर में आते रहे और शहरी केंद्र के करीब रहने के लिए संभव हो सके। इसने शहरी बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। साहिल गुप्ता वास्तव में शहर में मलिन बस्तियों के बड़े पैमाने पर प्रसार के साथ परेशान था। इन झाड़ियों में उचित स्वच्छता या पानी की आपूर्ति नहीं थी वे अक्सर सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अतिक्रमण करते थे किराया और पट्टे की जटिल व्यवस्था के साथ, मलिन बस्तियों की स्वामित्व पैटर्न और किराया-अर्थव्यवस्था को नष्ट करना असंभव था। शहर के प्रमुख क्षेत्रों से इन झोपड़ियों को बदलने के लिए समय-समय पर नई आवास योजनाएं तैयार की गईं। लेकिन यह एक सदी के समय में पूरी तरह से करना संभव नहीं समझा गया था। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के दौरान कलकत्ता में अधिकांश प्रकाशन ने इसे 'शहरी दुर्घटना' के रूप में नामित किया। शहर के क्षेत्र में बढ़ती आबादी, सीमित रोजगार के अवसर और उच्च घनत्व ने शहरी प्रबंधन प्रणाली पर दबाव डाला। अधिकारियों ने पूरे अवधि में हालत में सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से कोशिश की लेकिन समस्याएं बनी रही। और इन संरचनात्मक कठिनाइयों के साथ ही, शरणार्थी आबादी से

लगातार दबाव, मुस्लिमों के लिए जगह की बढ़ती संख्या के साथ गुप्त सांप्रदायिक तनाव और अप-देशवासियों की बढ़ती संख्या के साथ दबाव था। शहर में कानून और व्यवस्था की समस्या बढ़ी।

पुनर्वास नीतियों ने राष्ट्र की विकास व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़कर आबादी के भारी प्रवाह की समस्या को हल करने की कोशिश की। फैलाव योजना दो चिंताओं को मर्ज करने का एक प्रयास थी, जहां शरणार्थी के पुनर्वास किसी विशेष राज्य के लिए चिंता का विषय नहीं था, बल्कि पूरे देश। लेकिन विस्थापित आबादी का पुनर्वास एक ठंडे , तकनीकी तरीके से नहीं किया जा सकता था। हालांकि सरकार ने शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए कई उपाय किए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लागू किया गया था, वांछित होने के लिए बहुत ज्यादा छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल इस समय कई संकटों से गुजर रहा था। बड़े पैमाने पर काले बाजार की गतिविधियों के साथ एक तीव्र भोजन संकट था, जिसने अक्सर शहर में हिंसक झड़पों को जन्म दिया। जूट उद्योग की स्थिति अक्सर श्रमिक हमलों के साथ तनावपूर्ण थी। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार शरणार्थियों में वामपंथी दलों के बढ़ते प्रभाव से बहुत चिंतित थी। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने आधार को सुरक्षित रखने की जरूरत है इसका मतलब शरणार्थियों के साथ-साथ राज्य के पूर्व निवासियों की देखभाल करना था। शरणार्थियों के संकट की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए प्रारंभिक अनिच्छा ने केवल समस्या को बढ़ा दिया और असंतोषपूर्ण आवाजों को सरकार के खिलाफ एक साथ आने के लिए जगह दी। वर्षों से, विभिन्न समितियों की सिफारिशों के माध्यम से सरकार संशोधित नीतियों और योजनाओं के साथ आ गई। लेकिन प्रत्येक नए चरण के साथ आगे की चुनौतियों का सामना किया गया था ।

विस्तृत संदर्भ के साथ पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP72.pdf.

समकालीन कोलकाता में शहरी नियोजन, सेटलमेंट प्रैक्टिस, और न्याय के मुद्दे
-ईमन कुमार मित्रा

यह अध्ययन कोलकाता शहर में जीवन, आजीविका और आवास प्रथाओं के दो पहलुओं को एक साथ लाने का प्रयास करता है- शहरीकरण की घटना और ग्रामीण-से-शहरी प्रवास के मामले। इसी समय, यह इन दोनों प्रथाओं के संयोजन के क्षणों में सामाजिक न्याय के मुद्दे को अग्रभूमि करने का प्रयास करता है, उलझन में जुड़े विभिन्न नेटवर्कों में प्रचलित नेटवर्क और अलग-अलग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पदानुक्रमित व्यवस्थाओं द्वारा समर्थित, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण के व्यापक और निकटवर्ती प्रवचनों में 'प्रवासी मजदूर' की श्रेणी की जांच करना और अनुसंधान की एक योजना शुरू करने के लिए है जो इस स्थान को परिभाषित करने और स्थिर बनाने और उसके प्रभाव को पता लगाने की राजनीति का पता लगाएगा। शहरी गरीबों के लिए सामाजिक न्याय के क्षेत्र में न्याय का यह विशेष क्षेत्र तथाकथित 'बाहरी लोगों' पर हिंसा की घटनाओं से संबंधित है, स्वयं को 'मिट्टी के बेटों' द्वारा शहर में और बेहतर जीवन की तलाश में शहर आने वाले श्रमिकों की भेद्यता। और इन घटनाओं के चेहरे पर बेहतर रोजगार के अवसर। इसके अलावा, शारीरिक हिंसा के उदाहरणों के अलावा, अंदरूनी और बाहरी लोगों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक अलगाव के मुद्दे हैं, जो लंबे समय में पहचान के गठन और प्रामाणिक शहरी अनुभव के निर्माण की राजनीति के रूप में विभिन्न परेशान करने वाले प्रश्नों में शामिल होंगे। प्रवास और शहरीकरण प्रथाओं के संयोजन के क्षणों में भौतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक हिंसा के इन घटनाओं को व्यवस्थित करने और प्रासंगिक बनाने के लिए इस संबंध में महत्वपूर्ण है।

कोलकाता (पूर्व में, और आज भी कुछ क्वार्टरों में, कलकत्ता के रूप में जाना जाता है), वाणिज्यिक हितों और सांस्कृतिक आकांक्षाओं की एकाग्रता के संदर्भ में पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। कलकत्ता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और राज के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवास के लिए सर्वाधिक मांग वाले स्थानों में से एक बन गया था। स्वतंत्रता के बाद भी, यह अन्य राज्यों के लोगों को आकर्षित करने के लिए जारी रहा - खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे देश के पूर्वी भाग में - और सभी समुदायों, धर्मों और भाषा समूहों के सदस्यों के लिए आतिथ्य की पेशकश करते थे। कोलकाता की इस महानगरीय छवि को थोड़ी क्षति हुई जब कथित औपनिवेशिक रूप से 'कलकत्ता' से कथित तौर पर बंगाली भाषिक 'कोलकाता' को शहर के नाम बदलने के लिए मांग बढ़ी थी। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था की 'उदारीकरण' के बाद पिछले दो दशकों में इन संकीर्ण भावनाओं और शहरी नियोजन के प्रोटोकॉल और शहर के स्थानिक पुनर्निर्माण के बीच संबंध पर बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जैसे नवीनतम शहरी नवीकरण कार्यक्रमों का अनुमान लगाने वाली एक ऐतिहासिक नींव है।

कागज के पहले भाग में 1960 और 1970 के दशक में कलकत्ता में प्रवास और क्षेत्रीय प्रथाओं पर किए गए कुछ पूर्व अध्ययनों का उल्लेख है, जिसमें निर्मल कुमार बोस का कलकत्ता 1964: ए सोशल सर्वे (बॉम्बे: लालवानी पब्लिशिंग हाउस, 1968) शामिल हैं। 1911 से 1961 तक कलकत्ता निगम के आकलन रिकॉर्ड्स के आधार पर शहर के जटिल भूमि उपयोग के नक्शे तैयार करने के अलावा, बोस के अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि शहर के निवासियों द्वारा शहरी परिदृश्य कैसे साझा किया गया, भाषा समूहों और व्यवसायों का शहर की आबादी कई नगरपालिका वार्डों में फैली हुई थी और बोस का इरादा कुछ समुदायों - धार्मिक, जातीय, और अन्यथा - कुछ विशेष वार्डों की एकाग्रता का मानचित्रण करना था। उनके अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 1910 और 1920 के दशक की शुरुआत में, कलकत्ता का शहर स्थान विशेष क्षेत्रों में वितरित किया गया था जहां लोगों के विशिष्ट समूह रहते थे और उनकी आजीविका अर्जित की थी। भले ही 1960 के दशक में कलकत्ता के 'सामाजिक

स्थान' के बोस के सर्वेक्षण ने माइग्रेशन के सवाल को सीधे संबोधित नहीं किया, लेकिन 'नॉन-बंगाली' समुदायों के आवास प्रथाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया- जो उड़िया बोलने वाले थे नलसाजी, गैस, और इलेक्ट्रिकल कार्यों या हिंदी बोलने वाले मजदूर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए थे और औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रित थे - शहर में 'बाहरी लोगों की मानसिकता को समझने के लिए जिज्ञासा की भावना देता है।' अक्सर उन्हें हिंसा की घटनाओं के बाद उनके स्थान को बदलना स्क्रैप लोहा और मशीन भागों में काम करने वाले हिंदी बोलने वाले कलवारों ने वार्ड 53 में व्यापार किया - एक मुख्य रूप से मुस्लिम इलाके, जैसा कि अध्ययन में बताया गया - लेकिन 1946-47 में दंगों के बाद क्षेत्र छोड़ना पड़ा और 7, 10 वार्ड में बस गए , 13, आदि ।

इस ऐतिहासिक कथा से एक सुराग लेते हुए, मित्रा के पेपर ने पिछले कुछ दशकों में कोलकाता में निपटान के तरीकों से संबंधित कुछ मुद्दों की खोज की और यह दिखाया कि 'प्रवासी' की श्रेणी में शहरी नियोजन के स्तर पर विभिन्न विचार-विमर्श के माध्यम से और किस प्रकार उत्पादन किया जाता है और नीति बनाने कोलकाता में प्रवास के बारे में पहले के कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों से मुख्य शहर का विकास रोक दिया गया है, क्योंकि कलकत्ता में आबादी के कारण पिछले पचास वर्षों में गिरावट आई है। दूसरी ओर, गैर-बंगाली आबादी का आकार 1951 में 34.06% से बढ़कर 1971 में 40.08% रहा। कुल जनसंख्या में अन्य राज्यों के प्रवासियों का अनुपात 1951 में 25.24% से घटकर 17 से कम हो गया 1971 में%। 2011 की जनगणना में, कोलकाता जिले की दसवीं साल की विकास दर -1.88% दर्ज की गई - भारत में जनगणना के इतिहास में सभी समय का न्यूनतम - 2001 में जनसंख्या घनत्व 24718 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में 24258 प्रति वर्ग किलोमीटर के लिए। यह देश के सभी हिस्सों में अधिक से कम दृश्य है, जहां बड़े शहरों में आबादी बाहर से आ रही है, क्योंकि इन शहरों में रोजगार के अवसर पूंजी की गहन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण निराशा से कम दिखते हैं औद्योगिक क्षेत्र हालांकि नौकरी पाने की संभावना कम दिखती है, पश्चिम बंगाल के अन्य राज्यों और अन्य जिलों के सैकड़ों लोग रोज़गार और कुछ प्रकार के आवास की उम्मीद के साथ कोलकाता आते हैं। उनमें से ज्यादातर को विभिन्न नगरपालिका वार्डों में मलिन बस्तियों या बस्टीज़ में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

कोलकाता के निवासियों को स्थलांतरित समझौते के संभावित स्थल के रूप में चुनने का निर्णय कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (केएमडीए) द्वारा तैयार शहरी नियोजन के कुछ दस्तावेजों में एक दिलचस्प अभिविन्यास से प्रभावित होता है। कोलकाता की मलिन बस्तियों के नमूने सर्वेक्षणों के आधार पर अपनी विभिन्न रिपोर्टों में, केएमडीए ने प्रवासी श्रमिकों की आवास, उनके रहने की स्थिति और सामाजिक समायोजन, और ग्रामीण-शहरी संबंधों के आवास के मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है, जो उनके अपने स्थानों पर लगातार दौरा मूल रूप से, शहरी नियोजन और विकास के प्रश्नों के सिलसिले में। कलकत्ता के शहरी परिवारों के 'सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल' के 1996-97 के अध्ययन में पहली बार 'प्रवासियों' की एक पूर्ण परिभाषा प्रदान की गई थी। लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से म्यांमार से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए केएमडीए (पूर्व सीएमडीए, जब तक कि शहर का नाम बदल गया न हो) में दिखना शुरू हो गया। बस्टीज़ ने न केवल शहरी गरीबों को शरण प्रदान किया, उन्होंने उन्हें समान आधार के भीतर रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। शहरी विकास की योजनाएं 'कलकत्ता 300: फॉर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट' को अक्सर प्रवास और बस्टी सुधार के दोनों मुद्दों पर छुआ, लेकिन दोनों के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं बना। यह कलकत्ता के झुग्गी निवासियों की 'सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल' का 1989-90 का अध्ययन था, जिन्होंने प्रवासियों के रूप में उन्हें काफी संख्या में पहचान की थी। न केवल अध्ययन ने माइग्रेशन और बस्टी बस्तियों के बीच एक करीबी संबंध को पहचान लिया, इसने इन बस्तियों के निर्माण के प्राथमिक कारण के रूप में प्रवासन की भी पहचान की। 1980- 99 में कलकत्ता की झुग्गी बस्तियों के सर्वेक्षण में दिलचस्प बात ये थी कि: (1) इन बस्तियों में रहने वाले विशेष भाषा समूहों की प्रबलता के अनुसार झुग्गियों को वर्गीकृत किया जा सकता है (और शहर को ज़ोन किया जा सकता है) (2) प्रवासियों के अपने मूल भूमि के दौरे के माध्यम से स्थापित ग्रामीणों के संबंधों का मुद्दा ।

इस बीच, 1981 में, शहर की योजना और शहरी विकास के आधिकारिक प्रवचन में एक और दिलचस्प बदलाव हुआ था। यह साल था जिसमें कोलकाता थिका किरायेदारी (अधिग्रहण और विनियमन) अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में सभी बस्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया और मकान मालिकों द्वारा कथित शोषण से रहने वालों और थिका किरायेदारों को बचाने के लिए कुछ विनियामक तंत्रों का निर्धारण किया। शहरी भूमि छत (1976) के बारे में नई कार्यवृत्त का हवाला देते हुए, सरकार ने शहर के विभिन्न हिस्सों में बिखरे इन सभी भूखंडों को पकड़ लिया और वास्तविक मालिकों को मुआवजे के रूप में बहुत कम राशि का भुगतान किया। यह बस्टी बस्तियों के मामले में सबसे शक्तिशाली हितधारक बनने का आग्रह करता है कि राज्य द्वारा शहरी विकास के संबंध में अस्तित्व और शहर के झुग्गियों के सुधार के सवालों के मुताबिक राज्य को कितना महत्व दिया गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह शहरीकरण का एक अनूठा पहलू है- श्रम और भूमि के बीच संबंध। यह याद किया जाना चाहिए कि, ऐतिहासिक रूप से, कोलकाता की ज्यादातर झुग्गियों को उन जिलों या राज्यों से शहर में रहने वाले श्रमिकों को समायोजित करने के लिए बनाया गया था। इसलिए शहर में भूमि उपयोग के बदलते पैटर्न, शहरी क्षेत्र में उत्पादन के बदलते तरीकों का सह-गठन कर रहे हैं।

बाकी पेपर में, मित्रा शहरी जमीन के रीसाइक्लिंग के संदर्भ में कुछ बदलते रिश्ते की खोज करते हैं और समकालीन कोलकाता में शहरी नियोजन और पुनर्वास कार्यक्रमों में नव-उदारता के आगमन के बारे में है। अगर कोई आगे रीसाइक्लिंग की अवधारणा को तलाशना चाहता है, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि इसे संचय के दो सह-आकस्मिक तंत्रों द्वारा महसूस किया गया है - वितरण और पुनर्वास श्रम शक्ति की गतिशीलता को नियंत्रित करके पूंजी की गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही हिंसक और संरचित है। यह इस संदर्भ में है कि कोई व्यक्ति प्रवास और श्रम अनौपचारिकता के प्रश्नों पर वापस लौट सकता है। यह अनौपचारिकता शहरी निपटान और किराया के मुद्दों को उठाए बिना लगाई जा सकती है। शहरी अंतरिक्ष के रीसाइक्लिंग के दो पहलू हैं जो श्रम और भूमि के प्रश्नों को एक साथ लाते हैं: (1) प्रवासी मजदूरों के लिए 'अन्य' बस्ती की मौजूदगी और बढ़ते हुए; और (2) रीसाइक्लिंग के प्रभाव के रूप में शहरी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन। 1981 के थिका टेनेंसी अधिनियम ने गरीब-आय वाले शहरी निपटान प्रथाओं को 'औपचारिक रूप देने' का फैसला किया था। खुद को सार्वभौमिक मकान मालिक के रूप में पहचाने और किराए पर निकासी (दोनों घर और भूमि किराए) के एक वंशानुगत नेटवर्क की शुरुआत करके, सरकार ने 'कानूनी' बस्टी और 'अवैध' स्टेफ्टर कॉलोनियों के बीच अंतर करने में कामयाब रहे - स्थायी संरचनाओं के बीच जो आसानी से नहीं जा सकीं गैर-स्थायी बस्तियों जो हमेशा बेदखली के खतरे के अधीन थे यद्यपि शब्द 'बस्टी' का प्रयोग सार्वजनिक प्रवचनों में ढीले ढंग से किया जाता है, आधिकारिक दस्तावेजों में यह अधिनियम के तहत पंजीकृत निपटारे के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय और बिजली प्रदान की जाती है। इसके विपरीत, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, जो झुग्गियों को सरकार द्वारा 'अवैध' घोषित किया जा सकता है और कट्टरपंथी रूप से बेदखल किया जा सकता है। आमतौर पर, वे नगरपालिका सेवाओं के हकदार नहीं हैं पंजीकृत बस्टीज़ और अपंजीकृत लोगों के बीच अंतर, प्रवासियों की नई पीढ़ियों के आने से प्रासंगिक हो जाता है। पंजीकृत पीठियों में आश्रय ढूंढने के लिए वर्तमान पीढ़ियों के लिए मुश्किल है आखिरकार, वे अपंजीकृत स्क्वाटर कालोनियों में रहने के लिए एक जगह सुरक्षित रखते हैं, जिनमें से अधिकांश को सरकार द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाया जाना कहा जाता है। कभी-कभी ठेकेदारों द्वारा स्वयं की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है उदाहरण के लिए, शहर के अधिकांश निर्माण श्रमिकों ने भवन की जगह पर अपनी रातों को अर्ध-पूर्ण इमारतों की नाजुक छत के नीचे बिताया। लेकिन ये व्यवस्था अस्थायी और विशेष साइट पर नौकरी हासिल करने के लिए आकस्मिक है। जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चलता है, वहां श्रमिकों के कई उदाहरण लंबे समय तक 'आश्रय रहित' रहते हैं, शहर के फुटपाथ पर सो रहे हैं, रोजगार की तलाश में और जीवित रहने के लिए ।

शहर के इतिहास में एक हालिया घटना का हवाला देते हुए मित्रा ने अपने कागज को समाप्त कर दिया, जहां प्रवासी मजदूर पर्यावरण के सुधार के नाम पर उनके बस्तियों से विस्थापित हुए थे। इन बस्तियों के अधिकतर लोग शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सबसे निम्न स्तर से संबंधित थे, माल के वाहक, रिक्शा-चालक, अनुबंध मजदूर

और घर के नौकरों के रूप में काम करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहर इन सेवाओं के बिना जीवित नहीं रह सकता है और कई तरह से, वे आंतरिक रूप से शहरी रीसाइक्लिंग की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हैं। सरकार या कॉरपोरेट कैपिटल के लिए इस कार्यबल का पूर्ण निपटारा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। हालांकि, भूमि और श्रमिकों के रीसाइक्लिंग की अर्थव्यवस्था को अक्सर यथास्थिति को परेशान करने और निकासी के नए तंत्र तैयार करने की आवश्यकता होती है। नॉनदंगा में भूमि को साफ करने की आवश्यकता को 2012 की शुरुआत में प्रकाशित किए गए केएमडीए दस्तावेज में समझाया गया है जिसमें 'व्यापक विकास' के लिए थोक भूमि के निपटान के लिए 'ब्याज की अभिव्यक्ति' शामिल है जिसका अर्थ है अचल संपत्ति केंद्रों और मनोरंजक सुविधाओं की स्थापना। लेकिन विकास के इस शासन को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पुनर्गणना के बिना शहरी अंतरिक्ष के पुनर्मूल्यांकन में एक योगदान कारक के रूप में काम नहीं कर सकते। इस घटना को केवल अवशोषण के संचय के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि शहरी भूमि के रीसाइक्लिंग और शहर के कर्मचारियों की अनौपचारिकता के बीच एक संरचनात्मक संबंध के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

विस्तृत संदर्भ के साथ पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP72.pdf.

प्रवासी श्रमिक और समकालीन कोलकाता में अनौपचारिकता
-ईमन कुमार मित्रा

वर्तमान अध्ययन में प्रवास और शहरी अंतरिक्ष के सम्मिलित व्याख्याओं में श्रम के प्रश्न की केन्द्रीयता को समझना है। शहर में प्रवास के पैटर्न पिछले दो दशकों में कुछ प्रकार के बदलावों के माध्यम से चले गए हैं, शहरी नीति में पाली को देखते हुए, फैक्ट्री रिक्त स्थान को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बदलने और शहर के अंतरिक्ष में काम और श्रम के रूपों में बदलाव के लिए दिया गया। ये दो कारक समकालीन कोलकाता में प्रवासन प्रथाओं के संबंध में 'श्रम प्रश्न' समझने में महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर 'नव-उदारवाद के शहरीकरण' के संदर्भ में। Neoliberalism पूंजीवाद के संकट (मुनाफे का एक स्थिर गिरने दर) से निपटने के लिए प्रयास करता है अन्वेषण और विनिर्माण स्थलों जो de-regularized और अनौपचारिक हैं (लेकिन एसआईजेड जैसे संस्थात्मक या अनगॉर्डेड नहीं) ज़ोनिंग प्रथाओं के विशाल प्रदर्शनों के साथ शहरी नियोजन से यह पूंजीवादी संचय के नवीनतम कारनामों को पेश करने का अवसर प्रदान करता है। यद्यपि ये अवलोकन अद्वितीय नहीं हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शहरीकरण और नवउदारवाद के बीच के संबंधों को आमतौर पर माइकल हार्डट और एंटोनियो नेग्री द्वारा विकसित किए गए 'अथाह श्रम' की धारणा पर लगाया जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इक्कीसवीं शताब्दी में पूंजीवाद बेहद टेक्नोलोजीकृत अथाह श्रम के प्रसार के लिए बेहद अनुकूल है - विशेष रूप से शहरी स्थान के सभ्यता और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में - लेकिन, साथ ही, विभिन्न सामग्री के सह-अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए श्रम रूपों को बनाए रखने और अंतरिक्ष-निर्माण की एक किराये अर्थव्यवस्था के पुन: उत्पादन के जरिए शहरीकृत नव-उदारता के इन क्षणों को महसूस करते हैं। किराया अर्थव्यवस्था के स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिक मौजूद हैं इस अर्थव्यवस्था का बहुत ही ढांचा कार्यबल की अनौपचारिकता के चेहरे पर उनकी भेद्यता पर आकस्मिक है। पेपर के दौरान, मित्रा दो कार्य रूपों में दिखता है जो इस अर्थव्यवस्था को बनाने में योगदान करते हैं, जो कि सौंदर्यीकरण के संग्रहित कथाओं में समाहित हो जाता है।

अध्ययन किए गए दो कार्य रूप ठोस कचरे का प्रबंधन हैं (या इसे लोकप्रिय और सरकारी प्रवचन दोनों में कहा जाता है) और निर्माण कार्य। शहर में ज्यादातर सफाई वाली ज़िम्मेदारी बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रवासी कामगारों द्वारा की जाती हैं। दूसरी ओर, अधिकांश निर्माण श्रमिक पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से विशेषकर दो 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूर्वी मिदनापुर के हैं। ठोस कचरा प्रबंधन उद्योग में अधिकांश श्रमिक दूसरे या तीसरे पीढ़ी के प्रवासियों, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले अपने परिवार के साथ शहर में बस गए हैं। कुछ को छोड़कर, निर्माण श्रमिक मौसम में शहर में स्थानांतरित हो जाते हैं, अपने परिवारों को उनके गांवों और छोटे शहरों में पीछे छोड़ देते हैं अपने संबंधित रोजगार पैटर्न, रिश्तेदारी व्यवस्था और सांप्रदायिक पहचान में भी कई अंतर हैं।

हालांकि, 'विकसित' देशों में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जलाए जाने और स्वच्छतापूर्ण भूमि-भरने की प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है, हाल ही में कोलकाता में नगरपालिका कचरा प्रबंधन का एक अध्ययन है कि हमें बताया गया है कि खुली जगहों में कूड़ेदान । कोलकाता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी कार्यों को चार चरणों में किया जाता है - व्यापक, संग्रह, परिवहन और निपटान इसी अध्ययन से पता चलता है कि शहर में कचरे के डिब्बे की कुल संख्या 664 है। कचरे को डंपिंग ग्राउंड में ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का कोलकाता नगर निगम द्वारा स्वामित्व है। हर दिन एकत्र किए गए कचरे की कुल मात्रा 5000 मीट्रिक टन से अधिक है। अपशिष्ट निपटान के अध्ययन एक बिंदु पर एकमत से हैं: कोलकाता में मौजूदा कचरा प्रबंधन प्रणाली अक्षम है वर्तमान

प्रणाली के साथ बड़ी समस्या स्रोत या संग्रह बिंदु पर विभिन्न अपशिष्ट वस्तुओं को सॉर्ट करने और अलग करने में असमर्थता है।

इस हिस्सेदारी पर मुद्दा सिर्फ शहर की सफाई नहीं कर रहा है और इसे और अधिक स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बना दिया है। अपशिष्ट प्रबंधन के पूरे प्रवचन को रीसाइक्लिंग की धारणा से ग्रस्त है जहां प्रबंधन का मतलब है कि कचरे को लाभदायक कुछ और में बदल दिया जाए। कचरे को ऊर्जा और ईंधन में बदलना, मिशन स्टेटमेंट में स्मार्ट शहरों की एक अनिवार्य विशेषता और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित स्मार्ट शहरों के लिए दिशानिर्देश के रूप में वर्णित है। इस ज्ञान को साकार करने में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) बहुत पीछे नहीं है यह 'वात-मुक्त कोलकाता' के लिए प्रचार करता है और वह शहर के आसपास के इलाके में 'नई टाउन', राजारहाट में ऊर्जा संयंत्र को अपशिष्ट बनाने की योजना बना रहा है। हाइड्रोलिक टिपिंग सिस्टम के साथ बैटरी संचालित वाहन भी कुछ नगरपालिका नगरों में पेश किए जाते हैं इस परिदृश्य में, श्रम का सवाल एक चुप उपचार हो जाता है। वास्तव में, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के शैक्षिक और सरकारी प्रवचनों में, श्रम का प्रश्न मैनुअल स्केन्वेन्गिंग के दु: खद अभ्यास के संबंध में ही प्रकट होता है - घरों में सड़कों और सेप्टिक टैंकों का समाशोधन और शारीरिक श्रम के साथ वाणिज्यिक भवनों के साथ। इस उद्योग में श्रमिकों की पूरी पहचान - सफाईकर्मी या 'सफाई कर्मचारी' - मैनुअल स्केवेन्गिंग की धारणा के चारों ओर घूमती है। उदाहरण के लिए, सफाई कर्मचरी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन 1993 में 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के निर्माण और ड्राय लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट की निर्माण' के बाद 1993 में मैनुअल स्कॅन्गिंग के अभ्यास को समाप्त करने के लिए किया गया था। लेकिन मैनुअल स्केवेन्गिंग, अपशिष्ट निपटान के अलावा एक शहर में कई अन्य जिम्मेदारियां शामिल हैं जैसे शहर की सड़कों पर सवार होकर, वाहक ट्रकों को चलाया जा रहा है, और जल निकासी, सीवरेज और इंजीनियरिंग जिम्मेदारियां जो कि 'आधुनिक' सफाई प्रक्रियाओं के अनुकूल तरीके से मशीनों और रसायनों से निपटने में शामिल हैं ।

निजी कचरा प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती हुई संख्या के साथ भी, कोलकाता में अभी भी सबसे सुरक्षित कर्मचारी हैं। ब्रिटिश भारत में स्कैवेंजर्स के रूप में सेवा करने वाला पारंपरिक जाति समूह भांगियों थे जो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तैनात किए गए थे ताकि शहर में कूड़े, मानव मलमूत्र और मृत शरीर शामिल हो सके। यह प्रथा अभी भी उत्तर भारत में जारी है जहां भगी, मेहता, बाल्मीकिस (या वाल्मीक्स) और हेलस जैसे विशिष्ट जाति समूहों के लोगों द्वारा सड़कों और सफाई और गलीचा और सेप्टिक टैंकों की सफाई जैसी सेवाएं दी जाती थीं। हालांकि अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को विभिन्न जाति समूहों और भाषाई समुदायों से रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर अकुशल मजदूर अब भी पारंपरिक 'मेहतर जाति' से संबंधित हैं। कचरे के निपटान उद्योग में श्रम की अनौपचारिकता से केवल नौकरी की सुरक्षा का अभाव ही नहीं होता है - श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अनियमित वेतन के साथ संविदात्मक आधार पर रखा जाता है - लेकिन सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी सहित अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं। लेकिन यह सब भयानक जीवन और काम की स्थिति के संदर्भ में असुरक्षा की रोज़ाना प्राप्ति से अधिक है। केएमसी द्वारा बनाए गए और बनाए गए श्रम बस्तियों में केवल कुछ अकुशल श्रमिक ही रहते हैं। पूरे सफारी कर्मचरों को शहर भर में बिखरे कई अकड़न कालोनियों में निवास के लिए दम घुटना पड़ता है। अक्सर इन मलिन बस्तियों में उनके नौकरी विवरण के कारण उनका स्वागत नहीं होता है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और 1993 के सूखे लैट्रिन (निषेध) अधिनियम के निर्माण से, भारत सरकार ने मैनुअल स्केन्वेन्गिंग के अभ्यास को रोकने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, इस कानून और इस अभ्यास के खिलाफ बाद के जुलूस कई दलित कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी का परिणाम था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा 'आधुनिकीकरण' अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के कारण उद्योग में अकुशल श्रमिकों के महत्व को कम कर दिया गया है। किसी के सिर पर रात की मिट्टी के बर्तनों को ले जाने की भयावह तस्वीर पूर्व-आधुनिक, प्रीबर्न, रिसाइकिलिंग पूर्व भारत से अवशेष के रूप में लुप्त होती है। इस सामाजिक परिवर्तन का एक प्रतीकात्मक अहसास स्वच्छ भारत अभियान में कब्जा कर लिया गया है जहां भारत के सभी नागरिकों को झाड़ू लेने और अपने खुद के पड़ोस साफ करने के लिए अनुरोध किया जाता है। अपशिष्ट निपटान के बारे में सामाजिक वर्चस्व तोड़ने के साथ,

परंपरागत मेहतर जाति भी व्यवस्था से भीड़-भाड़ कर रहे हैं और उनके झाड़ू मध्यम वर्ग सक्रियता के अन्य साधनों में बदल रहे हैं ।

कोलकाता में स्कैवेंजर्स को शहर में स्थायी प्रवासियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहां तक कि अगर वे अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हैं, तो वे उन जगहों पर अपनी जड़ों से वियोग के कारण ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों को खोने से डरते हैं यदि वे एक नई जगह के लिए जाते हैं दूसरी ओर निर्माण श्रमिकों को प्रवासियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो इस कदम पर हमेशा रहे हैं। कचरा प्रबंधन उद्योग में मजदूरों के विपरीत, निर्माण श्रमिक वर्ष में केवल एक विशेष समय में शहर में पलायन करते हैं, मुख्यतः इस अवधि के दौरान जब कृषि उत्पादन रोक दिया जाता है और आसपास के क्षेत्र में सभी को समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों से पलायन वाले श्रमिकों की संख्या कोलकाता के पड़ोसी जिलों से प्रवास करने वालों की तुलना में बहुत कम है। अधिकांश निर्माण श्रमिक उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, पुरुलिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी और पूर्वी और पश्चिम मिडनापर्स से आते हैं। वे उद्योग में रोजगार पाने वाले थिकारों या ठेकेदारों के माध्यम से गांवों और छोटे शहरों में प्रतिनिधि हैं। कभी-कभी लोगों को काम के किसी भी वादे के बिना शहर में दिखाई पड़ता है और सियालदह और अल्टडांगा या बिधाननगर रोड जैसे शहर के रेलवे स्टेशनों के बाहर इंतजार करना पड़ता है जो सक्षम शरीर और पुरुषों की तलाश में थाकरदार द्वारा उठाए जाते हैं।

पिछले बीस वर्षों में, कोलकाता ने अचल संपत्ति और निर्माण बाजार में ब्याज की एक बड़ी पुनरुत्थान देखी है। कारखाने के स्थान अब अचल संपत्ति अटकलें के संभावित स्थलों में बदल रहे हैं। पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है और गगनचुंबी इमारतों में फंसे हैं ऊपर से पूरे शहर एक विशाल कीट की तरह दिखता है जो फ्लाईओवर, पुलों, बायपास और मेट्रो रेल पटरियों के एक जटिल वेब में फंस गया है। इस बीच, निर्माण कार्यकर्ता की स्थिति सदैव भयावह बनी हुई है, जो काम के दौरान घातक चोटों के जोखिम से भरा है, नियोक्ताओं द्वारा रहने के लिए उपयुक्त जगह खोजने का तनाव है और रोजाना शोषण का दैनिक उदाहरण है। यह मानना गलत होगा कि सरकार स्थिति को बदलने में कोई प्रयास नहीं कर रही है। 2011 में नवनिर्मित तृणमूल सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम 1996 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने 2005 में पश्चिम बंगाल बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना की है। इस योजना के लाभार्थियों को 18 और 60 वर्ष की आयु के बीच सभी निर्माण कार्यकर्ता होंगे, जिनके पास पंजीकरण के दिन से पहले 12 महीनों में 9 0 दिनों से भी कम समय तक काम किया गया था। कल्याण बोर्ड, एक ही रिपोर्ट बताती है, काम पर चोट के मामले में अस्पताल में भर्ती और विकलांगता के लिए मुआवजे, टीबी रोगियों के लिए चिकित्सा व्यय, पेंशन योजनाएं, मृत्यु लाभ, बच्चों की शिक्षा और साइकिल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता आदि का लाभ प्रदान करेगा। ऐसे लाभों का लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को एक 'सामाजिक मुक्ति कार्ड' प्राप्त करना होगा जो एक स्मार्ट कार्ड के रूप में काम करेगा, सीधे अपने बैंक खातों में जमा कर देगा। निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत नियोक्ताओं से लगाया जाएगा ताकि ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जबकि श्रमिकों को रुपये का भुगतान करना होगा। 30 सालाना फंड के लिए सदस्यता के रूप में ।

हालांकि सतह पर, पश्चिम बंगाल में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना की पहुंच काफी संतोषजनक है, लेकिन सतह को थोड़ी सी खिसकाने से एक अलग तस्वीर सामने आएगी इस योजना में देश के अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है। इस विसंगति का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि ये कर्मचारी अपने गृह राज्यों में इसी तरह की योजनाओं के तहत पंजीकृत हैं। हालांकि, यह स्पष्टीकरण उनके रोजगार की जगह पर उनके बहिष्कार के तथ्य को कम नहीं करता है, जहां वे वास्तव में शोषण के विभिन्न उदाहरणों के लिए कमजोर हैं। अपवर्जन का एक और महत्वपूर्ण मामला 18 वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों की संख्या 60 से ऊपर है। निर्माण कार्य एक सजातीय कार्य फार्म नहीं है। इसमें कई जिम्मेदारियां शामिल हैं, जिनमें उन

लोगों को शामिल किया गया है जो आसानी से युवा और पुराने द्वारा किया जाता है। अक्सर छोटे बच्चे शहर में अपने माता-पिता के साथ आते हैं और राजमिस्तिरिस या मेसन के लिए सहायक होते हैं।

कई मामलों में, वृद्ध पुरुषों को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है जो इमारत स्थल की सुरक्षा के लिए रात में निर्माण स्थल पर रहते हैं। इन आयु समूहों को छोड़कर यह योजना सुरक्षित काम के माहौल को सुनिश्चित करने में काफी अप्रभावी बनाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के लिए हर पंजीकृत कर्मचारी को बैंकिंग सुविधाओं तक नियमित पहुंच की आवश्यकता होती है - जो कि राज्य के सबसे अविकसित क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है। यह महिला निर्माण श्रमिकों को किसी भी अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं करता है जो मजदूरी असमानता और रोज़मर्रा के आधार पर यौन उत्पीड़न के जोखिम का सामना करते हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक निम्न-और मध्यम-जाति पृष्ठभूमि से आते हैं, विशेष रूप से आवास क्षेत्र में। इस उद्योग में श्रमिकों के रोजगार का अब भी बड़े पैमाने पर रिश्तेदारी नेटवर्क का प्रभुत्व है जहां समान जाति और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग एक विशेष स्थल निर्माण स्थल में इकट्ठा हुए हैं। कड़ी मेहनत के पीढ़ियों के माध्यम से संचित प्रशिक्षण और अनुभव के कारण कुछ खास नौकरियां हैं जो कि एक विशेष धार्मिक पृष्ठभूमि से लोगों द्वारा की जाती हैं। ऐसा एक नौकरी का विवरण बढ़ईगीरी है जो आमतौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद से मुस्लिम प्रवासी कामगारों द्वारा किया जाता है। हालांकि, परंपरागत रूप से, बढ़ईगीरी निर्माण उद्योग से जुड़ी नहीं है, इस दृश्य ने अब पूरी तरह सुसज्जित फ्लैटों की बढ़ती मांग के साथ बदलना शुरू कर दिया है। फिर से दोनों जिलों में कई निर्माण कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से दूसरे शहर के निर्माण कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं और एक ही ठेकेदार या निर्माता के साथ मिलते हैं। ज्यादातर मामलों में, उनकी पहचान को छिपाना पड़ता है लगभग हर हिंदू परिवार को उनके देवताओं और देवी के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है; हालांकि, मुस्लिम फर्मों द्वारा डिजाइन और तैयार की जाती लकड़ी के सिंहासनों में हिंदू देवताओं को स्थापित करना संभवतः पवित्रभक्त होना चाहिए।

निष्कर्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि शहरी सेटिंग में किराए के संचय की सबसे महत्वपूर्ण साइटें दोनों काम हैं। यदि कचरा प्रबंधन क्षेत्र शहरी रीसाइक्लिंग की दृष्टि से सौन्दर्य सभ्यता के वादे के साथ जोड़ता है, तो निर्माण उद्योग एक ठोस पृष्ठभूमि प्रदान करता है जहां यह कनेक्शन महसूस होता है और निरंतर होता है। दूसरी तरफ, दोनों उद्योगों में श्रमिक, इस किराये की अर्थव्यवस्था के मार्जिन में मौजूद होते हैं: अक्सर वे अपनी क्षमता के पूर्ण विनियोजन के बाद शहर से बाहर निकल जाते हैं, जो एक शहरी तमाशा के सनकी खेल से विस्थापित हो जाते हैं जो हमारे सपनों के निवास में रहता है ।

पूर्ण शोध पत्र (अप्रकाशित) के लिए कृपया संपर्क करें mcrg@mcrg.ac.in.

कलकत्ता में महिलाओं और प्रवासी बच्चों का अध्ययन
देबारती बागची और साबिर अहमद

यह अध्ययन दो शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जो नृवंशविज्ञान की दो अलग-अलग साइटों पर केंद्रित है। देबारती बागची कलकत्ता में प्रवासी महिला कामगारों के जीवन और काम को ट्रैक करती हैं। साबिर अहमद रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे के एक समूह के साथ काम करते है।

देबारती बागची का तर्क है कि एक प्रवासी की हमारी पहचान अभी भी काफी हद तक शहर में 'आवास' विषय की प्रकृति द्वारा सूचित की गई है। अगर कोई शहर में पैदा हुआ है और एक 'उचित घर' में रहता है तो किसी को एक प्रवासी को कॉल करना मुश्किल है। इसके विपरीत, सार्वजनिक रूप से रहने वाले लोगों को ग्रामीण इलाके की एक मौजूदा स्थिति को संदर्भित करता है - हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वह उसे एक प्रवासी बनाता है। शहर हमेशा अपने स्वयं के शब्दों में फुटपाथ निवासी की मेजबानी करता है महिला कचरा बीनने वालों को अक्सर शहर में प्रवासियों के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उनमें से कई सड़क पर रहते हैं। उनके अध्ययन से पता चलता है कि कचरे के चयन के जुर्माना वाले प्रश्न को कचरा चुनने के कार्य को समझने से संबोधित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाए, इसे अपने निवास की स्थानिकता के साथ संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए जो प्रायः हमारी प्राथमिक समझ में शामिल है कि कचरा कामगारों को प्रवासियों के लिए होना चाहिए क्योंकि वे शहर की औपचारिक अवधि के किरायेदारी से संबंधित नहीं हैं।

अध्ययन भारत में आम तौर पर और कलकत्ता में श्रम प्रवास के पैटर्न के साथ शुरू होता है और फिर प्रवासी मजदूरों के पास जाता है। यह पहली बार प्रवास के पैटर्न में कुछ हाल के रुझानों की चर्चा करता है, जिन्हें विभिन्न जनगणना दशकों से हासिल किया जा सकता है। यह मैक्रो डेटा और केएमसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की गतिशीलता के बीच वार्तालाप विकसित करने के लिए आय है। यह विचार यह देखना है कि क्या महानगर क्षेत्र में जनसंख्या रुझान बड़े राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप है या नहीं। इसके बाद, वह तीन अलग-अलग समय में किए गए केएमसी क्षेत्र में फुटपाथ निवासियों के तीन उपलब्ध सर्वेक्षणों को देखे: 1973-74 में, 1986-87 में, और 2012-13 में, शहर में प्रवास के स्थानीय गतिशीलता को समझने के लिए कामकाजी आबादी का निचला स्तर जैसा कि इन सभी सर्वेक्षणों में बताया गया है, जनसंख्या के निचले वर्गों के बीच ग्रामीण-शहरी प्रवास में प्रवृत्तियों को शहर की सड़कों और फुटपाथों पर रहने और पुनरुत्पादित समूहों से समझ लिया जा सकता है जिन्हें आमतौर पर भारत के फुटपाथ निवासियों में कहा जाता है और हाल के वर्षों में बेघर '। अगले काम के लिए फुटपाथ निवासियों और बेघर आबादी के बीच प्रवासन, व्यवसाय, जीवन और श्रम की स्थिति, कमजोरियों की प्रक्रियाओं और संरचनाओं और इस विशेष व्यवसाय समूह के बीच अवसंरचना और संसाधनों तक पहुंच का सवाल समझने के लिए कचरा बीमारियों का पता लगाने है।

दक्षिण के शहरों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर कचरा प्रबंधन, कचरा रीसाइक्लिंग और शहरी स्वच्छता पर साहित्य का प्रमुख संग्रह मौजूद है। इसके अलावा, उत्तर के शहरों के संदर्भ में स्वच्छता के ऐतिहासिक खातों ने हमें 18 वीं शताब्दी के बाद से सभ्यता और आधुनिकीकरण के तरीकों की अच्छी तस्वीर दी है। हालांकि, जैसा कि बागची दिखाती है, हम कोलकाता में ऐसे ऐतिहासिक तंत्र की अपेक्षाकृत गरीब महसूस कर रहे हैं। शहर के कचरे का प्रबंधन करने के बारे में केवल कुछ ही खाका उपलब्ध हैं। 1980 के दशक के आरंभ में क्रिस्टीन फर्देई का काम एशियाई

शहरों में अपशिष्ट के प्रबंधन में शामिल मानवीय प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। वह इन शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की विशिष्ट परंपराओं की बात करती है और विकेंद्रीकृत और भागीदारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर देती है। कलकत्ता के कचरा बीनने वाले कुछ हालिया कार्यों ने एनजीओएशन और यूनिअनिंग के बारे में लंबाई का विस्तार किया है। हालांकि, इनमें से कोई भी इस विशेष व्यवसाय समूह के निवास स्थान के स्थानिक आयाम पर जोर या चर्चा नहीं करता है।

इन टिप्पणियों से संकेत लेते हुए, वह कलकत्ता के एक विशिष्ट शहरी केंद्र में कचरा कामगारों की जीवन कथाओं की खोज करने का प्रयास करती है। इस अध्ययन का प्रारंभिक अन्वेषण लक्ष्य नृवंशविज्ञान अनुसंधान के माध्यम से अपशिष्ट पिकर्स के जीवन, श्रम और रूटीन के कुछ पहलुओं की समझ के लिए सीमित है। वह यह देखने का इरादा रखती है कि क्या उत्तरदाताओं का सीमित संख्या में गुणात्मक शोध रचनात्मक रूप से बड़े डाटा-सेट में बोलता है उनके उत्तरदाता कलकत्ता शहर में दूसरी या तीसरी पीढ़ी के महिलाएं 'बसने वाले प्रवासियों' हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी मां के साथ उत्तीर्ण होने वाले अध्ययन के तहत इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला राग-पिकर / फुटपाथ निवासी हैं। उनमें से कई ने थोड़ी देर के लिए भीख माँग दी, या घरेलू सहायता के रूप में काम किया और धीरे-धीरे चीर चुनने के लिए चले गए। प्रवासन की उनकी कहानी मुख्य रूप से घरेलू / घरेलू हानि का एक खाता है- कि कमाई करने वाले पति की मृत्यु, या उसकी निराशा ने महिलाओं को आजीविका के लिए शहर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। वे काम की एक 'स्वतंत्रता' और 'लचीलेपन' की बात करते हैं जो उनके चौबीस घंटे की व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें घरेलू सहायता पर चीर लेने के लिए आकर्षित किया गया। ऐसा इस तरह का एक कार्य-काल व्यवस्था है जो बड़े पैमाने पर महिला प्रभुत्व वाले क्षेत्र को चुनने के लिए चिंतित है। अपशिष्ट चयन क्षेत्र में स्व रोजगार इन महिलाओं को घरेलू सहायता क्षेत्र में दिन-समय के विनियमन से राहत देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वे जो आजादी कहते हैं, अनिवार्य रूप से अनुशंसा करता है कि उनका काम उनके आवास के स्थान से घनिष्ठ है। इस तरह की स्वतंत्रता उनके सिर के ऊपर छत के लिए थोड़ा आराम से रिलीज करती है।

इस प्रकार, बागची बेघर होने की धारणाओं के साथ इसे टैग करके एक सामाजिक-आर्थिक आजीविका अभ्यास के रूप में अपशिष्ट-चयन में दिख रही है। वह समय, क्षेत्र, परिवार संरचनाओं और किसी विशेष आवास क्षेत्र में और उसके आसपास होने वाले व्यवसाय में बदलावों के पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। उनका उद्देश्य उनके घरों की स्तरित स्थानिकता में अव्यवस्था करना है, जो सभी मौजूदा कार्यों में अनुपस्थित है। सड़क पर किसी विशेष स्थान पर बहु-संगठनात्मक जीवन की घटना को समझने और समझाने के लिए, इस अध्ययन पर जोर दिया गया है, हमें यह समझना होगा कि निवास की उनकी स्थितियां संरचनात्मक रूप से उनके व्यवसाय की विशिष्टताओं से कैसे जुड़ी हैं। 'बेघर' पर साहित्य शहरी गरीबों के आवास की जगह के महत्वपूर्ण आर्थिक और बुनियादी ढांचे को याद करता है। अध्ययन बताता है कि आवास सक्रियता को एक अलग तरीके से बेघर होने की आवश्यकता क्यों है। बेघर रहने वाले शहर के एक नए सीमा तक विस्थापन के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। अलग तरीके से रखें, अध्ययन व्यवसाय के आकस्मिकताओं और सामाजिक प्रजनन के प्रश्न के बीच संबंधों में दिलचस्पी लेता है जिससे अंतरिक्ष का सवाल जीवित है।

साबिर अहमद का अध्ययन उन बच्चों के जीवन की व्याख्या करता है जो अपने गरीब छोटे गांव छोड़ते हैं, शहर के जीवन की बुरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पर समाप्त होते हैं। वह दिखाता है कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म प्रवासी बच्चों के पसंदीदा स्थलों में से एक है। यह तत्काल शरण, भोजन और आजीविका सुनिश्चित करता है। एक रूढ़िवादी अनुमान से पता चलता है कि औसतन तीन प्रवासी बच्चों को अपनी आजीविका कमाने के लिए स्टेशन पर पहुंचने के लिए, उनमें से कई रेगपिकेर है , नौकरी खोजने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक है। नमूना में बच्चों की औसत आयु लगभग 12 वर्ष का अनुमान है, न्यूनतम उम्र 4 से 7 वर्ष के बीच होती है, अधिकतम उम्र 16 और 18 वर्ष के बीच होती है। उनकी आय 350 रुपये के करीब है। वे व्यसन, भोजन पर खर्च और कभी-कभी सेक्स पर खर्च किए गए पैसे को नहीं बचा सकते थे। उनमें से कई बाल श्रम के रूप में काम करते हैं, वे दुर्व्यवहार और शोषण के संपर्क में आते हैं। वे कई कमजोरियों से पीड़ित हैं जो शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार के शिकार होने से

लेकर संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से वंचित हैं। हमारे चारों तरफ बच्चों की उपस्थिति के बावजूद, इस मुद्दे पर हाल ही में बहुत कम ध्यान दिया गया। बच्चों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं में कुछ प्रावधान हैं, लेकिन वे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में बहुत कम सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 200 9 सड़क के बच्चों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की बात करता है। हालांकि, हम जो देखते हैं वह बहुत बड़ी संख्या में बहिष्कार और बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी है। बच्चों के एक करीब पचास प्रतिशत को प्राथमिक विद्यालयों में कुछ समय पर नामांकित किया गया था, लेकिन शायद ही पढ़ा और लिख सकता था। हैरानी की बात है, लगभग 80 प्रतिशत बच्चों ने अपनी क्षमता को मौखिक और तुरन्त गणना की है।

स्वयंसेवी संगठनों और रेलवे प्राधिकरणों द्वारा दर्ज की गई अपनी प्रोफ़ाइल का एक करीब से पठन बताता है कि सियालदह स्टेशन में करीब 78% बच्चे अनुसूचित जातियों और मुसलमानों में से है। ज्यादातर मामलों में, बच्चों के माता-पिता स्थानीय श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, जैसे कि कृषि मजदूरों,, बिरी बाँधने वाले, कूलियों, माली, रिक्शा-चालक, वैन-खींचने वाले और स्थानीय दुकानों में सहायक। उनमें से कुछ कारखाने के कर्मचारियों और चालकों के रूप में काम करते हैं। कुछ मामलों में, कुछ माता-पिता स्थानीय इलाके में छोटी किराने की दुकानों की खरीद करते हैं। अहमद के अध्ययन में कम वेतन वाले माता-पिता, उनके बड़े परिवार का समर्थन करने में असमर्थता, बच्चे से मिलने वाली उम्मीदें और बच्चे को घर से भागने के लिए मजबूर होना कारकों के बीच संबंधों को दिखाकर संरचनात्मक हिंसा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर बताता है । उनके शोध से पता चलता है कि माता-पिता जो छोटे उद्यमों या किराने की दुकानों के मालिक हैं, वे अपने उद्यमों में लंबे समय तक बच्चों की भागीदारी चाहते थे। यह कारण बच्चों में भाग लेने के लिए एक कारण है ।

सियालदह स्टेशन पर, करीब 80 प्रतिशत बच्चों को पश्चिम बंगाल से है, शेष बच्चों को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे चार या पांच पड़ोसी राज्यों में फैल गया। पश्चिम बंगाल के भीतर, बच्चों का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता और उसके आस-पास के जिलों (उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली) से हैं। सियालदह स्टेशन के निकट जिले में से एक और रेलवे संचार से जुड़ा हुआ है, दक्षिण 24 परगना प्रवासी बच्चों के स्रोत क्षेत्रों की सूची में सबसे ऊपर है। अपमानजनक परिवार की स्थिति और गरीबी के पारंपरिक कारणों के अलावा, विस्थापन के कारण प्राकृतिक आपदाओं और परिवारों के अव्यवस्था के चलते बच्चों का एक हिस्सा सियालदह स्टेशन पर चले गए। बच्चों का एक छोटा खंड (4 प्रतिशत) बांग्लादेश से है। विभिन्न श्रेणियों के तहत बच्चों के लिंग-वार वितरण पर एक करीबी नतीजा यह दर्शाता है कि लड़कों को भागने की अधिक संभावना है, जबकि लड़कियों को खो जाने, त्याग और तस्करी होने की अधिक संभावना है। जैसा कि पहले बताया गया है कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवासी बच्चों के मुद्दों को बच्चों और बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के दायरे से परे था। स्वतंत्रता के बाद से रेलवे मंच पर बच्चों की उपस्थिति के बावजूद, रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत परंपरागत औचित्य यह था कि बच्चों को मंच पर नहीं रहने देना चाहिए। मौजूदा कार्यक्रम और नीतियां शायद ही इस बारे में सीधे बोलती हैं कि हम इन बच्चों को शहर के सही निवासियों के रूप में शामिल करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं।

ये बच्चे पूरी तरह से पुनर्वास के लिए उचित उपाय करने के लिए न्याय अधिनियम संशोधन (2010 के तहत देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कानूनों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (2009), यौन अपराध अधिनियम (2012), युवा न्याय अधिनियम संशोधन अधिनियम (2010) और बच्चों पर राष्ट्रीय नीति (2013), एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009 में एकल विंडो एजेंसी के रूप में शुरू की गई थी बाल सुरक्षा के मुद्दों के साथ सौदा करना। ये कानूनी प्रावधानों का उपयोग कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं।

हाल ही में हमने दिसंबर 2013 में मुद्दों के एक महत्वपूर्ण विकास और स्वीकृति को देखा है, जब बाल अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा एक रिट याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रेलवे द्वारा बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश की गई थी। मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) या प्रोटोकॉल्स को रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में बाल सुरक्षा के मुद्दों और भारतीय रेलवे और अन्य हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के संदर्भ में तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करने के उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया है, ऐसे बच्चों को ' देखभाल और संरक्षण की जरूरत है 'अकेले यात्रा करने वाले या परिवार के साथ या परिवार के बिना रहने वाले लोगों की पहचान करना।

एसओपी के साथ मिलकर, सियालदह को पश्चिम बंगाल में बाल-अनुकूल स्टेशन घोषित किया गया है, जो रेलवे और सामाजिक कल्याण और महिलाओं और बाल विकास दोनों के द्वारा घोषित किया गया है। इसके लिए, एक कियॉस्क का उद्घाटन किया गया, ताकि जब बच्चे स्टेशन पर आये तोह उन्हें सहायता मिल सके । 'बच्चे के अनुकूल कोने' की स्थापना के इस कॉस्मेटिक कार्यकर्म के अलावा, कुछ बुनियादी सवालों के अनसुलझे रह गए हैं: कैसे इन बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम के पूर्वावलोकन के तहत लाया जा सकता है, कैसे इन बच्चों को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में एकीकृत किया जा सकता है , कन्या श्री प्रक्लापा के लाभ लेने के लिए बालिकाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अंत में, क्या हम इन बच्चों के खोए हुए बचपन को बहाल करने के लिए निरंतर तरीके से बजटीय आवंटन पर एक प्रवचन शुरू कर सकते हैं?

विस्तृत संदर्भ के साथ पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP72.pdf

समकालीन कोलकाता में देखभाल अर्थव्यवस्था और महिलाओं का प्रवासन
माधुरीलता बासु

अध्ययन कोलकाता के आयुधों और नर्सों पर ध्यान देने के साथ, समकालीन पूंजीवाद के तहत श्रम के एक गिनेदार डोमेन का पता लगाने का प्रयास करता है। कोलकाता में और आसपास के क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर, यह उनकी नौकरियों की प्रकृति, गतिशीलता के पैटर्न का अध्ययन करती है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संरचनाओं के माध्यम से परिचालन के रूप में 'देखभाल' में भी दिखता है नर्सों, अस्पतालों और नर्सिंग होम में काम कर रहे, संस्थागत या औपचारिक देखभाल प्रणाली से संबंधित हैं, जबकि ऐया, ज्यादातर निजी घरों में काम करने वाले हाथों में काम कर रहे हैं अनौपचारिक देखभाल अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। इसके अलावा, उचित कौशल, शिक्षा, प्रशिक्षण के बिना आयता हाशिए पर पड़ जाता है। जबकि पूरे समय के घरेलू नियोक्ता के परिवार में रहने में मदद करता है, अयाज (जो कि नैनियों और घर की नर्सों के संयुक्त कर्तव्यों को पूरा करते हैं और घर में अन्य काम करने के साथ-साथ खाना पकाने और सफाई भी करते हैं) या तो बड़े शहरों या विभिन्न जिलों से निकटतम बड़े शहर तक उपनगरीय इलाके से महिलाओं का यह हर रोज़ प्रवाह, अधिकतर किसी का ध्यान नहीं जाता ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, पेशेवर मध्यवर्ती बाजार अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में पहचाना गया है और काफी विस्तार हुआ है। वे नए देखभाल-व्यवस्था के मुख्य ग्राहक हैं। सेवा के रूप में 'देखभाल' को विभिन्न क्षेत्रों से निकाला जाता है। निकासी की प्रकृति विभिन्न स्तरों पर भी अलग है। हा लांकि, नर्सों के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण के साथ देखभाल करने वाले कोलकाता जैसे कई शहरों में काम करने के लिए बड़े शहरों में आ रहे हैं, जबकि उपनगरों में से कोई एक समूह नहीं है जो शिक्षा के साथ या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, या तो अस्पताल में विशेष सहायक या अयाह या घरेलू निजी घरों में मदद करता है ।

वृद्ध, कमजोर या बच्चों को देखभाल करने के मामले में बढ़ते मध्यम वर्ग को अब अतिरिक्त सहायता मिल सकती है - जो कार्य पहले किसी घर के सदस्यों द्वारा किया गया था इसके अलावा, मध्यम वर्ग, पेशेवर महिलाएं और मध्यम वर्ग के घरेलू निर्माताओं ने आज अपने परिवार के कर्तव्यों को महिलाओं के दूसरे भाग में सौंप दिया है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और परिधि में मौजूद हैं। पति, विधवा और अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की तरह निराशा जैसे विभिन्न प्रकार के श्रम बाजार में बातचीत करने के लिए अयाह की शक्ति कम हो जाती है। गरीबी के 'नारीकरण' और 'मातृत्व के गुनहगार' की यह प्रवृत्ति, जिसे कई समृद्ध देशों में भी देखा गया है, गंभीरता से महिला सौदा करने की शक्ति को प्रभावित करती है ।

भारत में, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे, मजदूरों के बाद श्रमिक सेना में शामिल होते हैं, जब पुरुष सदस्यों के मामले में आय के नियमित स्रोत से धन का प्रवाह सीमित हो जाता है या सीमित हो जाता है। चूंकि श्रम बल में उनकी प्रविष्टि अपने परिवारों की ज़रूरत से तय होती है, इसलिए पत्नियों के रूप में उनकी पारिवारिक भूमिकाएं और माताओं उनकी कामकाजी पहचान का हिस्सा रहे हैं और इसलिए वे कम मोबाइल हैं और भुगतान किए गए कार्यों के लिए अधिक समय तक काम करने में असमर्थ हैं।

ज़्यादातर महिलाएं अपने घर से रोज़ काम तक आना जाना करती है । इस अध्ययन के लिए जिन 40 महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया है, उनमें से 34 दैनिक यात्रियों की सूचना दी गई हैं। उपनगरीय रेलवे कई लोगों को अपने काम के स्थान पर जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलकाता के उपनगरीय रेलवे क्षेत्र दक्षिण बंगाल के नौ जिलों को कवर करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण यात्री टर्मिनलों में सियालदह और हावड़ा हैं। पूर्वी रेलवे की उपनगरीय सेवाएं सियालदह, कोलकाता और हावड़ा स्टेशनों से दोनों काम करती हैं। लगभग सभी उत्तरदाता रेलवे स्टेशनों जैसे सियालदह, बिधाननगर, गारिया और पार्क सर्कस जैसे रेलवे स्टेशनों का प्रयोग करते हैं जो कि महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
2011 में, अयाह प्लेसमेंट केंद्रों में से कुछ, जो साल्ट लेक (पूर्व कोलकाता), जादवपुर और न्यू अलीपुर (दक्षिण कोलकाता) में अपने भावी नियोक्ता के साथ आयतों से जुड़े थे, उनके मासिक वेतन का 10-15% शुल्क लगाया गया था। 2014 में, केन्द्रों द्वारा लगाए गए राशि का प्रतिशत थोड़ा नीचे आ गया है, क्योंकि ये प्लेसमेंट केंद्र अब अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। यद्यपि आजकल नियुक्ति केंद्रों की एक प्रवृत्ति रोज़गार प्रक्रिया को थोड़ा कड़े बनाने के लिए है: महिलाओं को केंद्र या एजेंसियों के पास दो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ़ और पहचान पत्र जमा करना होगा। लेकिन पहले, कोई पहचान प्रमाण के बिना महिलाएं भी रोजगार की तलाश कर सकती थीं। केयर सेक्टर में काम करने के लिए कोलकाता आने वाली अधिक से अधिक अकुशल महिलाएं, प्लेसमेंट केंद्र रोजगार के लिए उम्मीदवारों से कम नहीं हैं। कभी-कभी, एक विशेष 'केंद्र' से आने वाली आयतों, व्यक्तिगत संबंधों और रोजगार के दौरान अर्जित अच्छी प्रतिष्ठा के आधार पर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। कई मामलों में वे ऐसा करते हैं ताकि उनके केंद्रों को कमीशन के भुगतान से बच सकें।

2015 में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, वर्तमान में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तहत श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि भारत आईएलओ कन्वेंशन नं। 168 को घरेलू श्रमिकों के लिए अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि यह नहीं था मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं के अनुरूप इससे पहले, केंद्र सरकार ने घरेलू श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत कुछ लाभ भी प्राप्त किए। लेकिन हाल ही में, एक मसौदा प्रस्ताव श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है जो पूरे समय के वेतन और अंशकालिक घरेलू कामगारों को तय करने का लक्ष्य रखता है। रु। का न्यूनतम वेतन 15 दिनों की छुट्टी और कुछ अन्य लाभों के साथ, पूर्णकालिक घरेलू कार्यकर्ता के लिए प्रति माह 9000 का सुझाव दिया गया है।

शहरों के आकार में वृद्धि, मध्यम वर्ग की वृद्धि और कई 'चिकित्सा पर्यटन' शब्द की वृद्धि के साथ, भारत में प्रशिक्षित नर्सों की बढ़ती मांग है। इस प्रकार, हम भारत के विभिन्न राज्यों से निजी अस्पतालों में नर्सों का एक सतत प्रवाह पाते हैं। यद्यपि भारत के दक्षिणी राज्यों में नर्सिंग संस्थानों की एकाग्रता में गिरावट आई है, बीएससी की पेशकश करने वाली संस्थाओं की संख्यानर्सिंग में डिग्री छह गुना बढ़ी और 2004 और 2010 के बीच जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ़री (जीएनएम) डिप्लोमा कोर्स तीन बार बढ़ने लगे। स्नातक नर्सिंग कार्यक्रम की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए यह गिरावट आई थी - 2004 में 78% से बढ़कर 2010 में 60% उन जीएनएम पाठ्यक्रमों की पेशकश की तुलना में, देश के बाकी हिस्सों की तुलना में नर्सिंग संस्थानों में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पूर्वी मेट्रोपॉलिटन बाईपास के एक निजी अस्पताल में साक्षात्कार में पता चला कि 1200 नर्सों में से 65% भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं। उनमें से अधिकांश केरल से आते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और मणिपुर कभी-कभी, मानव संसाधन विभाग पूरे देश में अलग-अलग नर्सिंग कॉलेजों से संपर्क करता है जब अस्पताल में नर्सों की आवश्यकता होती है, या ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र से नर्सों का एक समूह एक बड़े समूह में आकर अपने सीवी में बदल जाएगा। हालांकि अस्पताल ने एमएससी, बीएस्सी। और जीएनएम नर्सों (नर्सों जिन्होंने जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स पास किया है), एएनएम नर्स (नर्स जो सहायक नर्सिंग

मिडवाइफ़री डिप्लोमा कोर्स पार कर चुके हैं) को नियोजित नहीं किया गया था और हालांकि अयाज विभिन्न क्षमताओं में अस्पताल में या मरीज के परिवार के आदेश पर काम करते थे , उनके नाम पेरोल में नहीं थे

केरल से रीनता राजू के साथ एक साक्षात्कार, जो ट्रस्ट द्वारा चलाए गए दक्षिण कलकत्ता अस्पताल में कार्यरत हैं, ने बताया कि 100-200 नर्सों में से करीब 25% बाहर के हैं। केरल से 20 नर्स जीएनएम की परीक्षा पास कर चुके हैं और बाकी ओडिशा और मणिपुर से हैं। निजी नर्सिंग होम में, पश्चिम बंगाल के बाहर के नर्सों की संख्या नगण्य है। उत्तर-मध्य कोलकाता में एक नर्सिंग होम के दौरे से पता चला है कि सुंदरबन, बोंगाओं और अन्य जगहों से पलायन करने वाली महिलाओं ने नर्सों और अयाहों के लिए मददगार के रूप में काम किया है। इसके अलावा, बारासात और बर्दवान (बड़े जिला कस्बों) में नर्सिंग होम में आयोजित साक्षात्कारों ने अन्य राज्यों से नर्स की अनुपस्थिति का खुलासा किया। जिले में कृषि उत्पादकता में गिरावट के साथ, महिलाओं को बहुत कम वेतन पर चौबीसों घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया है।

कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ एक अनौपचारिक साक्षात्कार में, यह पता चला कि यद्यपि महिलाएं पीजी डिप्लोमा या एमएससी में अध्ययन करने के लिए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में आती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य से बाहर के पाठ्यक्रम, वे सरकारी अस्पतालों में रोजगार नहीं मिलते, क्योंकि त्रिपुरा या मणिपुर से नर्सों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई कोटा नहीं है, जो ज्यादातर यहां अध्ययन करने आते हैं। इस प्रकार, अगर उन्हें कोलकाता में रोजगार मिलना है, तो उन्हें निजी अस्पतालों में आवेदन करना होगा।

 स्पष्ट हो जाता की सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से स्नातक नर्सों या अन्य सरकारी नर्सिंग स्कूलों को पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों द्वारा भर्ती किया जाता है, जहां निजी अस्पतालों में यह वेतन अधिक है। उदाहरण के तौर पर, एक सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स (ग्रेड II) के अनुभव के आधार पर, रु। 7100 और रु .37600 के बीच कुछ मिलेगा।

इसके अलावा, विदेशी मुद्राओं के खिलाफ रुपये के मूल्य में गिरावट ने भारत में चिकित्सा पर्यटन की सुविधा प्रदान की है। मेडिकल टूरिज्म में उछाल ने गलेनैगल्स, कोलंबिया एशिया और वॉक्हार्ट जैसे निजी उद्योगों में कई निजी खिलाड़ियों को लाया है, जो अस्पतालों को स्थापित करने के लिए तैयार हैं और देखभाल करने वाले आवास, फार्मेसियों जैसे अन्य आकर्षण के साथ एकड़ जमीन पर फैली दवाएं ' और रेस्तरां, बच्चों के लिए खेल क्षेत्रों, पुस्तक भंडार आदि समकालीन समय में, नर्सों इंडोनेशिया, मलेशिया, खाड़ी देशों, कनाडा और अन्य जगहों जैसे देशों में पलायन करते हैं, जहां वेतन बेहतर है, घरेलू देश में एक वैक्यूम छोड़कर। लेकिन नर्सों को कोलकाता में स्थानांतरित करने के लिए, केवल बेहतर वेतन की तर्क पर समझाया नहीं जा सकता है ।

देखभाल के क्षेत्र में होने वाला एक और बदलाव, पोर्टे चिकित्सा या भारत होम हेल्थ केयर जैसे बड़े खिलाड़ियों या संगठनों का प्रवेश है जो घरेलू परिवारों में देखभाल या चिकित्सा सहायता प्रदान करता है या दूसरे शब्दों में इन-होम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है इंडिया। चिकित्सकों, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रशिक्षित नर्सों को बीमार या हाल ही में अस्पतालों से रिहा किए गए लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर पोर्टेआ मेडिकल या भारत होम हेल्थकेयर अस्पतालों के साथ काम कर रही है, तो दीप प्रोबेन पोरिशेबा जैसी संस्थाओं से बाहर रहने वाले लोगों को अपने पुराने और बीमार माता-पिता की देखभाल करने की इजाजत है।

तथ्यों और आंकड़ों को लिया गया है http://www.indiannursingcouncil.org/.

अनुसंधान संक्षेप
धारा 2: दिल्ली

राजधानी शहर: कानून और नीति की भ्रामक विसंगति
-अमित प्रकाश

यह अध्ययन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) को शासित करने के लिए मौजूदा नीति और कानूनी ढांचे के पीछे वैचारिक परिसर की जांच करता है। संवैधानिक योजना में अपने विशिष्ट स्थान के कारण एनसीटी के संबंध में विश्लेषण का यह फोकस अधिक से अधिक मिलता है, जिसमें यह एक संघ राज्य क्षेत्र और एक राज्य है जिसमें कई एजेंसियों और दक्षताओं में शक्तियों और कार्यों को भंग किया जा रहा है। तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना - एक शहर की अवधारणा, गरीबी और आजीविका का प्रश्न, और इन नीतियों में प्रवासियों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है - अध्ययन का अध्ययन करता है कि उनके इंटरस्टेस एक शहर के निर्माण की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोधक स्थान कैसे बनाते हैं अपने denizens का सामना महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए शहरी नियोजन और विकास के विघटनकारी आधिपत्य, जो कि दिल्ली के प्रशासन के ढांचे को सूचित करता है तकनीकी और नौकरशाही नियंत्रण, केंद्रीकरण और विश्व स्तरीय सुंदर शहर की बुर्जुआ की आकांक्षाओं से प्रेरित है। इस विचारधारात्मक फ्रेम में, सामाजिक न्याय के मुद्दे गरीब और हाशिए वाले लोगों के अदृश्य होने के एक विशिष्ट प्रयासों के कारण पिछली सीट लेते हैं। दिल्ली के निष्पक्ष चेहरा पर एक धब्बा के रूप में देखा जाने वाला यह प्रयास बाहरी इलाके में उत्पादक उद्यम को हटाने और श्रमिक उद्योगों को कम करने की सीमा तक चला गया है। 2021 के लिए दिल्ली मास्टर प्लान के एक अध्ययन से पता चलता है कि नीतिगत चर्चा अक्सर इस तथ्य से लापरवाही होती है कि एक ही गरीब और प्रवासियों, जिन्हें अनुशासित या अन्वेषित करने की मांग की जाती है, शहर में आर्थिक विकास और सेवा उद्योग के मोटर्स हैं।

इसे यहां पहचाना जाना चाहिए कि नीति और कानूनी निर्माण में, शहरों के विकास की जैविक स्वभाव को नजरअंदाज किया जाता है। शहरों ने पारंपरिक रूप से तीन गुना कार्य किया है, जो इसे एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय है जो उन्हें अन्य मानव निवास समूह से अलग बनाता है। सबसे पहले, शहरों में राजनीतिक सत्ता के केंद्र हैं और इस प्रकार सैन्य 'ढांचे' या छतों। हालांकि राजधानी शहर अतीत में समान सैन्य कार्यों का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन यह राजनीतिक प्रतियोगिताओं के तंत्रिका-केंद्र और निर्णय लेने के रूप में सेवा जारी रखती है। यह दिल्ली को एक अनोखे विचलित चरित्र प्रदान करता है, जो संरचनाओं और नीति को सीमित करता है और कानूनी विकल्प जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

इसके अलावा, दिल्ली, सभी प्रमुख शहरों की तरह, उत्पादन और विनिर्माण के लिए एक केंद्र होने के अलावा, उत्पादन और कलाकृतियों के व्यापार का केंद्र भी रहा है। वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि पिछले 200 वर्षों से उत्पादन की बदलती प्रौद्योगिकियों ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के साथ समकालीन शहरों को बहुत अधिक चरित्र प्रदान किया है जो कि अपनी बहुआयामीता में शहरीकरण की प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया ने मजदूरी श्रम के कंटेनर के रूप में शहरों को देखने के लिए तर्क बनाया (जिसे केवल गैर-औद्योगिक क्षेत्र से प्रवासियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है), साथ ही साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए एक कंटेनर (दोनों, गर्भधारण की पूछताछ के साथ-साथ प्रतियोगिता के लिए इसके पीछा) यहां याद किया जा सकता है कि ऐतिहासिक

रूप से, यूके के औद्योगिक शहरों की कल्पना जैसे लंदन, मैनचेस्टर और ग्लासगो को प्रायः दोनों तरह के रूप में देखा जाता है, आदिम संचय की प्रक्रिया के चरम अभिव्यक्ति और मुक्त राजनीति की प्रतियोगिताओं की साइटें - सार्वभौमिक मताधिकार , सामाजिक अधिकार, श्रम संगठन, सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता, विशालतावाद, और सामाजिक-सांस्कृतिक एकता दिल्ली तर्कसंगत रूप से कई प्रक्रियाओं की एक समान साइट है, जिस पर एक अवरुद्ध स्तर पर असंगति और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। एटेक्निक की तैनाती और 'सेवा अर्थव्यवस्था' की वृद्धि के संदर्भ में उत्पादन की प्रौद्योगिकियों के विकास का नवीनतम चरण इस प्रक्रिया को एक और परत जोड़ता है।

आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शहरों के विकास की इस प्रक्रिया की चर्चा में, शहरों का एक हिस्सा रहा है और तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्थान रहा है और विकसित केन्द्रीयकृत आधुनिक राज्य पर एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। शहर प्रशासनिक नियंत्रण के तंत्रिका केंद्रों के रूप में और इस प्रकार, राज्य संरचनाओं की अनुशासन क्षमता कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के भीतर होती है, जिसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और लड़ेगी। शहरों की यह महत्वपूर्ण बहुआयामी भूमिका, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दों और प्रवासियों जैसे दुर्लभ वर्गों की आजीविका के संदर्भ में, अक्सर शहरी सामाजिक-राजनीतिक संगठन के रूप में दिल्ली की कल्पना करते समय देखा जाता है।

दिल्ली के आधुनिक विचारधारा (और संभवत: भारत के अधिकांश शहरों) में, जो आधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं - मध्यम वर्ग, आधुनिकीकरण, आकांक्षात्मक वर्गों - को शहर की अर्थव्यवस्था और समाज में मूल्य जोड़ने के रूप में देखा जाता है उनके परिश्रम को केवल मान्यता प्राप्त नहीं है बल्कि उपयुक्त उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की सेवा देने वाले शहरी क्षेत्रों में गेट एलिट कॉलोनियों के शहरी परिदृश्य में सदस्यता द्वारा उचित रूप से पुरस्कृत किया गया है। गरीब और (ज्यादातर गरीब) प्रवासियों को शहर में विकार, गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के द्वारा एक नाली के रूप में देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से संकेतित तकनीकी शहर की योजना में कोई अवधारणा नहीं है कि ये 'अवांछनीय' शहर के आर्थिक सिनवे हैं और उनकी ताकत के बिना, शानदार शहर जल्द ही कचरा और गड़बड़ी पर जलमग्न हो जाएगा और बुनियादी ढांचा निर्माण । इस पॉलिसी के मामले में एक मामूली तथ्य यह है कि 'योजनाबद्ध कालोनियों' के पास गरीबों के लिए कोई अवधारणा नहीं है, जो उन्हें सेवा प्रदान करते हैं।
इस प्रकार सामाजिक न्याय के मुद्दों को व्यापक रूप से उजागर किया जा रहा है और कानून और नीति का विघटनकारी विश्लेषण करने के लिए ढांचे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में, शहर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंतरिक्ष की तैनाती के बारे में सर्वसम्मति को भी समस्या बनाने में महत्वपूर्ण है। आधुनिकतावादी योजनाकारों ने पूंजी के प्रजनन के लिए शहरी परिदृश्य के लिए अंतरिक्ष की तैनाती की कल्पना की, समुदाय की तैनाती के द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए। शहरी नियोजक फ्लाईओवर, मॉल और सड़क की इच्छा रखते हैं, जो समुदाय अंतरिक्ष की वैकल्पिक अवधारणा की मांग कर सकते हैं। इस संघर्ष में, यह शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे सेवाओं की आपूर्ति के तंत्रों तक कम हो जाते हैं: विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बुनियादी ढांचा, और संभवतः, दूर स्थित बस्तियां ।

विश्लेषण के इस तरह के एक फ्रेम में प्रवासियों को पता चलता है कि इस तथ्य के कारण उचित हो जाता है कि नीति और कानूनी फ्रेम उन लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनके पास नीतिगत प्रक्रिया में एक संस्थागत या प्रक्रियात्मक स्थान है, ऐसे फैसले का निहितार्थ स्थलीय जनसंख्या और श्रमिक इस तरह उत्पन्न प्रतिनिधित्व और वैधता घाटे दोनों में खेलना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शहर की समस्याओं के साथ-साथ शहर के लिए एक वांछित भविष्य का एक सपना तैयार करने के साथ-साथ दृष्टिकोणों के असंतोष और बहुतायत में तेजी से गिरावट की जगह है।

यह रेखांकित होना चाहिए कि प्रवासी जनसंख्या शहर के आर्थिक (और सेवा) आवश्यकताओं के इंजन हैं, लेकिन उपर्युक्त प्रतिनिधित्व और वैधता घाटे के कारण, नीति और कानून की केंद्रीय चिंता के रूप में ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजतन, इस तरह के प्रवासी जनसंख्या के संबंध में मुद्दों को हल करने के लिए किए गए उपायों में एक डिग्री के साथ-साथ नीतिगत जड़ता और अप्रासंगिकता भी होती है। आधुनिकतावादी शहर में ऐसी सामाजिक रिक्त स्थान के लिए कोई स्थान नहीं है, जो मोबाइल, मौसमी और जनसंख्या अनुशासन के लिए कठिन है क्योंकि वे आसानी से आधुनिकतावादी वर्गीकरण और स्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। शहर के इस तरह के एक उदार आधुनिकतावादी पुनर्गठन की लालसा की इच्छा अदृश्य अप्रवासी है जो शहर में ऐसी कई आवश्यकताओं के लिए श्रम प्रदान करती है - घरेलू कार्य को निर्माण कार्य के लिए, लेकिन सामाजिक न्याय का दावा नहीं करता कि वह शहर को वापस पकड़ सके। अपने आधुनिकीकरण सपने का पीछा करते हुए ऐसे शहर में 'अनियंत्रित' और 'अवांछनीय' प्रवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है, जिन्हें शहर के अंतरराज्यीय इलाकों में से निकाला जाता है: 'शहरी गांवों' और परिधि।

जबकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और यहां तक कि सेवा प्रावधान के मुद्दे दिल्ली में गड़बड़ी का एक आदेश है, जो आसानी से साफ होने की संभावना नहीं है, दोनों में असंतुलित सहमति, मीडिया और शहरी नियोजन मंडलों को सुंदर बनाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक विशेष छवि परियोजना के लिए शहर सौंदर्यीकरण के इस प्रवचन में कम से कम तीन अलग-अलग, परस्पर संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है: (ए) शहर को अपने उचित चेहरे पर फफोले के रूप में देखा जाने वाला स्थान निकालना: झुग्गी (कई या अधिकतर प्रवासियों द्वारा आबादी वाले); (बी) शहर और अन्य जगहों की मध्यवर्गीय आबादी की खपत के लिए विरासत का कमोडिटीकरण; और (सी) 'वैश्विक शहर' के रूप में दुनिया के साथ 'पकड़ना' शहर को संचालित करने के मुख्य पैरामीटर के रूप में सौंदर्य की प्राथमिकता के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक आवास और खाद्य सब्सिडी के क्षेत्रों से सार्वजनिक निधियों के मोड़ को लेकर उच्च प्रोफ़ाइल अवसंरचना के निर्माण में निवेश करने की वजह से गरीबी को नजरअंदाज कर दिया गया और दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दिल्ली में सौंदर्यीकरण के मापदंडों में दिल्ली का 'विश्व स्तर' बनने के प्रयासों की आकांक्षाओं और गरीब वर्गों और झुग्गियों की आबादी के साथ थोड़ा सा संबंध नहीं है। दिल्ली मास्टर प्लानों में लिखी जाने वाली घोषणाओं की एक श्रृंखला एक ही अवरोधक तर्क का पालन करती है, जो कि ऊपर चर्चा की गई है, जिसमें सौंदर्यीकरण, संरक्षण और पर्यावरणवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि गरीबों की आवश्यकताओं पर थोड़ा ध्यान दिया जा सके।

गरीबों और प्रवासियों के अनिश्चित सामाजिक-आर्थिक और स्थानिक अस्तित्व, कम-भुगतान, अकुशल या अर्धसैनिक, आकस्मिक श्रम और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जीवित करते हैं, जो कि टेक्नोकरीक शहरी नियोजन के तहत नगर निकाय निकायों द्वारा 'निकासी' की लगातार खतरा हैं दिल्ली के बुर्जुआ के दर्शन के रूप में वैश्विक शहर एक विशिष्ट लोकतांत्रिक खतरा है जो दिल्ली को नियंत्रित करता है। योजना निकायों को केंद्रीकृत, तकनीकी रूप से प्रकृति में है और मतदाताओं के लोकतांत्रिक मांग-निर्माण के अधीन नहीं। दिल्ली की मतदाताओं को दिल्ली की सरकार के विज्ञापन-हॉकिस्ट पॉलिसी समाधानों को प्रभावित करने की सीमित सीमा को भी एलजी और केंद्र सरकार के कार्यालय के सामने दिल्ली सरकार के संरचनात्मक स्थान से भी सीमांकित किया गया है। सीमित उत्तरदायित्व के इस ढांचे के भीतर, दिल्ली का सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कि विश्व स्तर के मध्यवर्गीय विचार द्वारा आक्रामक रूप से अपनाया गया है। यह हाल के वर्षों में दिल्ली के बजट में धन के आवंटन के द्वारा प्रमाणित है। शहरी आवास के प्रमुख, जो गरीबों और 'अवैध' जेजे समूहों से उखाड़ फेंकने वाले प्रवासी पर असर डालता है, में पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखी गई है: 2011-12 में बजट का 14 प्रतिशत से 2015-16 में 9 प्रतिशत हो गया है।

उपर्युक्त चर्चा से, एक यह विचार प्राप्त कर सकता है कि शहरी नियोजन और विकास के इस असंतुलनकारी आधिपत्य, जो कि दिल्ली के प्रशासन के ढांचे को सूचित करता है, तकनीकी और नौकरशाही नियंत्रण, केंद्रीकरण और विश्व स्तरीय सुंदर शहर की बुर्जुआ की आकांक्षाओं से प्रेरित है। यह भी स्पष्ट है कि इस विचारधारात्मक फ्रेम

में, सामाजिक न्याय के मुद्दे गरीब और हाशिए पर बने लोगों के (invisiblization) पर एक विशिष्ट प्रयासों के कारण पिछली सीट लेते हैं। दिल्ली के निष्पक्ष चेहरा के चेहरे पर एक धब्बा के रूप में देखा जाने वाला यह प्रयास बाहरी इलाके में उत्पादक उद्यम को हटाने और श्रमिक उद्योग को कम करने की सीमा तक चला गया है। लिटिल पॉलिसी विवेचना इस तथ्य पर केंद्रित है कि एक ही गरीब और प्रवासियों को अनुशासित या अन्वेषित करने की मांग की गई है, जो शहर में आर्थिक विकास और सेवा उद्योग के मोटर्स हैं। सीमित चुनावी आवाज से मामलों की सहायता नहीं की जाती है, जो शहर की प्रशासन संरचनाओं को अनुमति देते हैं; और, इस तरह के प्रभाव के लिए मौजूद छोटी संभावनाएं नियोजित, अनुमोदित कॉलोनियों तक सीमित हैं, जिनमें गरीब और प्रवासियों नहीं रहते हैं। शासन तंत्र और साथ ही गरीब और प्रवासियों दोनों को शहरी नियोजन की एक सरकारी व्यवस्था के द्वारा अनुशासित किया जाता है और जब तक कि शासन संरचनाओं में बड़े बदलाव किए जाने पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक दोनों प्रवचन और नीति को एक अलग मार्ग के रूप में दिखाया जाना संभव नहीं है ।

विस्तृत संदर्भ के साथ पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

साम्राज्य का टेरा फर्मा: प्रवासी श्रम का भूमि, अधिग्रहण और बनाना
-मिथिलेश कुमार

यह अध्ययन भूमि अधिग्रहण, प्रवासी श्रम और शहरी विकास से संबंधित मुद्दों के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करता है। यह नांगल देवत की कहानी के साथ शुरू होता है, जो कि होटल सेंटॉयर के निकट दिल्ली हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक गांव है। पहली नजर में एक गांव , फिर भी जब हवाई अड्डे के विस्तार के लिए समय आया, तो गांव ने उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जो समुदाय, स्वामित्व और व्यक्तिगत विषयों की धारणा को चुनौती देंगे।

1972 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए नांगल देवट को अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। हवाई अड्डे के पास एक और गांव रंगपुरी पर्वदी के पास उनके जमीन खोने वालों के लिए वैकल्पिक भूखंड प्रदान किए गए थे। जो भूखंड मुआवजे की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया था, वह निम्नानुसार है:

क्रमांक	ग्रामीणों द्वारा आयोजित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	एएआई (AAI) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	0-32	26
2	33-48	40
3	49-80	64
4	81-100	90
5	101-140	100
6	141-180	160
7	181-250	200
8	251-350	250
9	351-550	350
10	551-800	450

11	801-1500	550
12	1500 and above	650

यह आंकड़ा 1 972-73 में एक सर्वेक्षण आयोजित करके आ गया था। गांवों में भूमि के विभाजन के औपनिवेशिक स्वरूप के बाद नांगल देवत में पुरानी अबादी (लाल डोरा) के साथ-साथ विस्तारित आबादी क्षेत्र शामिल थे। समस्या यह थी कि हालांकि विस्तारित आबादी क्षेत्र के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड तैयार किए गए थे, पुराने बूढ़ी या लाल डोरा क्षेत्र के लिए कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था। मुआवजे की शर्तें यह थी कि भूमि के भूखंडों को भूमि के भौतिक कब्जे में रखने वाले भूखंडों को भूखंड दिया जायेगा। समस्या यह थी कि ग्रामीणों ने जमीन के अभिलेखों के अनुयायियों का पूरी तरह से पालन नहीं किया बल्कि भूमि रिकॉर्ड रोज़गार में होने वाले रोज़मर्रा के बदलावों को दर्ज करने में विफल रहे। इसने अजीब स्थितियों का नेतृत्व किया क्योंकि रिकॉर्ड फ़ील्ड सर्वेक्षण से मेल नहीं खाएंगे। इस प्रकार, ऐसे अवसर होंगे जहां एक व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण रिपोर्ट में होगा, लेकिन नक्षत्र मंताज़ामिन और इसके विपरीत में नहीं होगा। यहां तक कि जब यह नाम सर्वेक्षण रिपोर्ट और नक्शा मंताजामिन में अलग से सामने आया, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि वैकल्पिक रूप से कोई प्लॉट नहीं उठाया जाता है जो अधोसंरचना के आधार पर नहीं उठा है। दिलचस्प पहलू यह है कि भूमि निर्मित संरचना से कानूनी रूप से अलग है यह एक ऐसा पहलू है जिसे हमें हार्वे की श्रेणी के संदर्भ में निर्मित पर्यावरण का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी, इन मुकदमों का आसान हिस्सा था क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड के बारे में अनोखी बात यह है कि एक व्यक्ति का नाम जमीन के एक टुकड़े के लिए तय किया गया है। सवाल यह है कि हम जमीन और विषयों को समझने के लिए कैसे शुरू करते हैं, जहां विषयों की विशिष्टता से इनकार किया जाता है। यह वास्तव में गांव के दलितों को हुआ है।

सबसे पहले निपटान की कहानी और अंततः नांगल देवत में दलितों के विस्थापन शायद राज्य, नागरिकता, पहचान और श्रम का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी विश्लेषणात्मक संयोजनों में से एक है। यह 1 9 58 में शुरू हुआ, आजादी के एक दशक बाद, जब 122 दलितों को नंगाल देवत में उत्तर-औपनिवेशिक राज्य द्वारा किए गए भूमि सुधारों के प्रोजेक्ट के भाग के रूप में बसाया गया था। उन्हें निवास के लिए भूखंड दिए गए थे लेकिन कृषि या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं। नांगल देवत में बसने वाले चार समुदायों में मकबुजा जुल्लान, माकबुजा चामरन, मकबुजा कुमारर और मकबुजा अहले थे। दिलचस्प पहलू यह है कि जमीन व्यक्तियों को नहीं बल्कि समुदायों को आवंटित की गई थी। उपरोक्त मामले में विपरीत जहां दलितों के मामले में अभिलेखों में जमीन और व्यक्ति का मिलान नहीं हुआ, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। कम से कम बाद में ज्यादा देर तक नहीं। यह बहुत महत्व का है और हम बाद में इसमें आ जाएगा। यह राज्य और विषय को प्रदान करने वाले नागरिकता के बीच के संबंधों के बारे में क्या बताता है? काफी स्पष्ट रूप से, इस मामले में व्यक्तिगत नागरिकता का मुद्दा नहीं उठता है। यह समुदाय था जिसे भूमि दी गई थी। समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं के भीतर कौन और कौन कहां का फैसला किया जाता है इस प्रश्न को गहरी जांच की जरूरत है क्योंकि जाति के मुद्दे शामिल हैं। अगर राज्य एक विशेष जाति समूह को एक 'समुदाय' के रूप में देखता है और इसके कल्याणकारी परियोजना के संबंध में व्यक्तियों को सामाजिक अनुबंध की प्रकृति बदलती है, तो इसके बारे में रूसी समझ से बदल जाता है। वास्तव में, यह हॉब्सियन लेविथान भी नहीं है इसके बजाए, हमारे पास जो राज्य है, वह एक ऐसा राज्य है जो अपने विषयों को अलग-अलग (ऊंची जाति) नागरिकता और संपत्ति के अधिकारों को प्रदान करता है जबकि अन्य नागरिकता से इनकार किया जाता है और पात्रों के अधिकार के अधिकारों के साथ देहाती शक्ति के एक रूप से पूरक है। यह तब तक था जब तक राजधानी की अनिवार्यता एक निर्णायक मोड़ थी और जिस समस्या का सामना करना पड़ा था, वह अब समुदाय से व्यक्ति को निकालना था। जब अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का सवाल उठाया गया तो यह काफी स्पष्ट है कि ऊपरी जातियों के लिए अपनाए गए उपायों दलितों से अलग थे। किसी भी मामले में, तीन

सदस्यीय समिति ने इस मामले को देखे जाने का काम किया, दलितों को मुआवजे के लिए सिफारिशों के साथ आया। 'समिति ने यह विचार किया कि 1958 के रिकॉर्ड को केवल एक द्वितीयक सबूत के रूप में माना जा सकता है और 1 9 58 के रिकॉर्ड में 122 नामों के संबंध में भूमि के कब्जे का पता लगाने के लिए एक नए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।' वैकल्पिक भूखंडों की पात्रता यह थी कि 'सामुदायिक इलाके में 122 व्यक्ति भी जमीन के कब्जे में हों। उनकी मृत्यु के मामले में, उनके एलआर को आवंटित भूमि के कब्जे में होना चाहिए। केवल 1 9 58 में जमीन का आवंटन वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। सामुदायिक इलाके में कब्जे को साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमिक दस्तावेज में 'बिजली बिल आदि' शामिल थे। विस्थापित समिति ने देखा कि वर्ष 1 9 58 में बनाए गए निर्धारण में, भूखंडों को गिने गए थे। हालांकि, तिथि के अनुसार, स्थिति लगभग 50 वर्षों के अंतराल के कारण भिन्न है। इसलिए, यह माना जाता था कि किसी व्यक्ति को केवल कारण ही नहीं मानता है कि वह उसी भूखंड पर कब्जा नहीं कर रहा है। हालांकि, उन्हें केवल सामुदायिक ज़मीन में ही वही खसरा संख्या में कब्जा करना चाहिए। 'दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई समिति द्वारा इन मानदंडों का उद्देश्य' यह सुनिश्चित करना था कि उन लोगों को जो लगातार मालिकाना हो चूंकि 1958 को वैकल्पिक भूखंड दिए जाने चाहिए, क्योंकि वे 50 वर्षों से अधिक समय तक जमीन पर रह रहे थे, जो आईजीआई हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक थे, और उन्हें पुनर्वास करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, जिन व्यक्तियों का नाम 122 व्यक्तियों की सूची में प्रकट हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी भूमि का आदान-प्रदान किया था या फिर इस क्षेत्र से बाहर चले गए थे, वे जमीन के एक वैकल्पिक भूखंड का दावा करने के योग्य नहीं होंगे। इसी तरह, जिन लोगों ने 1 9 58 के बाद समुदाय भूमि में सम्पत्ति अर्जित की थी, वे पात्र नहीं होंगे क्योंकि उन्हें सामूहिक भूमि के मूल आबंटियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है। 'हमें विराम दें और न्यायालय की व्याख्या पर करीब से नज़र डालें कानूनी तौर पर लेकिन गंभीर रूप से अदालत के लिए समस्या संपत्ति का एक कानूनी व्यक्ति बनाने के लिए किया गया था यह एक समस्या थी क्योंकि राजस्व में यह रिकॉर्ड था कि भूमि सामुदायिक भूमि थी। यहां हरिजन और पिछड़ी जाति कल्याण समिति की एक याचिका उच्च न्यायालय के बचाव में आई थी। मूल रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था क्योंकि 'अदालत का मानना था कि इस तरह के समुदायों को वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए जाने चाहिए ... समूह और समूह में शामिल व्यक्तियों के लिए नहीं। यह समूह पर निर्भर करेगा कि इसके घटकों में वैकल्पिक भूमि को विभाजित किया जाए। 'जाहिर है, अदालत अभी तक व्यक्तिगत / नागरिकों को देखने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि, समिति ने एक अलग रिट याचिका दायर की और उपर्युक्त समिति बनाई गई। निर्विवाद राजनीतिक विषय ने नागरिक की स्थिति की मांग की। यह विशेष निर्णय कानूनी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान देने और इसलिए एक नागरिक की ओर पहला कदम था। सर्वेक्षण और बिजली का बिल अंतिम नागरिक आंकड़ा तैयार करेगा जो दलित भी है। नतीजतन: 122 में से 59 व्यक्तियों को एक योग्य नागरिक के नए परिभाषित मानदंडों के माध्यम से गिर गया। इसलिए, अब पूछने वाला प्रश्न यह है कि राज्य सत्ता की संरचना में क्या है जो इसे सबसे अधिक हाशिए पर नागरिकता अधिकारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, भले ही सकारात्मक कानूनी प्रणाली इसके अनुदान के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है? दिल्ली के मुख्य मंत्री के पद के अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अनुसार उत्तर दलितों के खिलाफ भेदभाव है। यह गलत नहीं है क्योंकि सभी 59 लोगों को, जो कि रंगपुरी पहाड़ी में वैकल्पिक भूमि नहीं आवंटित किए गए थे, समिति द्वारा उल्लेखित मानदंडों के अलावा अन्य कारणों से खारिज कर दिया गया था। दलितों और गैर-दलितों के मामले में मुकदमों की प्रकृति में अंतर को ध्यान में रखना काफी दिलचस्प है। ऊंची जाति आवंटियों के ज्यादातर मामलों में मुकदमेबाजी मूल के अनुरूप आबंटित जमीन के आकार के बारे में है। यह एक कारण है कि भूमि और अधिरचना के बीच विश्लेषणात्मक अंतर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि में सबसे ज्यादा बदलाव भूमि या भूमि के अतिक्रमण को खरीदकर निर्मित अधिरचना के माध्यम से किया गया था। दलितों के मामले में जमीन का सादे और सरल प्रश्न। फिर भी यह स्पष्टीकरण का एकमात्र हिस्सा है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि जमीन के आसपास रोजमर्रा की जिंदगी शायद ही कभी भूमि के रिकॉर्ड या संपत्ति के लिए अन्य राज्य के उपरांत का पालन करती है। सुविधा के मुताबिक दलितों द्वारा अक्सर भूमि का आदान-प्रदान किया जाता था। उनके लिए संपत्ति के रूप में भूमि या जमीन तय नहीं हुई थी। यह उस राज्य से भूमि का एक अलग दृष्टिकोण है जो हमेशा इसे ठीक करना और उसे दस्तावेज बनाना चाहता है। एक तरल भूमि प्रभु की शक्ति के

दर्शन के लिए एक चुनौती है, जिसके लिए एक फर्म और फिक्स्ड जमीन की आवश्यकता है, टेरा फ़ारमा। यह भूमि की यह स्थिरता है जो राज्य को अपवाद की अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। वास्तव में, भूमि वह राजनीतिक इकाई है जहां राज्य का उपयोग करने वाली प्रमुख शक्ति एक अपवाद है। विस्थापन, विध्वंस, निष्कासन आदि केवल अपवाद की संप्रभु शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण की आयु और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध राज्य निकायों की वृद्धि में यह राज्य द्वारा अपवाद की शक्ति का अंतिम अभिव्यक्ति है। दलितों के अभ्यास ने राज्य शक्ति के इस अभियान को चुनौती दी। ज्यादातर दलित हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से हवाई अड्डे के गोदाम में कुलियों के रूप में काम करते थे, जबकि ऊंची जाति ने ज्यादातर टैक्सियों का संचालन किया था या हवाई अड्डे से सामान ले जाने वाले रसद कारोबार में थे। दलित सामूहिक श्रम थे वे अभी भी हैं लेकिन अब उन्हें प्रवासी मजदूरों की स्थिति भी मिली है। यह अध्याय, कुछ इंद्रियों में, श्रमिक श्रम की जीनोलॉजी प्रदान करता है। श्रमिक श्रम बनाने के लिए इसे सत्ता के प्रभु, पशुधन और जैविकता के जटिल परिसर की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस श्रम को पूंजी के लिए उपयुक्त रूप से उपयोगी होने के लिए निश्चित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे मोबाइल रखा जाना है। इसे आरक्षित सेना में बदला जाना चाहिए लेकिन यह अब पर्याप्त नहीं है। श्रम की एक स्थायी आरक्षित सेना बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे न केवल शारीरिक रूप से या काम के संदर्भ में बल्कि पहचान, नागरिकता, विषमता, गैर-अधीनता के संदर्भ में भी स्थानांतरित करना होगा। शासन की कला इस आंदोलन को विनियमित करने में है। एक यह भी कह सकता है कि शासन वास्तव में राज्य का साजिश है।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

दिल्ली के 'सर्विस' गांवों में काम करने और प्रवासी श्रमिकों के जीवन के 'क्षणिक' रूप -इशिता दे

दिल्ली के शहरीकरण के 'सेवा' गांवों की यह नृवंशविज्ञान पढ़ना, प्रवासी महिलाओं के कार्यकर्ताओं के जीवन से है जो दिल्ली की 'देखभाल' अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। यह अध्ययन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र में तीन साइटों (गुड़गांव, नई दिल्ली में गौतमपुर पुनर्वसन कॉलोनी और फरीदाबाद में एक डेरा) में प्रवासियों के जीवन पर आधारित है। प्रवासियों के गतिशीलता के रुझान को समझने के लिए माइग्रेशन के जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से माइग्रेशन प्रवृत्तियों में प्रवासन की लिंगीय प्रकृति दिखाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में जनगणना प्रवास तालिका और प्रवास आंकड़ों पर करीबी नज़र रखने वाले मौजूदा अध्ययनों से पता चलता है कि 1993 और 2007-2008 के बीच ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के लिए महिला प्रवास की दर में वृद्धि हुई है। हालांकि विवाह से प्रवासन राज्य प्रलेखन में आंतरिक प्रवास के व्यापक कारण है, अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि ज्यादातर महिलाएं ने श्रमिक बल में शामिल हो गई हैं। एसोसिएटेड प्रवासन विभिन्न रूपों को ले सकता है और अक्सर महिलाओं और बच्चों को ऋण चुकाने के लिए 'सहायक घरेलू दासता' का हिस्सा बन जाते हैं ऋण चुकौती और घरेलू दासता को जोड़ने वाली यह टिप्पणी हमें यह समझने की अनुमति देती है कि काम और श्रम के लिंग के आधार पर महिलाओं के जीवन पर कैसे प्रभावित होता है जो पति, परिवार या यहां तक कि स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। संबंधियों को संदर्भित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रवासी महिलाएं शहर के कभी विस्तारित 'सेवा' गांवों में अपने जीवन का आयोजन करती हैं।

राजरहाट न्यू टाउन के उपग्रह क्षेत्र के मौजूदा इलाकों के मौजूदा गांवों को देखने के लिए, मैं 'सेवा गांव' के विचार से एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में उधार लेता हूं कि 'शहर' का उत्पादन सेवाओं के समूह पर आधारित है। जो एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बचे हुए नहीं हैं बल्कि इसके बजाय 'अधिशेष मानवता' के 'आवासीय खजाने' द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में सेवा गांव, यह समझने के लिए एक एवेन्यू प्रदान करते हैं कि इसके प्रशासनिक विशिष्टताओं के बावजूद पुनर्वास कॉलोनियों, डार और झुग्गी बस्तियों में आम धागा साझा है। इसके बसने वाले प्रवासियों और प्रवासी श्रमिक हैं जो कई निपटान साइटों - झुग्गी, पुनर्वास कॉलोनियों, डेरस और गैरकानूनी घाटियों में रहते हैं और वे 'शहर' जीवन के साथ बातचीत करने के लिए इन साइटों के बीच भी जाते हैं। मैं शहरी प्रवासियों, अंतर राज्य प्रवासियों या अंतरराज्यीय प्रवासियों के लिए शहरीकरण का आकार समझने के लिए 'सेवा' और 'गांव' के विचार को लाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं खुद को दिल्ली के शहरीकरण की सीमाओं के भीतर सीमित कर देती हूं और शहर के प्रवासियों के साथ संघर्ष और प्रवासियों ने शहर के स्थानिक संगठन को समझने के लिए एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की है । साथ ही साथ 'सेवा गांव' का विचार मलिन बस्तियों, पुनर्वास कॉलोनियों और रहने की अन्य जगहें हैं कि लोगों को शहर के रिक्त स्थान के संबंध में अपने दैनिक जीवन में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यद्यपि इन श्रेणियों में से प्रत्येक- झुग्गी बस्ती, पुनर्वास कॉलोनियों, डेरा प्रशासनिक श्रेणियों के रूप में दिल्ली के जीवित अनुभवों के अधिकार और अधिकारों के अपने विशिष्ट सेट हैं,

इसके परिधीय स्थान मोबाइल आबादी इन जगहों पर बसने के लिए अनुमति देता है क्योंकि वे शहरों में कदम रखते हैं।

शहर के स्थानिक संगठन हमेशा 'सेवाओं' के आसपास आयोजित किए गए थे, और शहर की सर्विसिंग के किनारे पर हमेशा शहर की दीवारों के बाहरी इलाके में स्थित थे। दिल्ली के 'दीवारों वाले शहर' पर ऐतिहासिक लेख भी सार्वजनिक भूमि पर बैठने के साक्ष्यों के साथ छापे गए हैं। स्वतंत्र भारत के बाद जब एड्रियन मेयर को शामिल किया गया था, उन्होंने दिल्ली को एक महानगरीय क्षेत्र और एक संसाधन क्षेत्र के क्षेत्र मे एक क्षेत्र की कल्पना की थी। इस क्षेत्र की योजना के दौरान मुख्य संघर्षों में से एक शहर की चुंबकीय शक्ति और महानगरों के प्रति प्रवासी पैटर्न था - किसी भी शहरीकरण और दिल्ली के एक अंतर्निहित आयाम एक अपवाद नहीं है।

हालांकि प्रवासी मजदूरों और उनकी जरूरत को शहर के कामकाज में पहचाना गया था, लेकिन प्रवासियों के आवास एक विवादास्पद बने रहे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि परिधीय शहरों में रहने की कम लागत का मतलब होगा कि प्रवासी मजदूर छोटे शहरों में अपने आवास पर वापस जाकर काम करेंगे और वास्तव में पड़ोस के गांवों से मोदीनगर तक काम करने वाले श्रमिक साइकिल चालन के उदाहरण तुलना की बात हैं। उस समय की एक और ज़रूरत थी जहां से प्रवासियों ने काम करने के लिए स्थानों पर बदलाव शुरू किया था। दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि की प्रत्याशा में दो उपाय ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के लिए प्रस्तावित किए गए थे। शरण ने निष्कर्ष निकाला कि औपनिवेशिक शासन और पहली मास्टर प्लान के काउंटर मैग्नेट के तहत दोनों विस्तार कार्यक्रम अपने तरीके से असफल रहे। वे असफल रहे, क्योंकि शहरी और ग्रामीण और 'प्रवासी' और 'ग्रामीण' के बीच एक तीव्र ध्रुवीकरण था 'योजनाबद्ध शहरी काल्पनिक' के भीतर बहुत कम जगह मिली। प्रवासियों और उनकी जिंदगी की साइटों को एक खतरा या एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है और जब शहर प्रवासी पर निर्भर था, तो उनके पास शहर में प्रवासियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। प्रवासियों के राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में चुनौतियां- मतदान अधिकारों की संख्या में बड़ी संख्या में मोबाइल आबादी उछाड़ रही है जो दर्शाती है कि क्षेत्रीय जड़ें के आसपास नागरिकों के राजनीतिक अधिकार कैसे बनाए जाते हैं। प्रवासियों के जीवन में इसके प्रभाव ने स्थलीय राज्यों से पहचान पत्र पेश करने और राजस्थान के अजीविज्ञान ब्यूरो की पहल के लिए प्रवासी मजदूरों के समूह को मजबूर कर दिया है। राजस्थान में स्थित आजीविका ब्यूरो द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, इसके सदस्यों के बीच श्रम मंत्रालय और राजस्थान के रोजगार मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रवासी घरेलू श्रमिकों के आयोजन करने वाले अधिकांश संगठन पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता महसूस करते हैं क्योंकि एनसीआर के भीतर गेट किए गए आवासीय समुदायों में भी पहचान पत्र जारी करने के प्रावधान हैं, जिन्हें नियमित अंतराल के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है। इस तरह की पहल उन प्रवासी मजदूरों को संगठित करने के लिए सामूहिक प्रयासों को दिखाती है जो परिजनों को व्यक्तिगत रूप से, परिजनों या रोजगार एजेंसियों के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। विवाह से संबंधित प्रवासन महिला प्रवासन पर साहित्य में एक विशेष उल्लेख के योग्य है और एक महिला प्रवासी मजदूर के जीवन पाठ्यक्रम में सूचित 'शादी से प्रेरित प्रवासन' की स्तरित जटिलताओं को दर्शाता है।

मैं तर्क करती हूं कि एक प्रवासी के जीवन में काम की प्रकृति 'क्षणिक' है और महिलाओं के लिए श्रम बाजार में प्रवेश घर-आधारित काम के माध्यम से होता है और शहर-आधारित देखभाल अर्थव्यवस्था की मांग महिलाओं की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तीन साइटों में उदाहरण के लिए, गौतमपुर पुनर्वास कॉलोनी से पूनम कहती हैं की, गौतम नगर के अधिकांश परिवारों की तरह, वे भी प्रवासियों में से थी । उसके माता-पिता लखनऊ से थे और जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता ने लखनऊ छोर दिया और बहार निकल परे। पूनम का पालन पोषण और शादी गौतम नगर में ही हुई । उसके पिता एक एम्बुलेंस चालक के रूप में काम करते थे और उसकी माँ ने घर आधारित काम किया था। उसने शादी के बाद काम करना शुरू कर दिया। पूनम अपनी शुरुआती तीसवां दशक में है और और मुझसे कहती है की शादी और तीन बच्चो के पालन पोषण के दौरान उसने सात नौकरिया बदली है । जब मैंने उनसे साक्षात्कार किया तो वह क्षेत्र के कामकाजी माताओं के लिए क्रैच (creche) खोलने के लिए अपने पैसे

को अलग कर रही थी । गौतमपुर की पुनर्वास कॉलोनी में जाने के बाद जब गौतमनगर में झुग्गीस को ध्वस्त कर दिया गया तो उन्हें विध्वंस के फिसलकर घरों को आवंटित किया गया और इसने पुनर्वासित क्षेत्र में सामुदायिक भावना का नुकसान हुआ। मैं उससे पूछता हूं कि अगर उनके पुनर्वास के बाद काम की प्रकृति बदल गई है। सुमन और निर्मला दोनों को सर्वसम्मति से कहते हैं, 'नहीं'। सुमन आगे बताती है , 'एक औरत के लिए देखें जो शहर में पहली बार कदम रखी है और नौकरी की जरूरत होती है तो घर पर काम करना पसंद करते हैं। लोग कोठियों में काम करने को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि आपका नियोक्ता एक महिला है कोठी में काम करना घर पर काम करते हुए समानता की वजह से ज्यादा स्वीकार्य है। निगरानी के लिए लगातार कोई व्यक्ति होता है और ज्यादातर मामलों में, यह महिलाएं हैं, इसलिए यह पहला काम बन जाता है '। निर्मला कहती है , 'मैं एक मंगल हूं। हमारा पारंपरिक व्यवसाय कचरे का संग्रह है । अब तक, मैं गौतम नगर की यात्रा करती हूं। मैं गौतम नगर जाने के लिए एक वैन लेती हूं और कचरा एकत्र करती हूं। ज्यादातर महिलाएं कामवाली, बेलदार, क्युरवली और कबीडीवली के रूप में काम करती हैं ' तो मैंने पूछा , 'क्या पूनम अपवाद है?' वह कहती है, 'मज़बूरी में सब कुछ करना परता है '।

यह इस संदर्भ के खिलाफ है कि मैं 'अंतरंगता' और अंतर-स्थान की प्रकृति की भूमिका को देखने का प्रस्ताव देती हूं, जो कि घर आधारित कार्य या देखभाल अर्थव्यवस्था में महिलाएं मौजूद हैं। इस अंतरंगता का मकसद जरूरी नहीं है कि चुनाव में बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता के कारण घरेलू अवकाश में घरेलू श्रमिकों के लिए इस्तेमाल किए गए पते के संदर्भ में फॉक्टिव कनन संबंधों के गठन के जरिए शोषण के कई स्तरों की ओर जाता है। फिर भी देखभाल की अर्थव्यवस्था और गृह आधारित कार्य के श्रम बाजार में प्रवासी महिलाओं के प्रवेश के लिए अंतरंगता का यह चरण महत्वपूर्ण है। नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में अंतरंगता की भूमिका साहित्य में अध्ययन का विषय रहा है और वैश्विक पूंजीवाद में सामाजिक जीवन में अंतरंग अंतरंगता के अनुकूलीकरण में प्रवासी मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय गेंडेड नेटवर्क में पूछताछ का विषय रहा है। दूसरे शब्दों में, 'अंतरंगता', एक सामाजिक संदर्भ में समझने की जरूरत है और काम की साइट इस छात्रवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु बन जाती है। यह जाति में स्पष्ट है कि रोज़गार की जगहों पर भेदभाव किया जाता है, रसोई घर के 'अंतरंग' काम स्थलों में उच्च / निम्न और शुद्धता और प्रदूषण के लगातार उत्पीड़न। अंतरंगता का कार्य अंतरंग मजदूरों का गठन करता है और अंतरंग और श्रम को जोड़ता है क्योंकि अमूर्त शो हमें काम से घर को अलग करने और अनुत्पादक श्रम से उत्पादक को अस्वीकार करने की इजाजत देता है। यह 'शारीरिक और घरेलू, व्यक्तिगत और पारिवारिक रख-रखाव और यौन संपर्क या संपर्क रखने सहित कई गतिविधियों को समझने की अनुमति देता है और सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से' श्रम के क्षणिक रूप 'को समझने में हमारी मदद करता है कि ये प्रवासी महिलाएं अपने जीवन में पारगमन में करती हैं।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

अनुसंधान संक्षेप
धारा 3: मुंबई

मुंबई में बेघर प्रवासियों: शहरी जगह में जीवन और श्रम
-मनीष झा और पुष्पेंद्र

वर्तमान नीति संक्षेप में मुंबई शहर में प्रवासियों की जीवन और स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। प्रवासियों, जो शहर के विकास में मानव संसाधन के प्रमुख घटक हैं, उनकी आजीविका के लिए शहरी गंतव्य महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण से शहरी इलाकों में श्रमिक प्रवास भारत जैसे विकासशील देशों की एक सतत विशेषता है। मुंबई, जिसे अक्सर विश्व-शहर कहा जाता है, देश भर से बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित कर रहा है। शहर में कानूनी आवास सम्पत्ति सम्बन्ध में प्रवेश करने में असमर्थ, प्रवासियों को सार्वजनिक स्थान पर जैसे फुटपाथ, सड़क के किनारे, या कार्यस्थलों पर, या सभी प्रकार के आश्रयों में मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है एक घर कहा जाने योग्य वे 1987 में बेघर हो गए लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शरण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए परिभाषा के अनुरूप हैं, बेघर व्यक्ति को देखते हुए, न केवल कोई व्यक्ति जो सड़क पर या आश्रय में रहता है, लेकिन यह उतना ही हो सकता है जिसका आश्रय या आवास स्वास्थ्य और मानव और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी मानदंडों को पूरा करें। इन मापदंडों में कार्यकाल की सुरक्षा, खराब मौसम और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति संरक्षण, साथ ही सेनेटरी सुविधाएं और पेयजल, शिक्षा, काम और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। मुंबई में साइटों के मामले के अध्ययन के माध्यम से, नीति संक्षेप बेघर, असुरक्षा और सटीकता के अनुभवों को बताती है।

11.97 मिलियन की कुल आबादी में से, 5.18 मिलियन या मुंबई की 47.3 प्रतिशत आबादी को 2001 की जनगणना में प्रवासी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रवासी मुख्य रूप से पूरे देश से ग्रामीण मूल से हैं, जो सभी प्रवासियों के दो-तिहाई से तीन चौथाई का गठन करते हैं। अधिकांश प्रवासियों को अकुशल या निपुण कुशल और नौकरानी या छोटे नौकरियों में फिट होते हैं या वे नियोजित हैं। मुख्य रोजगार प्रदाता की अनौपचारिकता बढ़ाना, सेवा क्षेत्र, इस क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आधे से अधिक रोजगार प्रवासियों द्वारा किया जाता है कम आय और गरीबी को आगे बढ़ाए जाने वाले आवासों और सस्ते आवास की आपूर्ति की कमी की वजह से, प्रवासियों को मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, कई मामलों में अवैध / अनधिकृत, 2001 में मुंबई की आबादी का 54 प्रतिशत भयावह परिस्थितियों में झुग्गी बस्तियों में रहता था, जो शहर के कुल भूमि क्षेत्र का सिर्फ 6 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना में बृहत्तर मुम्बई में 11, 771 एचएच का आंकड़ा 39,074 की आबादी है। इसके अतिरिक्त, मुंबई शहर और मुंबई उपनगरों में बेघर एचएचएस की संख्या अनुक्रमे 7,184 और 4,591 थी, जिसमें 24,000 और 15,074 की आबादी थी। यह संभावना है कि असहाय आबादी को एन्यूमरेट किया गया है, और यह भी थोड़े समय के लिए अस्थायी प्रवासियों के लिए भी सच हो सकता है। शहर में बेघर आबादी के अनौपचारिक अनुमान ने इस आंकड़े को 1.5 लाख व्यक्तियों में डाल दिया।

1991 में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की विशेषता नवप्रवर्तनशील आर्थिक नीति पेश की गई, तो यह भी शुरू हुआ कि ग्रेटर मुंबई के लिए एक नया शहर विकास योजना शुरू की गई। इस योजना ने मुंबई में

नवउदारवादी शहरीकरण को और मजबूत करने की मांग की। दूसरी बातों के साथ, उदारवादी फर्श स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) ने पहली बार औपचारिक रूप से हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को बाजार आधारित योजना उपकरण के रूप में पेश की और पूर्व औद्योगिक इकाइयों की भूमि के पुन: उपयोग की अनुमति दी। झोपड़ी पुनर्विकास और झोपड़ी पुनर्वास टीडीआर से निर्माण और ढांचागत परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक भूमि मुक्त करने के लिए जुड़ा था, जिससे राज्य को गरीबों के लिए आवास की ज़िम्मेदारी और मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास से मुक्त कर दिया गया। इस योजना ने शहर से उत्पादन गतिविधियों को बाहर ले जाने और झुग्गी बस्तियों से शहर को मुक्त करने के द्वारा मुंबई की विघटन की कल्पना की। विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाओं - मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) और मुंबई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना (एमयूआईपी) के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेदखली और झोपड़पट्टी निवासियों के स्थानांतरित होने की वजह से हजारों बेघर लोगों को भी प्रदान किया गया। 2001 के स्लम अधिनियम ने उन झुग्गी निवासियों के दावों को अवैध रूप से बेदखल किया जो 1995 के बाद से झुग्गी बस्तियों में चले गए हैं। 2007 में सरकार ने शहरी भूमि छत अधिनियम को रद्द कर दिया, जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत धन की शर्त थी। 2005 में, आवास और रियल एस्टेट में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। बुनियादी सामाजिक सेवाओं का तेजी से निजीकरण हो चुका है और नगर निगम के कई कार्यों से बाहर निकाले गए हैं। कई और अधिक सुधार कार्ड पर हैं जैसे कि तटीय क्षेत्रों में बदलाव और भाड़े नियंत्रण अधिनियम को रद्द करना। 2003 में मैककिंसे एंड कंपनी द्वारा तैयार एक वैश्विक परामर्शदाता फर्म मैकेंसे एंड कंपनी द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज 'विज़न मुम्बई: वर्ल्ड-क्लास सिटी में ट्रांसफ़ॉर्मिंग मुंबई' के बाद, राज्य सरकार ने न केवल इसकी स्वीकृति दी बल्कि मुम्बई परिवर्तन के लिए मुंबई ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट 2003 के साथ भी बाहर आया। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, नागरिकों के अनुकूल सेवाओं और व्यापार-अनुकूल वातावरण के साथ एक 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र' में यह अनुमान है कि 10 वर्षों में 40 अरब डॉलर (लगभग 1,82,600 करोड़ रुपये) खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 75 फीसदी निजी निवेश के रूप में आने की संभावना थी। विजन मुंबई ने झुग्गी पुनर्विकास पर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए लगभग 60 प्रतिशत जमीन मुक्त करने के लिए जोर दिया। सरकार ने झुग्गियों के विध्वंस पर शीघ्र ही प्रारंभ किया। 2004-05 में, 90,000 से अधिक झुग्गी इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया था। तब से मलिन बस्तियों का आवधिक विध्वंस एक नियमित घटना है। अगर 1995 के कटऑफ़ की तारीख मानदंडों की पूर्ति हुई तो विस्थापित परिवारों को 225 वर्ग फीट क्षेत्र में रहने वाले मकान-शैली वाले अपार्टमेंट ब्लाकों के घनी पैक वाले समूहों में पुनर्वास किया गया, जो शहर के परिधि में मार्शल मैदानों में उगने वाले हैं; मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ लोग खुद को बेघर समझते हैं अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच आवास के अधिकार को स्पष्ट रूप से एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 'जीवित रहने के पर्याप्त स्तर' के पहलुओं के रूप में, यह मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (आईसीईएससीआर) के अंतरराष्ट्रीय नियमों में निर्धारित है। यह नीति संक्षेप में मुंबई में प्रवासियों के बेघर होने के मुद्दे पर राज्य और नागरिक समाज द्वारा की गई बेघर की राजनीति की पृष्ठभूमि में एक अनुभवजन्य काम के माध्यम से दिखाई देती है। हमने हिंसा, निष्कासन, असुरक्षा, गोपनीयता की कमी, आजीविका और विभिन्न स्थलों पर आयोजित साक्षात्कारों के आधार पर आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष से संबंधित मुद्दों से अर्थ प्राप्त करने का प्रयास किया है।

बेघर प्रवासियों ने शहर के रिक्त स्थान के विखंडन और अलगाव के माध्यम से शहरीकरण के विरोधाभास का पर्दाफाश किया। 1990 के दशक के शुरूआती दौर में आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप, भारत में मध्यम वर्ग का हिस्सा उनकी आर्थिक संपदा का विस्तार कर सकता है, सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकता है और राजनीतिक क्षेत्र में दावा-निर्माण बढ़ा सकता है। अधिक बार नहीं, नए नागरिकता प्रवचन की विशिष्टता के बारे में अभिव्यक्ति को नागरिक समाज के प्रभावशाली अनुभाग द्वारा जोर दिया गया है जो खुद को नागरिक समूह के रूप में कहते हैं। मध्यम और समृद्ध वर्ग के पड़ोसियों के साथ इस तरह के समूह बेघर, फेरीवाला आदि को विस्थापित करके और जमाराशियों के नए नियमों को छोड़कर सार्वजनिक स्थान पर दावा और पुन: दावा करते हैं। निर्वासन और विस्थापन के पहलुओं, असुरक्षा का अनुभव, अपमान, संरचनात्मक हिंसा और नागरिकता को

रोकना और विवादित राजनीति और इसके आस-पास का अभ्यास चर्चगेट स्टेशन के निकट क्रॉस मैदान पर बेघर प्रवासियों के निम्नलिखित मामले में हमारा ध्यान केंद्रित है।

ग्रेटर बॉम्बे की 1991 संशोधित विकास योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने व्यायाम / जिमखाना, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन मैदान, खेल का मैदान, उद्यान और पार्कों के लिए गोद लेने / देखभाल करने वाले आधार पर आरक्षित भूखंड देने की नीति तैयार की है। 2004 में नागरिक शहरी विरासत संरक्षण समिति (एमयूएचसीसी) ने शहर आधारित एनजीओ ओवल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत 5 एकड़ जमीन की पुनर्स्थापना योजना को मंजूरी दी थी, जो कि वर्डेंट एंबियंस एंड लैंड के लिए संगठन है। आखिरकार 28 जून 2010 को मैदान में एक मनोरंजक पार्क में जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेल क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के पेड़, फूलों, पीने के पानी का फव्वारा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंच के साथ मैदान में परिवर्तित करने के लिए मैदान खोल दिया गया। कई शहर के आर्किटेक्ट, इतिहासकार, उच्च प्रोफ़ाइल वाले नागरिक, विरासत कार्यकर्ता, पर्यावरणविदों और सार्वजनिक अंतरिक्ष जेहादियों के साथ मीडिया ने 'जनता' के लिए मैदान का उद्घाटन मनाया। हालांकि, मैदान को उन झोपड़ियों और हॉर्स से मंजूरी देनी होती थी जिन्होंने 40 साल से अधिक समय तक इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था (2003 में, मुंबई हाईकोर्ट ने क्षेत्र को नो-हॉकिंग क्षेत्र घोषित किया था)। उनमें रजनी भी शामिल थी, जो कि कई अवैध अतिक्रमणियों में से एक था, जिन्हें मैदान से बाहर निकाल दिया गया था। आज तक जारी होने वाली उसकी कठिनाई को याद करते हुए, रजनी ने प्रवासियों के अनुभव के जरिए नागरिकता की समस्या को उजागर किया। वर्ष 2006 में जब उन्हें कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार उन्हें अन्य जगह पर आश्रय प्रदान करेगी। अपने भाई समेत कुछ परिवारों को, पुनर्वास योजना के तहत मानखुर्द में घर मिला, जो एक गैर सरकारी संगठन स्प्रैकर द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। रेलवे कार्यालय का सामना करने वाले मैदान के साथ फुटपाथ उस समय खाली था जब उन्होंने कब्जा कर लिया था। ओवल ट्रस्ट के सचिव को लोहे की रॉड के साथ अतिक्रमण के रूप में पॉलिथीन का बांधना भी माना जाएगा और कई बार पुलिस या बीएमसी को फोन किया जाएगा, उनकी स्थिति पर दया दिखाने के लिए उनकी याचिका को बंद कर दिया जाएगा।

शिवजननगर झोपड़ी एम-ईस्ट वार्ड (इस वार्ड में 77.5 प्रतिशत आबादी झुग्गी बस्ती में रहते हैं) के अंतर्गत आता है और यह evctees, विस्थापित और पुनर्स्थापित द्वारा हिचकते हैं, जिसकी प्रक्रिया 1 9 75 के बाद से भिन्न चरण में हुई थी। एक बड़ा शहरी विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की श्रृंखला में पश्चिमी पड़ोसियों के शहरी क्षेत्रों में कई और नरीमन प्वाइंट के शहर के वर्तमान वित्तीय जिले में ध्वस्त हो गए हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बेदखली से पुनर्वास के निशान कठिन और जटिल था। शहरी परिधि के रूप में पहचाने जाते हैं, यह क्षेत्र देवनार डंपिंग ग्राउंड के दलदल की सीमा पर स्थित है, शहर का सबसे बड़ा खुला कूड़ा निपटान स्थल। डंपिंग ग्राउंड हर रोज हजार टन कचरे के शहर को राहत देता है और ऐसे कई लोगों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में काम करता है जो राग बीनने वाले के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, शहर का वध घर यहां भी स्थित है। झुग्गी बस्तियों के साथ-साथ, ऊपर वर्णित गड़बड़ी क्षेत्र से परे विशाल दलहन इलाके में प्रवासियों और विस्थापित परिवारों के एक बड़े खंड में रहने के लिए शुरू हो गया था 'इंदिरा नगर' के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र देवनार डंपिंग ग्राउंड के निकट है और इसे 'अवैध निपटान' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों सहित इंदिरा नगर के निवासियों, कचरा छंटनी कर रहे हैं और साल के लिए रेग चयन में लगे हुए हैं। दलदली भूमि और कचरे के ढेर के बने अस्थायी आश्रय में तिरपाल शीट, टिन रंगों, भीड़ और गंदे लेन, बह निकलने वाली नालियों और डंपिंग ग्राउंड से दबाना मुश्किल है। इलाके और निवासियों के जातीय साहित्य, शुद्धता और काम और आवास, अनौपचारिकता और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी गैरकानूनी और असुरक्षा और अपमान के अनुभवों का असुरक्षित विवरण प्रदान करते हैं जबकि 'अन्य' के साथ बातचीत करते हैं। वास्तविकता के आदी हैं कि साल में कम से कम तीन बार बीएमसी द्वारा उनकी आश्रय को बुलडोज़्ड और ध्वस्त कर दिया जाएगा, नृवंशविज्ञान लोगों के संघर्ष, धैर्य, दृढ़ता, वार्ता और दृढ़ता को दर्शाता है। कचरे के माध्यम से छीनने के दौरान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में चीर लेने के द्वारा उगाही की बेदखली और आजीविका के अनुभवों का लगातार भय। एम-ईस्ट वार्ड की शहरी परिधि में

भी शामिल नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र जो इसके न्यून विकास और मुंबई में सबसे कम एचडीआई के लिए कुख्यात है, इंदिरा नगर ने शहर में प्रवासी आबादी की गरीबी और सीमांतता का प्रतीक रखा है।

शफीना, अपने चालीस वर्ष की शुरुआत में एक मुस्लिम, अपने पति, छोटे भाभी और पांच बच्चों के साथ इंदिरा नगर के सबसे दूर अंत में रहता है। वयस्क सदस्य दैनिक मजदूरी मजदूरों के रूप में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जो अक्सर डंपिंग ग्राउंड में चीर उठा द्वारा पूरक होते हैं। उसकी आश्रय, 10 x 12 फुट का एक कमरा पतली टिन शीट से बनाया गया था - दीवारों और छत - हल्के लकड़ी के साथ संरचना का समर्थन करता है। एक टिन का दरवाजा अभी तय करना था। आश्रय में कोई बिजली नहीं थी क्योंकि पक्की छत घर में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की शर्त है। उसके सामान - कुछ ख़राब अवस्था में बिस्तरे , एक बड़ी चटाई, एक केरोसीन तेल स्टोव, कुछ एल्यूमीनियम बर्तन, पानी के भंडारण के लिए दो बड़े जेरी के डिब्बे, एक बाल्टी, एक एयर बैग और एक सूटकेस और कुछ कपड़े - आश्रय में लापरवाही से बिखरे हुए थे । आश्रय के एक कोने में जल और खाना पकाने के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया गया था और दूसरा बर्तन धोने और शायद स्नान करने के लिए। अधिकांश घरेलू काम सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं क्योंकि इस तरह के घर में मध्यवर्गीय घरों के विपरीत सीमित उद्देश्य हैं। हालांकि, गोपनीयता का व्यावहारिक रूप से सीमित अर्थ है क्योंकि अन्य सभी परिवार भी समान स्थितियों में रहते हैं। उसके बच्चे अकसर बीमार होते हैं, खासकर श्वास लेने की समस्या; डॉक्टर का कहना है कि यह धुएं से भरा वातावरण है और जगह बदलने की सलाह देता है। झुग्गियों में या सड़कों पर रहने वाले अधिकांश अन्य लोगों की तरह उन्हें भी आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसे विभिन्न पहचान प्रमाण मिलते हैं। शफीना इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़े हैं। आस-पास और कई दशकों तक झुग्गी निवासियों का समर्थन करने का इतिहास। एक नगर निगम द्वारा संचालित टैंकर से उन्हें फीस के लिए पानी मिलता है। आस-पास के निजी शौचालय की सेवा हर एक उपयोग के लिए 2 रुपये लेती है। केवल वयस्कों शौचालय सेवा का उपयोग करते हैं, बच्चों को खर्चों को बचाने के लिए खुले में शौच करने की अनुमति है स्थानीय स्तर पर इसकी आवृत्ति के कारण, अस्थायी झुग्गी के विध्वंस के बारे में भय और चिंता स्पष्ट है। शाफीना ने बताया कि सरकार ने पहले लोगों को दलदली भूमि में भरने के लिए और भूमि को पुनः प्राप्त करने के बाद और लोगों को अपने आश्रयों में डाल दिया, तो बीएमसी भूमि पर नियमित एंटीक्रोचमेंट ड्राइव चलाता है। अनुष्ठान एक वर्ष में दो से तीन बार आयोजित किया जाता है जिसमें वे जाली और खुदाई मशीन (लोकप्रिय जेसीबी कहा जाता है) को शैतान को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो कुछ भी घरेलू सामान जब्त कर लिया जाता है, वह मशीन का उपयोग करके नष्ट हो जाता है और वहां दफन कर दिया जाता है।

डंपिंग ग्राउंड के किनारे रहने वाला पृथ्वी पर सबसे आखिरी चीज है, हालांकि, श्रमिकों के प्रवासी ने अपनी स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है क्योंकि यह जगह कई उद्यमशील गतिविधियों और व्यवसायों का केंद्र बन गया है जो कचरा संग्रह पर आधारित है। डंपिंग ग्राउंड से उनमें से ज्यादातर ने मान लिया था कि उनकी स्थिति में किसी भी परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जाएगी, जब तक कि उनके बच्चे शिक्षा में श्रेष्ठ न हो और साहिब बन जाएं जो दुर्लभ है। वे पीढ़ी के बाद पीढ़ी और समतल परिस्थितियों में सड़ने और एक ही अस्तित्वपरक मुद्दों का सामना करने के बाद देखें।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP73.pdf.

समकालीन मुम्बई में एक समस्या चित्र के रूप में प्रवासी के उदय: हिंसा का इतिहास और न्याय के मुद्दे
-सिमप्रीत सिंह

महाराष्ट्र के अंदर और इस राज्य के बाहर के प्रवासियों ने मुम्बई शहर का आकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है औपनिवेशिक सरकार ने प्रवासन को प्रोत्साहित किया और औपनिवेशिक काल के बाद भी यह जारी रहा। शहर की शुरुआत के बाद से, इसकी वृद्धि - आकार और आबादी के मामले में इन-माइग्रेशन के कारकों की वजह से किया गया है। बॉम्बे ने अपनी प्राकृतिक आबादी के बजाय अधिक से अधिक आबादी को अधिवासियों के साथ-साथ प्राकृतिक विकास और शहर की कामकाजी आबादी में बहुमत हासिल कर लिया। वर्ष 1961 में प्रवासियों का कामकाजी आबादी का 84 प्रतिशत था और 1941 और 1971 की अवधि के बीच शहर के निवासियों के दो तिहाई शहर के बाहर पैदा हुए थे।
प्रवासियों की श्रेणी में विविधता थी जब वे शहर में बसने के लिए आए, जो भाषा उन्होंने बोलती थी, देश का वह हिस्सा थी और उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित थे। महाराष्ट्र के प्रवासियों को मुख्य रूप से कपास वस्त्र मिलों में ध्यान केंद्रित किया गया था जबकि आंध्र प्रदेश के मजदूरों की एकाग्रता निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। गुजरात और मारवाड़ी और सिंधियों के साथ व्यापार और वाणिज्य पर गुजरात का प्रभुत्व रहा। टैक्सी और ऑटो ड्राइव, घर आधारित उद्योग आदि के क्षेत्र में यूपी और बिहार के प्रवासियों ने अधिक महत्व दिया। इसके अलावा, बॉम्बे के व्यापारिक दुनिया ने विविधताएं उतार-चढ़ाव कीं, जिसमें पारसी, बांया और भतिस, बोहरा,यहूदियों, खोज और मेमन सहित गुजरात के कई समुदायों को शामिल किया गया।
बॉम्बे में मुसलमान एक अखंड समुदाय कभी नहीं रहे हैं गुजराती मुसलमान, हैदराबाद के मुस्लिम, महाराष्ट्रीयन मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं और अंत में बंगाली मुसलमान हैं। मेमन उनके व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और गुजरात से बोहरा और खाज जैसी हैं। फिर मालाबारी मुसलमान होटल, चाय के स्टालों और भोजनालयों पर हावी हैं। कोंकणी मुस्लिम परिवारों ने चीन के व्यापार में प्रवेश किया और बहुत पैसा बनाया। उत्तर प्रदेश के अंसारस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मोमिंस परिधान बनाने और बिजली के उत्पादन में लगे हुए हैं और उनमें से कई वस्त्र मजदूरों में कुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमान मजदूरों के रूप में श्रमिक गतिविधियों में व्यस्त हैं। मराठी मुस्लिम विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। अधिकांश मुस्लिम श्रमिक चमड़े के उद्योग, ज़ारी काम और कढ़ाई, बेकरी, परिधान बनाने और सिलाई, गहने बनाने में शामिल रहे हैं। दलितों के बीच, महाराष्ट्र में आने वाले पहले लोग मध्य महाराष्ट्र में नियमित रूप से सूखे की वजह से रोजगार की तलाश कर रहे थे और गांवों की जाति हिंसा से बचने के लिए भी थे। अधिकतर संविदात्मक नौकरियों और अकुशल रोजगार में लगे हुए थे, महाराष्ट्र की अन्य अस्पृश्य जातिओं की तुलना में चमारों और मातंग जैसे महारों का बेहतर संगठित और अधिक मोबाइल था।
माइग्रेशन की प्रकृति ओवरटाइम बदल गई है उदाहरण के लिए, पिछले 50 वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और गुजरात और गोवा की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा, अंतराल जिला प्रवासन में गिरावट इस अवधि के दौरान भी ध्यान देने योग्य है। अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में

प्रवासियों के बीच ग्रामीण आबादी का बड़ा प्रतिशत होता है। 'प्रवासी' की श्रेणी की समझ भी समय के साथ बदल गई है। 'मिट्टी के बेटे' के खिलाफ खड़ा होने पर, प्रवासियों को 'बाहरी लोगों' के रूप में माना जाता है, जो शहर में गलत चीज के लिए जिम्मेदार है; अधिकतर-अधिकतर गाड़ियों से लेकर अपराध दर में वृद्धि। 'प्रवासी' को 'अवैध', 'आतंकवादी', 'शहर के संसाधनों पर बोझ' आदि के रूप में लेबल किया गया है। कागज के समकालीन मुम्बई में एक समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में 'प्रवासी' के उद्भव की प्रक्षेपवक्र, कलाकार-सेना-कारण यह और इसके राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक विनिर्माण केंद्र से शहर के आर्थिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में एक सर्विस सेंटर के लिए।

'प्रवासियों' की श्रेणी की बदलती धारणाओं को समझने के लिए, मुंबई के शहरी विशेषताओं को तलाशना महत्वपूर्ण है। एक बंदरगाह शहर और व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होने से, यह एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित हुआ और फिर हाल के दिनों में वित्तीय गतिविधियों और सेवा क्षेत्र के केंद्र में परिवर्तित हो गया। शहरी गरीबों के व्यावसायिक चरित्र में होने वाली बदलाव का ध्यान देखा जाता है। शहर की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में इन बदलावों को जरूरी और शासन के तरीकों में बुनियादी ढांचागत परिवर्तन और परिवर्तनों के द्वारा समर्थित था। परिवर्तनों में लोगों के विभिन्न समूहों पर उनके सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अलग-अलग हैं, उनकी जाति, धर्म, वर्ग और निश्चित रूप से उनकी पहचान 'प्रवासियों' के रूप में है। जैसा कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र और एक 'विश्व स्तरीय शहर' के रूप में उभर रहा है, मलिन बस्तियों को 'अतिक्रमण' के रूप में देखा जाता है, और झुग्गी निवासियों को 'अवैध', 'अवांछित', 'बाहरी लोगों' के रूप में देखा जाता है। राज्य अपने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से गरीबों का अपराधीकरण कर रहा है। महाराष्ट्र स्लम क्षेत्रों अधिनियम, 1971 की धारा 3 (जेड) (6), जिसे वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था, 1995 के साल के बाद झुग्गी बस्तियों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों के दावों को व्यक्त किया। धारा 3Z-2 (6) कहा अधिनियम का कहना है कि 'मालिक / कब्ज़ाकर्ता या जो एक अनधिकृत या अवैध संरचना का निर्माण कर रहे हैं वह अपराधी का दोषी होगा, दोषी ठहराया जाएगा, उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा तीन साल तक हो सकता है और ठीक है ' महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम ने इस प्रकार 'कट ऑफ़ डेट' की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस के अनुसार, केवल उन झुग्गी निवासियों के पास बेदखली के खिलाफ बचाव और मुआवजे के खिलाफ दावा है, यदि वे साबित करने में सक्षम हैं कि वे उस कट ऑफ तिथि से पहले विशेष स्थान पर रह रहे हैं। इस प्रकार आबादी को दो समूहों में विभाजित किया गया है, जो कट-ऑफ से पहले है और दूसरा कट-ऑफ पोस्ट करता है। वर्ष 1 9 87 में, कट-ऑफ की तारीख 1980 से 1985 तक बढ़ा दी गई थी और 1995 में इसे 19 5 से 1995 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2014 में कहा गया कट ऑफ 1995 से 2000 तक बढ़ाया गया था।

1990 के दशक के बाद से विभिन्न कानूनों के माध्यम से, मुंबई के शहरी जगह में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मिल्स के बंद होने के बाद जगह अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। कुछ 1000 एकड़ जमीन जिस पर मिलों स्थित थे, को कॉर्पोरेट पार्क, शॉपिंग मॉल, सुपर लक्जरी स्टोर, पांच सितारा होटल और शानदार अपार्टमेंट में बदल दिया गया है। अचल संपत्ति की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तथाकथित झोपड़ी विकास की पहल से आया। शहरी अंतरिक्ष के पुनर्गठन, ज़ाहिर है, एक हिंसक प्रक्रिया है जो शहरी गरीबों को हाशिए पर और अपराध करता है। मुंबई या बॉम्बे ऐतिहासिक हिंसक दंगे, विरोध प्रदर्शन और कट्टरपंथी दलित और बाएं आंदोलनों की एक साइट है। दूसरी ओर, शहर के शासन के नाम पर, सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों हिंसा का एक बड़ा अपराधी रहे हैं। शिवसेना जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा के लिए शहर के मुसलमान और दलित विशेष रूप से कमजोर हुए हैं। मुंबई / मुंबई में शहरी प्रक्रियाओं को समझना, इस प्रकार, हिंसा के गहन अध्ययन में ध्यान देना होगा। विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, 'समस्या' के रूप में प्रवासी के निर्माण को देखना महत्वपूर्ण है।

औपनिवेशिक सरकार ने सक्रिय रूप से प्रवासन को प्रोत्साहित किया क्योंकि शहर को नियमित रूप से श्रम आपूर्ति की आवश्यकता है, विशेष रूप से कुशल श्रम। हालांकि, 19वीं सदी के मध्य से, सरकार ने प्रवासियों को 'योग्य' और 'अयोग्य' के रूप में अलग करना शुरू किया, जिसे बाद में 'प्रदूषणकारी', 'विदेशियों' या 'भिखारी' के रूप में वर्णित किया गया। इसके अलावा आजादी के शुरुआती दशकों में प्रवासियों का सीमांतन हुआ, जब बॉम्बे 'भाषाई क्षेत्रवाद' की साइट थी। यद्यपि प्रमुख समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व किया, इसने मराठी और गैर-मराठी भाषी लोगों के बीच अंतर बनाया। क्षेत्रीय राजनीति में शिव सेना के उद्भव के साथ,

प्रवासी 'मिट्टी के बेटों' सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गए। शिवसेना ने दक्षिण भारतीयों के मुम्बई में नौकरी हड़पने का मुद्दा पेश किया और प्रभावी रूप से कार्यकर्ता वर्ग को उद्योगपतियों और राजनीतिक वर्ग के प्रति अपनी भावनाओं को विभाजित करना शुरू कर दिया। शिवसेना के उभरने से बंबई प्रदेश कांग्रेस समिति (बीपीसीसी) और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के संघर्ष में बॉम्बे की स्थिति पर भी जड़ें थीं। पूर्व गुजराती व्यापार वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता था जो कि भविष्य में बंबई को भविष्य के महाराष्ट्र राज्य में रखने और ग्रामीण और मराठी बोलने वाले समुदाय की भूमियुक्त जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के विचार का विरोध करता था। बाल ठाकरे, शिवसेना सुप्रीमो, अप्रपुरा के रूप में प्रवासियों को संदर्भित करते थे, बिना आमंत्रित किये हुए ।

1998 में, जब शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता की थी, तब उसने 'अवैध आप्रवासियों' को भेजते हुए अभियान चलाया, जो जाहिरा तौर पर बांग्लादेश से आए थे। इसी वर्ष लगभग 1000 बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस में मजबूर किया गया था लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण, यह पहल रोक दी गई थी। फिर भी, बांग्लादेश से 'अवैध आप्रवासियों' का मुद्दा नियमित रूप से सही विंग पार्टियों और स्थानीय पुलिस बल द्वारा शहर के बंगाली बोलने वाले निवासियों पर अपनी हिंसा का औचित्य साबित करने के लिए लागू किया जाता है। शिव सेना की विरोधी प्रवासी राजनीति हमेशा मुस्लिम, विरोधी दलित और विरोधी मजदूर वर्ग की राजनीति में अनुवाद करती है। शिवसेना की राजनीति ने राज ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की है, जो उद्धव ठाकरे के पुत्र (बाला ठाकरे के बेटे) के रिश्तेदार चचेरे भाई थे। बिहारी और उत्तर भारतीय प्रवासियों को धमकी दी गई है और मनसे द्वारा नियमित रूप से दुर्व्यवहार किया गया है।

बॉम्बे के संदर्भ में शिव सेना की उत्कृष्टता को आर्थिक कारकों पर आधारित श्रमिक वर्ग की एकजुटता को तोड़ना था और इसे विखंडित एकता के साथ बदलना था जो भाषा या जन्म स्थान की तरह सांस्कृतिक कारकों पर आधारित है। इस प्रक्रिया में, वास्तविक लाभार्थियों शहर के पूंजीपतियों थे। हैरानी की बात नहीं, 2004 में मुंबई के प्रमुख निवासियों के एक समूह में, जिनमें प्रमुख महाराष्ट्रीयन साहित्यिक आंकड़े, फिल्म हस्तियों और पत्रकारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला दायर किया, जिसमें मतदान से झुग्गी रहने वाले लोगों को प्रतिबंध लगाने और विशेष रूप से गैर-अधिकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रतिबंधित करना है। उन्हें वे अवसंरचनात्मक विकास कार्यों में बाधा डाल रहे थे उन्होंने उच्च न्यायालय से मतदाता सूची से झुग्गी निवासियों के नामों को हटाने का आदेश दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका को 'पूरी तरह से गलत तरीके से' के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन यह प्रवासी गरीबों के प्रति शहर अभिजात वर्ग के बीच दुश्मनी को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, मुंबई में प्रवासियों के चारों ओर वर्णना को तीन प्रतिक्रियाओं में समझा जा सकता है- बिना योग्य, अन-आमंत्रित और अवैध। औपनिवेशिक शासन के दौरान, योग्य प्रवासियों का स्वागत किया गया था, जबकि जो लोग शहर के आर्थिक कार्यों के संबंध में उचित थे, उन्हें अनगिनत के रूप में लेबल किया गया और इस प्रकार शहर में इसका विरोध किया गया। स्वतंत्रता के बाद, शिवसेना के उद्भव के साथ उन्हें बिना निहत्थे और अधिक दशकों के रूप में इलाज किया गया, जहां स्थानांतरण लक्ष्य दक्षिण भारतीय, मुस्लिम, दलित और उत्तर भारतीय होते थे। शिवसेना की राजनीतिक अपेक्षाओं और शहर की पूंजीवादी मांगों की आवश्यकता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र-आमंत्रित प्रवासी का घटक स्थानांतरित हो रहा है। 70 के दशकों के दशक से शुरू होकर विरोधी प्रवासी अभियान ने राज्यों के कार्यकारी शासकों और न्यायिक शासकों द्वारा अदालत के निर्णयों द्वारा महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्रों अधिनियम को लाने के माध्यम से कानून बनाने में जड़ें बनाई हैं। कानूनी हमले ने अप्रवासी और गैरकानूनी और इस प्रकार समान रूप से खतरनाक के रूप में प्रवासियों के साथ व्यवहार किया है। उपरोक्त वर्गों में चर्चा के आधार पर एक यह कह सकता है कि फोर्डिस्ट शहर से बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाइयों का वर्चस्व है जहां अधिशेष निकासी एक ऐसे शहर में हो रही है जहां जगह का उत्पादन अधिशेष निकासी की जगह बन जाता है।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP73.pdf

खतरनाक कामकाज: मुंबई शहर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में मौत और वृद्धावस्था
-मौलेश्री व्यास

मुंबई जैसे शहरों को देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासियों के श्रम के माध्यम से बनाया गया है। मुंबई का आर्थिक इतिहास एक बार संपन्न कपड़ा निर्माण केंद्र पर प्रकाश डाला गया; मिलों के बंद होने के प्रभाव; और सेवा क्षेत्र की वृद्धि, जिसने शहर के चरित्र को बदल दिया। पिछले कुछ दशकों में अप्रवासी राजनीतिक वातावरण ने एक भ्रमित समाजशास्त्रीय और आर्थिक माहौल पैदा कर दिया है जहां प्रवासी मजदूर निर्माण, सेवा और प्रावधान के लिए आवश्यक है, और काम पाने में समर्थ है, जबकि शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और शहर में सांस्कृतिक स्थान उन्हें प्रधान नहीं किया जा रहा है । शहर का स्थानिक विस्तार, कुछ आबादी के साथ-साथ गठजोड़ और जीवित रहने वाले लोगों का व्यस्तता, कुछ कारक हैं जो मुंबई में श्रमिक वर्ग एकता और सामूहिक निर्माण की चुनौती को जोड़ते हैं।

गरीबी और अनौपचारिक काम से परे, इस समय की क्या जरूरत है लोगों के काम और जीवन में परिवर्तन की एक सूक्ष्म परीक्षा है जो संरचनात्मक हिंसा की अभिव्यक्तियां हैं - कारक हैं जो उनके जीवन को आकार देते हैं, और फिर भी उनके नियंत्रण से बाहर हैं ये कुछ प्रकार के कामों में स्पष्ट हैं, और अत्यधिक शक्तिहीनता जो कि उनके रोजमर्रा के जीवन में इस काम के अनुभव में लगे हुए हैं। इस पत्र ने इस घटना को दो घटनाओं के बारे में प्रवासी मजदूरों के अध्ययन के माध्यम से प्रयास किया - रोगग्रस्तता, और अनौपचारिक कार्यबल में बुजुर्गों के रोजगार; और दो अलग-अलग व्यवसायों में यह पत्र अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में मौत और बुढ़ापे की जांच करता है क्योंकि निजी सुरक्षा प्रावधान उद्योग में असुरक्षित नौकरियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के बीच काम से संबंधित रोग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। लेखक इस श्रम बाजार के इन दो विशेषताओं को 'अत्यंत खराशा' के रूप में बताता है ताकि अन्यथा असुरक्षित स्थितियों से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर गंभीर भेद्यता के इन स्थितियों को अलग किया जा सके जो इस क्षेत्र में अधिकतर काम और श्रम को चिह्नित करते हैं।
अध्ययन के लिए फील्डवर्क मुंबई के शहर में किया गया था, श्रमिकों, परिवार के सदस्यों, और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं (संरक्षा श्रमिकों के मामले में) के साक्षात्कार के माध्यम से।

कचरे के साथ काम, जो अब पुरुष और महिला श्रमिकों की कई श्रेणियों में शामिल है, एक नौकरी है जिसे मुश्किल के रूप में देखा जाता है, लेकिन शहर में प्रवेश करने वालों के लिए एक है, जो कौशल और औपचारिक शिक्षा की कमी है जो वर्तमान बाजार की स्थिति में मूल्यवान है। । शहर श्रम के इस खंड की भेद्यता और अनिश्चित स्थितियों को इस तथ्य से बढ़ाया जाता है कि उन्हें एकत्रित करना बेहद कठिन काम है। राजनीतिक वातावरण और औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र विभाजित करता है संघ निर्माण की चुनौती को बढ़ाता है, और इसलिए इन आबादी के द्वारा अधिकारों का दावा करता है। वर्तमान साहित्य में इस काम के खतरनाक स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है, इसके साथ जुड़े सामाजिक कलंक, अनुबंध श्रम शासन से निकलने वाले श्रम की शुद्धता और इसके भीतर एम्बेडेड बायोप्लाटिक्स।

समाचार पत्र की रिपोर्ट, साथ ही साथ ट्रेड यूनियनों के साथ डेटा इस काम का एक गहरा और भी अधिक रोगी पक्ष प्रस्तुत करते हैं। कई कार्यकर्ता संरचनात्मक स्थितियों के कारण अपने जीवन को खो देते हैं जिसके भीतर वे श्रम करते हैं। यह जिस वाहन पर काम कर रहा है, वह एक दुर्घटना हो सकती है, काम की प्रकृति के कारण, या निराशा

की समग्र भावना से ग्रस्त लोगों की एक बीमारी है जो जीवित रहने और गरिमा को बनाए रखने के लिए मुश्किल होती है। कचरा संग्रह और निपटान जैसे विशेष प्रकार के कार्य में लगे श्रमिकों की मृत्यु, और परिवार के लिए निरंतर संघर्ष और उसी रेखा के साथ अगली पीढ़ी, जटिल खतरों और भेद्यता प्रकट होती है।

इस पत्र के लिए किए गए फील्डवर्क से पता चला कि ठेकेदार के साथ सामंती संबंध में श्रम रखने के दौरान अनुबंध के आधार पर संरक्षण कार्य को अधिकतम काम निकालने के लिए संरचित किया गया है। कभी-कभी काम और मौत के कारण के बीच सूक्ष्म अभी तक नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए शराब की खपत, श्रम के इस खंड के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा है। श्रमिकों द्वारा इसे अक्सर समझाया जाता है ताकि उन्हें अपने काम के घंटों तक घूमने और गंदगी से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि, यह एक मुद्दा है जो कि समस्याग्रस्त होना चाहिए, इनकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रशासन के काम की प्रकृति को बदनाम नहीं कर पा रहा है, तो सभ्य काम करने की स्थिति प्रदान करने के लिए नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार हैं। सरकारी संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जो कि श्रमिकों की पहुंच है, वह खराब है, और अधूरी है अतः समग्र परिस्थितियां जो जीवन को दुखी बना देती हैं, वे व्यक्ति हैं और व्यक्तियों द्वारा छिटपुट प्रयासों के साथ और मुख्य आय अर्जक को खोने के बाद परिवारों की स्थिति के साथ सामाजिक आय के अभाव को इंगित करता है, और कोई भी महत्वपूर्ण समर्थन बच्चों के स्कूल छोड़ने, अनौपचारिक कार्यबल और यहां तक कि एक ही व्यवसाय में शामिल होने के साथ, जब तक कि श्रमिकों के इस वर्ग के लिए बेहतर काम सुनिश्चित करने के लिए काम की स्थिति बेहतर नहीं बदलती है, अगली पीढ़ी को और अधिक कठिन समय में गिरने की संभावना है मुंबई शहर में दिखाई देने वाले परिवर्तनों में से एक यह है कि विभिन्न प्रकार के गुणों में सुरक्षा रक्षक के रूप में काम करने वाले बुजुर्ग प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। शुरुआत का प्रश्न यहाँ है: कार्यबल में क्या लाया जाता है, ये आबादी अब आदर्श रूप से कम ज़ोरदार जीवन का नेतृत्व करने का विकल्प होनी चाहिए; वे इन नौकरियों को क्यों लेते हैं जो खराब भुगतान करते हैं, 12 घंटों के काम की मांग करते हैं और नींद और सामाजिक सुरक्षा के कार्यकर्ता को वंचित करते हैं? यह राज्य और संरचनात्मक प्रकृति और गरीबी में अंतर्निहित हिंसा की भूमिका के बारे में क्या संकेत करता है? क्या कार्यबल के इस भाग में 'अति शुद्धता' का एक और प्रकटीकरण है?

ठाणे शहर में सुरक्षा प्रावधान उद्योग का मूल्यांकन, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है, पंजीकृत कंपनियों के अस्तित्व को इंगित करता है, जो विभिन्न प्रकार के गुणों के संरक्षण के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करते हैं - जिनके स्वामित्व सरकार और स्वामित्व वाले हैं / समूह या निजी फर्म; घरों या आधिकारिक, और इतने पर। श्रमिक आयुक्त, और पुलिस आयुक्त जैसे नियामक निकायों की एक सक्रिय उपस्थिति है, जो लाइसेंसिंग की भूमिका निभाते हैं, और इन पंजीकृत कंपनियों के कामकाज की निगरानी जो सुरक्षा प्रावधान में लगी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित बृहहन मुंबई और ठाणे जिले के लिए एक सुरक्षा गार्ड बोर्ड, महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड्स (रोजगार और कल्याण पंजीकरण) अधिनियम 1981 के अनुसार कार्य करता है और न्यूनतम मजदूरी भुगतान (मासिक वेतन सीमा सहित कंपनियों के लिए नियमों को अनिवार्य है 10705 - 13015 से गार्ड की श्रेणी के आधार पर), सुरक्षा गार्ड के रूप में भर्ती और रोजगार की ऊपरी और निम्न आयु सीमाएं। हालांकि, जिन पैमाने पर कंपनियां संचालित होती हैं उनमें कुछ भिन्नताएं होती हैं: कुछ में 30 से 35 कर्मचारी होते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि 1500 - 2000 रंगरूटों को विभिन्न संपत्तियों में रखा गया है। न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले मजदूरों में मजदूरी अलग-अलग होती है, जिसे अधिक सभ्य वेतन के रूप में कहा जा सकता है।

हालांकि, कई हितधारकों के साथ: सरकार इस उद्योग को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने का प्रयास करती है, ठेकेदारों / नियोक्ताओं के रूप में कंपनियां, नियोक्ता के रूप में निजी संपत्ति के मालिक, और इस पदानुक्रम के नीचे सुरक्षा गार्ड, स्थिति जटिल है, और प्रकट होती है प्रवाह में होना एक बात निश्चित है: एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कर्मचारी अपने काम की स्थितियों और विकल्पों के नियंत्रण में कम से कम है, और कई एजेंसियां हैं जो उनकी काम की स्थिति निर्धारित करती हैं। शर्तों में से एक यह है कि रंगरूटों को 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए। जबकि कम आयु सीमा वह है जो भर्ती कंपनी का पालन करती है, वे ऊपरी आयु सीमा के साथ ऐसा नहीं

करते हैं इसके लिए एक आंतरिक औचित्य है: आवास सोसाइटी निर्धारित वेतन का भुगतान करने के लिए घृणा है; वे विकल्प तलाशते हैं और वे एक पुराने कर्मचारी को रोजगार के लिए तैयार हैं जो कि आधिकारिक मजदूरी से कम काम करने के लिए तैयार है।

दूसरे स्तर पर, शारीरिक रूप से सक्षम कार्यकर्ता जो साठ वर्ष से ऊपर होता है, और स्वयं और उसके परिवार के लिए निर्वाह साधनों की ज़रूरत होती है? यह स्पष्ट है कि जब नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो यह नियामक प्राधिकारियों और कंपनियों के बीच बातचीत की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है जहां चीजों को एक स्तर पर रिश्वतखोरी के माध्यम से कवर किया जाता है और दूसरे पर मजदूरी के भुगतान के माध्यम से। ऐसे संदर्भ में जहां सामाजिक नेटवर्क और कनेक्शन ठेकेदारों के लिए 'अपने स्वयं के लोगों को ऐसी नौकरी में लाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, ऐसी अनौपचारिकता पनपती है और भूमिगत अर्थव्यवस्था में कायम है ।

कुछ बुजुर्ग सुरक्षा गार्डों के साथ साक्षात्कार से पता चलता है कि वे एक संरचनात्मक और प्रणालीगत संदर्भ में दिखते हैं जो उनके खिलाफ काम करता है। उनमें से कोई भी अपने ठेकेदारों या नियोक्ताओं के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता था। वे सभी प्रवासियों और शहर में एक पैर जमाने के प्रारंभिक वर्ष हैं, सभी के लिए संघर्ष भरा है। यह पारिवारिक परिस्थितियों और एकल आय की अपर्याप्तता है जो प्रवासियों के परिवारों से सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में महिलाओं को लाई है, और पुरुष सदस्य को कई नौकरियों और व्यवसायों को ले लिया है। सुरक्षाकर्मियों के कब्जे में क्रमिक प्रवेश बड़े पैमाने पर हुआ है जब इन श्रमिकों के लिए अधिक शारीरिक रूप से मांग वाली नौकरियां मुश्किल हो गईं। यह स्पष्ट है कि इन पुराने कर्मचारियों में से कोई भी निर्धारित वेतन नहीं मिल रहा है; उनकी खराब सौदा की स्थिति उनके संबंधित घरों में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के विवरण से भी स्पष्ट होती है। कानूनी विनियमन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से करना है, लेकिन यह बढ़ते भूमिगत सुरक्षा प्रावधान उद्योग का नेतृत्व करता है, ठेकेदारों द्वारा सशक्त सुरक्षा गार्ड के साथ। उनमें से प्रत्येक ने मुंबई में संघर्ष के लंबे वर्षों को देखते हुए, मुश्किल हालात में भारी मुश्किल परिश्रम के माध्यम से परिवार का निर्माण किया है, और परिवार के संबंधों और अन्य कमजोरियों के कारण, एक बिंदु के बाद फिर से फिसल गए हैं।

अध्ययन से, ऐसा प्रतीत होता है कि अनौपचारिक कार्यबल के इन दो हिस्सों के जीवन की वास्तविकता, कार्य और मजदूरी से परे कारकों के अनुसार होती है - उनकी जीवन स्थितियां, बीमारी या मृत्यु सहित किसी भी कठिनाई से निपटने में असमर्थता, दलित जीवित जीवन गांव के मुकाबले शहर में, सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति या गुणवत्ता कल्याण सेवा तक पहुंच, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए अत्यधिक शुद्धता की स्थिति बनायें तेजी से अपर्याप्त कल्याणकारी शासन के तहत प्रेरकियेट का यह प्रजनन आने वाले वर्षों में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने का वादा करता है।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

प्रवासियों, सतर्कता और हिंसा: मुंबई में सुरक्षा गार्ड का एक अध्ययन
-ऋतम्भरा हेब्बार और महुआ बंद्योपाध्याय

यह अध्ययन उन प्रवासियों के जीवन की खोज के विरोधाभास में स्थापित किया गया है जो सुरक्षा गार्ड या संरक्षक के रूप में काम करते हैं, जो कि उनके खिलाफ हिंसा की राजनीति के लिए जाना जाता है। सुरक्षा गार्ड उनकी भूमिका से कैसे संबंधित हैं और जब उनकी स्थिति और पहचान प्रवासियों के रूप में अनिश्चित है और संदेह के साथ काम करती है? मुंबई के लंबे और जटिल इतिहास का विमोचन बेहद विविध और लगातार बदलते हुए प्रवासियों की आबादी में और जातीय रेखाओं के साथ ध्रुवीकृत पहचान की अपनी राजनीति के माध्यम से किया गया है। 1 9 60 के दशक में शिवसेना और उसके नेता बाल ठाकरे के उत्थान के साथ मुंबई अपने प्रवासियों के खिलाफ हिंसा के लिए जाना जाता है और 1960 के दशक में शिव सेना और उसके नेता बाल ठाकरे के उत्थान के साथ ही राजनीतिक फायदे के लिए नतीशवाद पैदा करने के लिए राजनीतिक दलों के शौक़ीन बने रहे। हिंसा का यह 'पंथ' और ऐसे homogenized तरीके जिनमें प्रवासी को माना जाता है और प्रवासियों के मुद्दों, भूमि आंदोलन के बेटों, शहर में श्रम के रूपों को बदलने और सुरक्षा के उभरते संदर्भ, आतंक , पैपटीसिज्म और निगरानी प्रवासी सुरक्षा गार्ड का अनुभव कई असुरक्षाओं के विरोधाभास और शहर में जीवन के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के कार्य के द्वारा तैयार किया गया है।

यह विरोधाभास अलग-अलग तरीके से खुला रहता है न कि सुरक्षा गार्ड के हर रोज़ अनुभवों में, बल्कि विशिष्ट मामलों में भी, जिनके वर्षों में शहर में अलग-अलग अपराधों में उन्हें फंसा दिया गया है, साथ ही साथ नियंत्रण और विनियमन पर लंबे समय से तैयार कानूनी लड़ाई में राज्य में सुरक्षा गार्ड की इन पहलुओं के माध्यम से संगठन में और शहर में सुरक्षा कार्य के अनुभव की खोज में, हम चुनौती देने और प्रवासी श्रम की शुद्धता की रैखिक और वर्णनात्मक समझ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं; स्थिरता को अक्सर वर्ग, 'प्रवासी' को सौंपा जाता है; और सुरक्षा की सरल समझ इन अवधारणाओं के पुनर्संकलन से हमें सिक्योरिटी काम में शहरी समाजवाद के विभिन्न भावों की समझ और उन तरीकों से सुरक्षा, प्रवासन और श्रम पर स्थापित प्रवचनों के बारे में समझा जा सकता है।

यह अध्ययन, बहुसंख्यक नृवंशविज्ञान की पद्धति संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा उद्योग के एक सिंहावलोकन से शुरू होता है, जिसमें मुंबई पर विशेष ध्यान दिया गया है। शोधकर्ताओं ने मुंबई में उद्योग की प्रकृति और शहर में सुरक्षा सेवाओं के अनूठे कानूनी रूपरेखा पर चर्चा की। फिर वे मुंबई में प्रवासी श्रमिकों के ध्रुवीकरण प्रक्रियाओं में निरंतरताओं का प्रदर्शन करने के लिए मुंबई में प्रवासी श्रम का एक विषयगत इतिहास प्रस्तुत करते हैं। इन प्रक्रियाओं को नृवंशविज्ञान रूप से समकालीन संदर्भ में विस्तारित किया गया है जो कि हर रोज़ कार्य और प्रवासी सुरक्षा गार्ड के जीवन में अंतर्निहित संरचनात्मक हिंसा को प्रकट करता है। अंत में, अध्ययन में ढांचागत हिंसा के विचार और शहर में प्रवासियों के जीवन पर इसके निहितार्थ के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

शोधकर्ताओं ने सुरक्षा एजेंसियों का दौरा किया, एजेंसी के मालिकों से मुलाकात की और शहर में निजी सुरक्षा एजेंसी के व्यवसाय की प्रकृति और सीमा को समझने के लिए। इसके अलावा, उन्होंने अपने कार्यस्थलों में सुरक्षा गार्ड का साक्षात्कार किया, उनके साथ रख दिया और उन्हें देख लिया जब वे ड्यूटी पर थे, निजी सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों और प्रबंधकों से मिले उनके साथ खुले और अन्तर्भाषित साक्षात्कार किए गए। इस शोध के सीमित समय सीमा को देखते हुए उन्होंने केवल पुरुष सुरक्षा गार्डों का साक्षात्कार करने का निर्णय लिया। शोधकर्ताओं ने भी

काफी समय तक महाराष्ट्र गार्ड बोर्ड, एक बड़े राज्य चलाने वाले सुरक्षा सेवा प्रदाता में काफी समय व्यतीत किया, जो सुरक्षा गार्ड की कार्यशील शर्तों और सुरक्षा गार्ड के एक विशेष संघ के कार्यालयों को विनियमित करने के कानून के बाद अस्तित्व में आया।

शोधकर्ताओं के लिए प्रवासी की श्रेणी एक बारहमासी है और एक निश्चित, निर्णायक श्रेणी नहीं है। प्रवासियों के जीवन और संसारों के माध्यम से शहरी सामाजिकता की प्रकृति को समझने के लिए, उन्होंने एक बहुसंख्यक नृवंशविज्ञान दृष्टिकोण का पालन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के सामाजिकता एक साइट या एक प्रकार की सामाजिक घटनाओं में शामिल नहीं हो सकीं। इसलिए उन्होंने न केवल विभिन्न निजी सुरक्षा एजेंसियों, आवासीय भवनों, कार्यालयों और अन्य सेवा भवन जैसे एटीएम, एक धर्मशाला, जहां सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे, गार्ड बोर्ड के कार्यालय और कामगार संघ कार्यालय, उन्होंने इंटरव्यू आयोजित करते समय भी विभिन्न पद्धतिगत रणनीतियों का इस्तेमाल किया।

निजी सुरक्षा उद्योग को सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक माना जाता है, और पूरे देश में 60 लाख से अधिक निजी सुरक्षा कर्मियों को रोजगार मिलता है। बुनियादी ढांचे के विकास और माना जाता सुरक्षा खतरे के रूप में 'राजनैतिक और प्रशासन अस्थिरता' के रूप में पहचान की गई जिसमें 'स्ट्राइक, क्लोजर और अशांति' और 'आतंकवाद और विद्रोह' शामिल हैं। आश्चर्य की बात नहीं, निजी सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख ग्राहक औद्योगिक और कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं।

मानव रखे रखवाली खंड खंडित है और बड़े पैमाने पर असंगठित है। संगठित बाजार में उद्योग का हिस्सा 35% है बड़े संगठनों, बड़ी खुदरा और कॉर्पोरेट इकाइयों, छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों को पूरा करने वाली बड़ी कंपनियां आयोजित की जाती हैं, जबकि मानव-संरक्षित सेवाओं के लिए असंगठित खिलाड़ियों पर काफी हद तक निर्भर रहता है। इन एजेंसियों की प्रकृति के बारे में स्पष्टता की कमी है, जिस तरह से वे कार्य करते हैं, उनके ऑपरेशन की प्रकृति और उनके बीच अप्रियता की सीमा। विडंबना यह है कि, सरकार का ध्यान इन सेवाओं के लिए बाजार पर पूंजीकरण पर रहता है, जो बिना किसी अज्ञात मानव रखे रखरखाव सेवा की सुरक्षा के निहितार्थ को समझने में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं रखता है।

अपने आपरेशन के पैमाने के बावजूद, सुरक्षा एजेंसियों को प्रति गार्ड आधार पर राजस्व उत्पन्न होता है। चूंकि आपूर्ति की गई गार्ड की संख्या पर राजस्व उत्पन्न होता है, बहुत से एजेंसियों को अधिक गार्ड के लिए बजट दिया जाता है, लेकिन अभ्यास में कम से ज्यादा गार्ड की रक्षा करने वाले गार्ड के कर्तव्यों को दोगुना करके वे अपने राजस्व को अधिकतम करने की आपूर्ति करते हैं। ऐसे मामलों में, एक गार्ड को अतिरिक्त कर्तव्यों जैसे कि हाउसकीपिंग, डबल शिफ्ट आदि करने की उम्मीद होगी। हम जिन गार्डो की साक्षात्कार की गईं हैं, उनमें से कई ने 12 से 12 घंटों में बदलाव किया था, और अक्सर कई स्थानों पर। उन्हें औसतन रुपये का भुगतान मिलता है 5000 प्रत्येक बदलाव के लिए दोगुनी बदलाव कार्य करने के लिए गार्ड शहर में एक जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। कई लोगों के लिए, मुंबई जैसे शहर में रात के लिए आश्रय खोजने का ख्याल रखता है जहां आवास बहुत महंगा है।

शहर में सुरक्षा गार्ड और एजेंसियों की संख्या पर स्पष्टता की स्पष्ट कमी उद्योग की कब्र प्रकृति का संकेत है, इसके संचालन की गुस्से की प्रकृति और राजनीतिक संबंध जो इसे सहारा देते हैं। कुछ सुरक्षा एजेंसियों के साथ साक्षात्कार में पता चला कि कितने नेताओं (मुख्य रूप से उत्तर भारत से घिरा) प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के मालिक हैं, और नौकरशाही में शीर्ष अधिकारियों के साथ समझ है जो उन्हें कानूनी रूप से बिना शहर में अपने व्यवसाय चलाने की इजाजत देता है। और प्रशासनिक भारोत्तोलन राजनेताओं के अलावा, व्यापार में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों का भी वर्चस्व है, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक परमिट और सहायता प्रदान की गई है। निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिकों द्वारा हाइलाइट की गई एक अन्य विशेषता यह है कि व्यापार में लाल टेप और भ्रष्टाचार है। एजेंसी के मालिक सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए

अपनी निजी शक्ति का प्रयोग करते हैं ताकि वे अपने कारोबार को चलाने के लिए मंजूरी और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें। प्रवासी के लिए, कार्यबल में उसकी प्रविष्टि को नियोक्ता, मित्रों, रिश्तेदारों और नेटवर्क की संपूर्ण श्रृंखला से लाभ के माध्यम से बंद कर दिया जाता है, जो न केवल शहर में जीवित रहने के लिए इन 'महत्वपूर्ण दूसरों' पर उनकी निर्भरता को उजागर करता है, लेकिन यह क्षेत्रीय, जाति और परिजन आधारित समाजवादियों में प्रवासियों को भी प्रवेश करती है।
ये तब शहर में, जो वास्तव में अपने ग्रामीण रोक टोक के बाहर उभरे नहीं, साथ ही निंदा की भावना के लिए आधार बन गए । यहां तक कि एजेंसियों के संबंध में जो उन्हें किराया, वे एक डबल बाँध में हैं। वे एजेंसी पर उनके लिए शहर में काम करने के लिए आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजेंसी पर निर्भर हैं, भले ही वे शर्तों और उनको पेश किए गए काम की शर्तों से परेशान महसूस करें। ब्रोकरेज की यह व्यवस्था व्यवसाय के साथ-साथ शहर में असंगत संबंधों को कायम करती है, और इसके भीतर ग्रामीण प्रवासी सबसे कमजोर और शक्तिहीन है।
विरोधाभासी कानूनों का अस्तित्व सुरक्षा गार्ड के जीवन और कार्यों को आगे बढ़ाता है।
शोधकर्ताओं द्वारा साक्षात्कार के अधिकांश सुरक्षा गार्ड यूपी, बिहार, ओडिशा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों से प्रवासियों हैं। उन सभी ने कहा कि उनके आंदोलन को अपने स्वयं के संदर्भों और शहर में काम, आजीविका और गतिशीलता के लिए कथित अवसरों की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर भी, शहर की राजनीति में इन प्रवासियों को मराठी और गैर-मराठी प्रवासी के रूप में अलग किया गया है। श्रेणी मराठी मनुस को भाईया (मूलतः यूपी और बिहार से प्रवासी) के खिलाफ जुड़ा हुआ है। इस भेदभाव, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण पतन के साथ, इस तरह की पहचान में प्रतिरूप किया जाता है जैसे कि घर मालिक बनाम गैर-मालिक या निवासी बनाम किरायेदार। ये बायनेरिज़ बाहरी और शैक्षिक रूप से बाहरी और शैक्षणिक रूप से बाहरी और अंदरूनी सूत्रों में शामिल होते हैं।

सुरक्षा गार्ड के साथ गहराई से साक्षात्कार में एक झलक, और एक परिप्रेक्ष्य, शहर में प्रवासियों के रूप में उनके जीवन, शहर में जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष, काम पर शोषण की प्रकृति, और सुरक्षा कार्य की चुनौतियों का सामना करते हैं। इन साक्षात्कारों से निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं:
1. कृषि से राजस्व घटाने, कृषि संबंधों में बदलाव, पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता और बेहतर जीवन के लिए एक आकांक्षा, शहर में पलायन के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं, विशेष रूप से ऊपरी जाति प्रवासियों, जो शहर में स्वच्छ रोजगार की तलाश करते हैं।
2. हालांकि, कृषि में आवश्यक कड़ी मेहनत की आदत को तोड़ने में शहर के जीवन का डर भी है। इस डर के कारण हमारे कई उत्तरदाताओं को शहर में शारीरिक श्रम के लिए घृणा द्वारा योग्य बनाया गया है। इस तरह के घृणा को अक्सर जाति, पितृसत्ता और लिंग के मानदंडों के माध्यम से लैंगिक और उचित माना जाता है।
3. प्रवासियों ने अपने गांवों के साथ एक मजबूत लिंक बनाए रखा है, अक्सर अपने परिवार को वहां रखते हुए। यह परंपरा के नाम पर उचित है अंततः गांव में वापस जाने की इच्छा भी एक वजह है कि प्रवासियों शहर के साथ एक लचीली संबंध पसंद करते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के अनुसार शहर में और बाहर जाने का विकल्प रखने के लिए।
4. सुरक्षा रक्षकों के लिए, उद्योग के अंदर की अप्रियता, काम की खराब स्थिति, गरीब और अनियमित वेतन, उनकी नौकरी खोने का निरंतर डर और उनकी शर्तों के तदर्थ और अनौपचारिक प्रकृति के कारण उनका व्यवसाय एक जोखिम भरा है। काम। वे लगातार आपराधिक लेन-देन में गलत तरीके से फंसा होने के डर में रहते हैं। गार्ड के लिए, उनके काम के संबंध में अच्छे अनुभव, पैतृतात्मक संगठनों से उत्पन्न होते हैं, उदारता और विशिष्ट व्यक्तियों की उदारता में। इन दोनों पहलुओं में उनकी असुरक्षा और गलतफहमी है।
5. साक्षात्कार से सुरक्षा गार्ड के काम से जुड़े निरर्थकता की भावना भी उभर कर सामने आती है। जबकि कुछ ने नौकरी में गतिविधि की कमी व्यक्त की और इसे बोरिंग के रूप में व्यक्त किया, कुछ अन्य इसे मूर्खों के लिए एक नौकरी फिट मानते हैं। यह आत्म-बहिष्कार काम की बड़ी स्थिति के संदर्भ में उभर आता है जो अपने आत्मसम्मान को कम करता है ।

6. सम्मान प्रवासी अनुभव के निर्माण के परिभाषित पहलुओं में से एक है। सुरक्षा गार्ड अक्सर काम पर अपने फैसले की व्याख्या करने के लिए एक रणनीति के रूप में सम्मान का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मान को बनाए रखने के मामले में हाउसकीपिंग के काम करने से इनकार अक्सर समझाया जाता है ।
7. राउंडर का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। वह एजेंसी द्वारा अपनी अलग-अलग साइटों पर जाने और गार्ड के काम की जांच करने के लिए कार्यरत व्यक्ति है। वह गार्ड और एजेंसी के बीच प्रमुख संपर्क व्यक्ति भी हैं। यद्यपि वे एक ही सोशल नेटवर्क से खींचा जाते हैं, गार्ड और राउंडर एक दूसरे के साथ और एजेंसी के साथ परिचित नहीं हो पा रहे हैं। इससे उनके काम के जीवन में अस्थिरता का एक अतिरिक्त अर्थ पैदा होता है।
8. यह साक्षात्कारों से स्पष्ट है कि प्रवासी (पैराप्रांति) होने का गहन अर्थ है, हर समय तीव्रता से महसूस किया गया है और फिर भी वहां उभर आती है, स्थानीय मुहावरों में दृढ़ता से व्यक्त किया जाता है, इसने एक श्रम और कड़ी मेहनत के साथ शहर का निर्माण करने का दावा किया। प्रवासियों ने शहर को संपत्ति खरीदने, राशन कार्ड खरीदने और आधार कार्ड खरीदने, सरकारी रोजगार की मांग, शहर में परिवारों को लाकर और व्यवस्थित करने, शहर आधारित नेटवर्क के माध्यम से विवाह व्यवस्था करके शहर के अधिकार का दावा किया।
9. प्रवासी सुरक्षा गार्ड का आंकड़ा अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि कुछ उदाहरणों में जहां वे हिंसा के अपराधियों को मुंबई की इमारत के सुरक्षा रक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न और बेरहमी से हत्या कर रहे उस जवान महिला के मामले में जैसे ही थे वह रहते थे संरक्षक के रूप में सुरक्षा गार्ड के चित्रकार, संरक्षक के रूप में, कभी-कभी एक बंदूक का प्रयोग करना, निगरानी के रूप में, पुलिस स्थानापन्न के रूप में, और बाहरी व्यक्ति के रूप में प्रवासी के रूप में और इसलिए हिंसा के अधीन, उनकी नाजुक और अक्सर हिंसक कार्य और जीवन संदर्भों के साथ जुड़ जाता है । सुरक्षा मानदंडों की भर्ती के लिए काम के मानदंडों के साथ ही मौजूदा नियमों का उल्लंघन, गार्ड की अकेली और गहरी असुरक्षित जिंदगी, जिस तरीके से पैपेटिक तंत्र का उपयोग किया जाता है - ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में केंद्रीय विचार प्रवासी श्रम आकार और शहरी स्थान पैदा करता है, नृवंशविज्ञान से पता चला है। उदाहरण के लिए हिंसा की सामग्री अभिव्यक्ति पर ध्यान, एक युवा निवासी की बलात्कार और हत्या जैसे हिंसा के एक अधिनियम में एक प्रवासी गार्ड की सम्मिलित भागीदारी के माध्यम से, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, संरचनात्मक का स्पष्ट और सीधे टकराव वाला दृष्टिकोण प्रवासी सुरक्षा गार्ड के जीवन में हिंसा हालांकि, संरचनात्मक हिंसा का यह टकरावकारी पहलू जो सुरक्षा गार्ड के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, को नजरअंदाज कर दिया जाता है और गार्ड द्वारा हिंसा के कृत्य के प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ाया और बढ़ाया जाता है। आपराधिक कृत्य और उसके चारों ओर आने वाले आगामी सार्वजनिक प्रवचन न सिर्फ व्यक्तिगत गार्ड का है, बल्कि 'प्रवासी' वर्ग को फंसाने के लिए अपराधी से परे का विस्तार। 'प्रवासी' की यह सार्वजनिक घोषणा ने शहर में प्रवासी की प्रथाओं और ध्रुवीकरण को मजबूत किया है, इस प्रकार वे संरचनात्मक हिंसा की शर्तों को न्यायसंगत बनाते हैं।
10. यह कोई सजातीय प्रवासी अनुभव नहीं है। लेकिन साक्षात्कारकर्ता इस विचार को गंभीरता से मानते हैं कि मुम्बई शहर में जीवन को बदलने की जबरदस्त क्षमता है।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

अनुसंधान संक्षेप
धारा 4: सिलीगुड़ी और बिहार के कोसी क्षेत्र

उत्तर बंगाल में एक ट्रांजिट टाउन: वैश्वीकरण के समय में सिलीगुड़ी
-समीर कुमार दास

निम्नलिखित अध्ययन में प्रवासी मजदूरों के लिए एक पारगमन शहर के रूप में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के एक शहर सिलीगुड़ी का पता चला है। यह हमेशा प्रवासियों के शहर के रूप में माना जाता है हालांकि, प्रवासन की प्रकृति और प्रोफ़ाइल में काफी बदलाव हुए हैं। हालांकि, सभी खातों के अनुसार, बीसवीं सदी की शुरूआत में केवल एक बड़ा गांव, इसके कुछ निवासियों के रूप में कुछ हजार लोगों के साथ, भारत में 1947 में विभाजन के बाद पड़ोसी देशों के प्रवासियों की आबादी के साथ ही सिलीगुड़ी बदल गया एक शहर में - कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा शहर विशेष रूप से हाल के वर्षों में अपनी आबादी का तेजी से विस्तार देख रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार, निवासियों की संख्या 1,220,275 थी और 2008 में एक और अनुमान के अनुसार, यह आंकड़ा 1,5 9 5,275 में चौंका देने वाला है।

यद्यपि इस प्रतिशत वृद्धि में से अधिकांश भारत के भीतर से और बिना दोनों के आप्रवासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन कम से कम कहने के लिए, जन्म और जगह की जगह दोनों जगह पर, आप्रवासियों की जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाना मुश्किल है। , आप्रवासियों की जातीयता और सामाजिक पृष्ठभूमि के केवल अविश्वनीय संकेतक हैं। विशेष रूप से 1981-1991 के दशक के दौरान जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि, सभी खातों द्वारा, जनसंख्या घनत्व को जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज़मीन पर दबाव डालता है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि भी मलिन बस्तियों की संख्या में इसी वृद्धि से मेल खाती है। 1975 में, 36 झुग्गी बस्तियों थे, जबकि 2003-4 में यह संख्या 156 तक पहुंच गई। 1991 की जनगणना के अनुसार, सिलीगुड़ी की जनसंख्या 21.57 प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहती हैं, जिनमें से अधिकांश लोग प्रवासियों में रहते हैं।

प्रवासियों को अलग-अलग विभाजित किया जाता है। जबकि विभाजन (1947) शरणार्थियों शहर के केंद्र में रहने वाले कम या ज्यादा कम-से-कम स्थित हैं, शहरी गरीबों को रेलवे पटरियों के साथ घूमने वाले कॉलोनियों में बसने और अपेक्षाकृत सूखी नदी हैं। प्रवासियों उच्चतम प्रतिशत बांग्लादेश से आये थे । बिहार, झारखंड और ओडिशा (पूर्व में उड़ीसा) के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों ने पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के रूप में ज्यादा प्रवास किया है। परिणामस्वरूप सिलीगुड़ी में प्रवासियों का शहर बन गया है और 20 से अधिक भाषाओं में असंख्य जातीय समूहों और समुदायों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का घर शहर से नियमित आधार पर प्रकाशित किया गया है। उत्तर बंगाल के सूक्ष्म जगत के रूप में सिलीगुड़ी में औद्योगिक बुनियादी बातों का अभाव है सिलीगुड़ी का शहरीकरण किसी भी संबंधित औद्योगिकीकरण से मेल नहीं खाता है। औद्योगिकीकरण की कमी ने सिलीगुड़ी को एक बाजार शहर बना दिया है। यह 1960 से थोक व्यापार का केंद्र बन गया है। दिल्ली में 0.21 की तुलना में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा - प्रति 100 लोगों की तीन दुकान हैं। 1981 के बाद, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बाल, भारतीय सेना और वायु सेना के प्रतिष्ठानों सहित कुछ महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालयों को स्थापित किया गया है या सिलीगुड़ी में स्थानांतरित किया गया है। श्रृंखला में नवीनतम सिलीगुड़ी का एक पुलिस आयुक्त के रूप में परिवर्तन है और 2013 में दोनों दोनों ही फार्बारी में उत्तरकालियं में सरकारी सचिवालय की स्थापना है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध और अंततः 1971 में पश्चिम पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण में योगदान शहर में शरणार्थियों का प्रमुख प्रवाह

जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है और शहर फैलता है, यह आसपास के चाय बागानों और पड़ोसी क्षेत्रों को चाय मजदूरी और हाशिए पर पलायन करने और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। शहरी-से-ग्रामीण प्रवास शीलुगुड़ी के शहरीकरण की विशिष्ट विशेषताओं में से एक रहा है। प्रशासनिक रूप से, ये क्षेत्र 'जोड़े क्षेत्रों' के रूप में पुनः वर्गीकृत होने के माध्यम से सिलीगुड़ी शहर का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह के 'जोड़े गए क्षेत्र' में दाग्राम, भक्तनगर, फुलाबारी, मतिगरा, बागडोगरा और सुकना शामिल हैं। शहर में खड़ी फैली

हुई है और तीन बड़ी नदियां हैं, जैसे कि बैलसन, महानंदा और तीस्ता आगे भौगोलिक विस्तार के लिए सीमित दायरे प्रदान करते हैं।

हालिया सालों में सिलीगुड़ी में जनसंख्या वृद्धि का संकट है, जो कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से चाय उद्योग को विशेष रूप से डूअर्स और तेराई क्षेत्रों में सामना करना पड़ रहा है। डूआरए में 72 चाय के बागानों को आज बीमार माना जाता है। डूअर्स में चाय बागानों में से छह बंद हो गए हैं और कई अन्य लोगों को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 3000 स्थायी कर्मचारी अपनी नौकरी खो गए यहां तक कि अगर वे खुले रहते हैं, तो प्रति दिन 9 5 रुपये का वेतन दुनिया में सबसे कम है। रेडबैंक समूह के स्वामित्व वाले तीन उद्यान हैं। रेडबैंक टी एस्टेट के अलावा, सुरेन्द्रनगर टी एस्टेट और धरनपुर टी एस्टेट हैं, जो हाल के वर्षों में बंद हो चुके हैं। लगभग 2,200 परिणाम के रूप में खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया गया था अलीपुरद्वार में, दो बागियां- ढेकलापारा चाय एस्टेट और बांदपति- कई सालों से बंद कर दी गई हैं। इन पाँच बागानों का लगभग 15,000 श्रमिकों और उनके 45,000 आश्रितों के लिए खाता है। चूंकि चाय उद्योग संकट का सामना करता है, अब तक शहर के आस-पड़ोसों और गांवों में चाय की खेती के तहत जमीन भूमि डीलरों, प्रमोटरों, डेवलपर्स और भूमि माफिया के लिए शिकार का मैदान प्रदान करती है। के रूप में चाय उद्यान तेजी से गैर-व्यवहार्य हो गए, चाय बागान के तहत अब तक की जमीन अब तेजी से रियायतों की कमाई में बदल गई है और शहर के किनारे पर स्थित उद्यानों को सबसे पहले ब्रेक सहन करना पड़ा। चंडमोनी टी एस्टेट एक उत्कृष्ट उदाहरण है- सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में बंद होने से पहले चाय मजदूरों के बड़े पैमाने पर बेदखली और विस्थापन हो गए थे, जिनमें से कई शव को बंद होने से पहले कैजुअल श्रमिकों में कम हो गए थे। जिन लोगों को बेदखल किया गया था, अब सड़क के विपरीत दिशा में प्रधान सार्वजनिक (खास) भूमि में बस्तियां (मलिन बस्तियों) में शरण ले ली है। सिलीगुड़ी इस प्रकार दो आप्रवासियों के सेट हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के खिलाफ थे। एक तरफ, जो थोक और खुदरा व्यापार में तेजी ला रहे हैं और इसे बाहर से तरल धन बनाते हैं और इसे उत्तरी बंगाल के बाहर स्थित अपने घरों में ले जाते हैं और जो लोग 'बदलते' शहर से लगातार बेघर हो जाते हैं
चाय बागान बंद हो जाने पर चाय श्रम क्या करते हैं? बहुत से लोग भूटान और काम की तलाश में अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं और उनमें से कुछ वहां मुख्य रूप से सूखा नदी के पत्थर, चूना पत्थर क्रशर, डोलोमाइट खनिक और आगे के पत्थरों के लिए काम करते हैं। दूसरों को अभी भी जीवित चाय उद्यान में काम खोजने की कोशिश करते हैं। चाय श्रम की गतिशीलता को गंभीर रूप से अवरुद्ध किया जाता है क्योंकि यह ज्यादातर अकुशल मजदूरों के साथ क्षेत्र के बाहर होने के इतिहास का नहीं होता है। जो लोग कदम नहीं उठा सकते हैं, बैलसन और दूसरी पहाड़ी नदियों के सूखे नदियों के पत्थरों से पत्थर इकट्ठा करते हैं और उन्हें ठेकेदारों को बेच देते हैं। उनके हाथ मोटे होते हैं और उनमें से कई रोगों से ग्रस्त हैं बागानों से महिलाओं को नियमित आधार पर लगभग तस्करी की जाती है जिन लोगों को बंद चाय बागानों में छोड़ दिया जाता है (वे न तो तस्करी करते हैं या न ही बेचे जाते हैं) भुखमरी और धीमी मौत के अधीन होते हैं।

शहरी गरीबों के रोजगार के साधनों को जानना महत्वपूर्ण है - अगर कोई भी हो नए प्रवासियों के रूप में आने और गेटित परिसरों में रहने के लिए, अनौपचारिक श्रम की इसी मांग - घरेलू श्रम के लिए, घर के काम के लिए देखभाल के लिए, घरेलू अपशिष्ट के लिए घरेलू अपशिष्ट, वाशिंगर, अर्द्ध कुशल इलेक्ट्रिकर्स, प्लंबर के लिए अपशिष्ट निपटान , और अन्य सेवा प्रदाताओं और सबसे महत्वपूर्ण अवैध शिकारियों, नदी के किनारों से अवैध चूना पत्थर इकट्ठे आदि - बिचौलियों द्वारा नियंत्रित एक क्षेत्र - जो उनके नियोक्ताओं और एजेंटों के रूप में काम करते हैं। अनौपचारिक श्रम के अधिकांश खराब रूप से कुछ हद तक भुगतान किया जाता है क्योंकि वे बहुत ही अपने नियोक्ता के साथ शब्दों को परिभाषित करने के लिए गरीब हैं और कुछ हद तक अनौपचारिक स्वभाव के कारण आंशिक रूप से। सिलीगुड़ी थोक बाजार के लोडर एक उदाहरण प्रदान करते हैं। अक्सर नहीं, थोक व्यापारी अपने गरीबी और असंगठित प्रकृति का लाभ उठाते हैं । इसके विपरीत, सिलीगुड़ी के नए अमीर लोगों में मुख्य रूप से प्लांटर्स, थोक व्यापारियों, सेना और सरकारी अधिकारी, एन.जी.ओ. के कप्तान, क्रॉस-बॉर्डर के साथ गहराई से जुड़े लोगों और कई बार ऐसा नहीं-लाइसेंस वाले व्यापार और आगे भी जो उनके रहते हैं आमतौर पर राज्य और उसकी

एजेंसियों (जैसे सिलीगुड़ी नगर निगम) द्वारा प्रदान की जाने वाली जीवन की शहरी सुविधाओं पर निर्भर हुए बिना, अपने शानदार और गेट वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आराम के भीतर रहने वाले को अपने जीवन जीना चाहिए। ये बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं, 'पवित्र स्थान' के रूप में, जिसने शहर के साथ अपने संबंध को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है, इस शहर के अपने जटिल जीवन के बाहर के लोगों को हाथ की लंबाई में रखा जाता है।

एक पारगमन शहर के रूप में सिलीगुड़ी मुख्य रूप से दो प्रकार की हिंसा के लिए एक स्थायी गवाह रहा है: एक, सामाजिक रूप से 'आपराधिक' हिंसा जिसकी वजह से क्रॉस-बॉर्डर आपराधिक नेटवर्क की प्रकृति से जुड़ी है जो कि वर्षों से विकसित हुई है। दो, एक पारगमन शहर होने के नाते यह किसी भी शहर में अपने निवासियों को प्रतिस्थापित नहीं करता है क्योंकि यह घर पर 'बेघर' था। बेघर होने की चिंता और वैश्विक व्यापार का आकर्षण और 'नकदी प्रवाह' ने शहर को मातृभूमि की मांग को चुनने के लिए एक आदर्श स्थल बना दिया है जो अक्सर हिंसा में पड़ता है। विडंबना यह है कि, सिलीगुड़ी किसी भी घर के बिना मातृभूमि दावों के दावों की जगह है।
सिलीगुड़ी में जातीय हिंसा का कोई इतिहास नहीं है, हालांकि सतह पर कमजोर शांति के संकेत हैं और सिलीगुड़ी के सामाजिक परिदृश्य में गहरी चाल होने वाले उथले हैं। एक ओर, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा (जीजेएम) गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अधिकार क्षेत्र में सिलीगुड़ी के कुछ मौजे को शामिल करने का दावा करता है। दूसरी ओर, जन चेतना मंच और जन जागरण मंच जैसे समर्थक बंगाली संगठनों का गठन किया गया है और जीटीए में इन मौजे को शामिल करने का विरोध किया गया है। इसके साथ हाथ में हाथ, अल्ट्रा अधिकार अमरा बंगाली शाखाएं कथित तौर पर उत्तर बंगाल में फैल रहे हैं।

इस संदर्भ में जबरन प्रवास में सामाजिक न्याय का मुद्दा दोनों बेहद प्रासंगिक और लगभग अदृश्य है। प्रासंगिक, क्योंकि पारगमन में शहर ने न केवल उन लोगों को बेदखल कर दिया है जो न केवल शहर पर अपने जीवन और आजीविका के लिए संपन्न हुए बल्कि शहर से उन लोगों के लिए 'घर' बनाते हैं जो शहर से लगभग अनुपस्थित हैं। सिलीगुड़ी में अनुपस्थितियों के लिए जगह है - लेकिन बेघर के लिए कोई जगह नहीं है जबरन प्रवास के मुद्दे पर जो न्याय की व्याख्या की गई है, संसाधनों और अवसरों की असमानता और प्रवासन के माध्यम से उन तक पहुंचने के लिए वंचित होने के अधिकार पर गहराई से इशारा किया है। वास्तविक रूप से अदृश्य - क्योंकि वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में दिक्कत आ रही है, दोनों प्रवासियों ने अपने 'घर' पर एक अज्ञातता प्राप्त की है जो जनता के नजदीक और जांच से अदृश्य हो जाता है।

शहर में शहरी गरीब और अंडरक्लास रहते हैं; लेकिन वे नागरिक नहीं हैं, क्योंकि उनके पास 'शहर का अधिकार' नहीं है वे अक्सर क्रूर हिंसा का अनुभव करते हैं - घरों की जला, बलात्कार, जबरन वसूली, पुलिस उत्पीड़न, पीट, हत्या, और कभी-कभी निष्कासन। वे खुद को कानूनी-न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना असंभव पाते हैं, जो अधिकारों के सही दावे बनाने के हकदार हैं। शहर (या एक पूरे के रूप में उत्तर बंगाल क्षेत्र) अभी तक किसी भी सामाजिक आंदोलन को सेक्स वर्कर्स और मोबाइल महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दों के बारे में रिपोर्ट नहीं किया है, लोडर, पोर्टर और छोटे वेतन अर्जक और अंडर वर्ग के लिए, रेलवे के लिए ऐसे बच्चों, जो तस्करी के लिए बेहद संवेदनशील हैं, चाय बाग़गार जो अपनी नौकरी खो देते हैं और शहर में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी खातों में, विशेष रूप से बच्चे के मुद्दे पर न्याय के लिए लड़ें और मजबूर प्रवास के महिला पीड़ितों को अधिकतर एनजीओ सक्रियता में कम समाज के किसी भी प्रकार के बिना किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए कम किया जाता है।

निरंतर मोबाइल स्थान और आबादी के मंथन मौजूदा प्रतिनिधि संस्थानों को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं देते - अकेले एकमात्र - एक की मांगें जबकि राजनीतिक दलों, लॉबी और हित समूहों की तरह हमारी राजनीतिक संस्थाएं प्रादेशिक रूप से विन्यस्त हैं, वैसे भी वैश्वीकरण के बल और प्रक्रियाओं के लिए न्याय के मुद्दों पर वास्तविक निराशात्मकता रही है। हालांकि इन बलों और प्रक्रियाओं ने न्याय-तलाश करने वालों को फैला दिया है, उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के आसपास बिखरे हुए हैं, पीड़ितों को यह मुश्किल लगता है - यदि असंभव नहीं है - उन्हें

वैश्विक स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक न्याय की भाषा में। पीड़ित जितना भी मोबाइल होता है, उतना अधिक वे सार्वजनिक वार्ता से निकल जाने की संभावना है जो राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले बड़े पैमाने पर जारी रहती हैं। बहुत सारे असंतोष जो फट जाता है, यदि सब कुछ हो, तो छिटपुट लगता है, 'जड़हीन' और क्षणिक।

हालांकि यह हमें यह समझने का एक सुराग देता है कि प्रवासियों का शहर होने के बावजूद, सिलीगुड़ी ने बेदखली और बेघर, शहरी गरीबी और पुलिस के अत्याचार और शहरी सुविधाओं की कमी के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण संघर्ष नहीं अनुभव किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पष्ट शांत जो शहर में मौजूद है वह हमेशा निरंतर नाजुक है और लगातार हिंसा की आशंका से भटकता है।

तथ्यों और आंकड़ों को सिलीगुड़ी नगर निगम (2001), अर्चना घोष और अन्य लोगों की रिपोर्ट से लिया गया है, शहरी गरीबों के लिए बेसिक सर्विसेज: बड़ौदा, भीलवाड़ा, संबलपुर और सिलीगुड़ी का एक अध्ययन [नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1 99 5] और टाइम्स ऑफ इंडिया और उत्तरबंगा संवाद सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट।

कोसी से दिल्ली: प्रवासियों के जीवन और श्रम
-पुष्पेंद्र और मनीष झा

इस अध्याय का उद्देश्य कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संरचना और पदानुक्रम और दिल्ली शहर में प्रवास के घटना के साथ उनके संबंधों को समझना है। यह गंतव्य पर प्रवासियों की स्थिति में उनके काम और रहने की स्थिति में पूछताछ करके और इस संबंध में राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करता है।

हाल के दशकों में, प्रवासन ने बिहार में भारी अनुपात अर्जित किया है। ऐसा अनुमान है कि अन्य राज्यों में काम कर रहे बिहारी प्रवासी मजदूरों के कुल संख्या 4.5 से 5 मिलियन हो सकती है। बिहार में भारत में सकल और शुद्ध अंतर-राज्य के बाहर-प्रवास दोनों के उच्चतम दर हैं। ऐतिहासिक रूप से, बिहार में प्रवास तीन चरणों से गुजर चुका है। पहले चरण में, ब्रिटिश प्रशासन की सक्रिय प्रवास नीति के तहत, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत अधिकांश प्रवासग्रस्त गरीबों के लिए गंतव्य था। दूसरा चरण औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ, खासकर जब साठ के दशक के अंत में हरित क्रांति के बाद, जब आबादी की दिशा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कृषिक्षेत्र में बदल दी गई थी। 1990 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत के बाद से तीसरे चरण का विशेष रूप से पता लगाया जा सकता है जब ग्रामीणों से शहरी प्रवास शुरू हो गया, जो प्रभावी प्रवृत्ति बन गया जो लोग शहरी इलाकों में पलायन करते हैं वे रहना पसंद करते हैं और बसने की इच्छा रखते हैं। दिल्ली शीर्ष स्थलों में से एक है और बिहारियों के 13 प्रतिशत लोगों को अवशोषित करता है। बिहार से दिल्ली तक प्रवासन ने भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। दिल्ली में कुल प्रवासियों में बिहार का हिस्सा 1971-81 से 19-1992 में 1979 के दौरान 5.77 प्रतिशत से बढ़ गया। दिल्ली में 4.24 लाख बिहारी प्रवासी की कुल संख्या रहते हैं। दिल्ली में उच्च प्रवासन कारक अवसरों जैसे बिहार से निकटता, कम पैसे और समय की लागत, भाषा में आसानी, पंजाब, हरियाणा और यूपी से निकटता के कारण कारकों से प्रभावित हो सकता है, जो उन्हें अपना स्वाभाव बदलने के लिए अनुमति देता है।

बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों से बाहर-प्रवास सबसे ज्यादा है। बाढ़, क्षेत्र में अत्यधिक कठिनाइयों और दुःख का कारण बना है, जिससे गरीबों को बिना किसी अन्य विकल्प को छोड़कर काम की तलाश में स्थानांतरित किया जा सकता है। सहरसा जिले जहां क्षेत्रीय कामकाज आयोजित किया गया, कोसी बाढ़ के प्रभावित जिलों में से एक है। नदी कोसी अपने पश्चिमी भाग से उत्तर से दक्षिण तक बहती है और अंततः कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में विलीन हो जाती है। इस जिले में कोसी सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई तटबंधों का एक नेटवर्क है। इतनी अधिक है कि इतने बड़े गांवों में बारिश के पानी से पड़ता है, क्योंकि वे सभी बार से जमा किए गए वर्षा जल के लिए बिना किसी आउटलेट के तटबंधों में घिरे रहते हैं। कुछ विशेषज्ञ इस स्थिति को मोचन से परे देखते हैं।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में, लोग दोनों को देखते हैं, स्थानीय कार्य की कमी और सामाजिक उत्पीड़न के कारण प्रवास के लिए मजबूर हैं। प्रवासियों, विशेष रूप से दलित और निम्न ओबीसी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मुक्ति के रूप में प्रवास पर विचार करें। प्रवासन ने स्थानीय नियोक्ताओं पर निर्भरता कम करने में मदद की है दलितों के लिए, ऊंची जातियों और ऊपरी पिछड़ी जाति और वर्ग के प्रभुत्व के साथ चरम गरीबी, गांव में अत्यधिक दमनकारी होते हैं। वे आर्थिक निर्भरता को अपने सामाजिक उत्पीड़न के मुख्य कारण के रूप में मानते हैं। प्रवासन ने मुक्त श्रम सेवाएं (भिखारी) को कम कर दिया है जो पहले उन्हें जमीन के मालिक को सौंपना पड़ा था। अगर स्थानीय क्षेत्र में नियमित रूप से काम की उपलब्धता होती है तो प्रवासन से शुद्ध आर्थिक लाभ के मामले में शायद ही कोई अंतर होता। हालांकि, प्रवासियों का मानना है कि वे अभी भी जाति के प्रभुत्व से बचने के लिए माइग्रेशन का विकल्प ले लेंगे।

उनके प्रेषण ने कई अन्य तरीकों से भी मदद की है उसके कारण गरीबी कम हो गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं पर उनके उधार को इनकार कर दिया है जो पहले उन्हें ऋणबंड में डाल दिया था। लोगों को अधिक और बेहतर भोजन तक पहुंच है और बीमारी के मामले में प्राथमिक उपचार की तलाश है जो कि अतीत में अनुपचारित रहेगी। कुछ लोगों ने अपने आवास में थोड़ा सुधार किया है प्रवासन पूरी तरह से भविष्य में उनकी स्थिति को बदल सकता है? एक स्पष्ट मध्यम आयु वर्ग के प्रवासी पल्तु सदाई कहते हैं, 'जब तक हम पंजाब या दिल्ली में तेंदुलकर (अनौपचारिक, व्याख्या, हमारा) श्रमिकों के रूप में पलायन करना जारी रख देते हैं, तो प्रवास केवल हमें जीवित रहने में मदद कर सकता है, और थोड़ा बेहतर बच सकता है। हम अपनी परिसंपत्तियां कभी भी उस हद तक नहीं बना सकते हैं जो माइग्रेशन अनावश्यक हो। लेकिन अब हम भूखे नहीं रहेंगे और जमीन के मालिकों से अनाज के लिए भीख नहीं मांगेंगे। यह सब हमने हासिल किया है। 'दिल्ली में घृणित आवास और स्वच्छ शर्तों और बिहारी श्रम के कलंक के बारे में पूछने पर, एक प्रवासी ने कहा,' हमें उम्मीद है कि हमारा काम गंतव्य स्वर्ग नहीं होगा। जब हम घर पर अच्छा इलाज नहीं करते हैं, तो अजनबियों के बारे में क्या बात करें। कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ हर जगह खराब होते हैं। फिर भी हम हर साल काम करते हैं और सुरक्षित होते हैं। हमने ऐसी स्थितियों में रहना सीख लिया है पृथ्वी पर समानता कहां है? लेकिन हम कमजोर नहीं हैं; हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सीख लिया है। '

क्षेत्रीय कथाएं बताती हैं कि स्रोत समूहों में भूमि समूहों, जाति के पदानुक्रम और शक्ति संरचना के संदर्भ में सामाजिक समूहों द्वारा उत्परिवर्तन के अंतर अनुभव कैसे असमानताओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जाति, वर्ग, भूमि स्वामित्व और लिंग इसके प्रभाव, गंतव्य पर काम की प्रकृति और भौतिक लाभों के संदर्भ में व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। परिवाहन, काम की प्रकृति और गंतव्य की पसंद के संदर्भ में प्रवासियों का स्रोत स्रोत पर उनकी शर्तों के अनुसार आकार लेते हैं। बेहद गरीब अकुशल हैं, मौसमी कार्य में अधिकतर संलग्न होते हैं, परिणामस्वरूप परिपत्र रहते हैं, वे उसी व्यवसाय की प्रतिलिपि बनाते हैं जो कि वे स्रोत पर करते हैं और उनके प्रेषण परिवार की आवश्यक खपत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च होते हैं। प्रवासन के उनके अनुभव कठिनाइयों से भरे हुए हैं, जो वे अनिवार्य रूप से अंतर्निहित होते हैं और जो उन्हें जोखिम भरे तरीके से अपने स्वयं के शरीर का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए मजबूर करते है। उनकी सामूहिक एजेंसी उपयोगी है जैसे मध्यस्थ प्रणाली को खत्म करने के लिए अपने स्वयं के सामाजिक नेटवर्क बनाने और प्रवासियों में दैनिक कामकाज के भार को साझा करने के लिए श्रम का एक विभाजन बनाने आदि। हालांकि, सामूहिक एजेंसी की संरचनात्मक असमानताओं का सामना करने में गंभीर सीमाएं हैं।

दिल्ली के तेजी से विकास और विस्तार के लिए अकुशल और अर्द्ध कुशल श्रम और आपूर्ति की आवश्यकता है। राज्य की नीति के करीब से जांच करते हुए पता चलता है कि दिल्ली में श्रम शक्ति का प्रमुख स्रोत के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासियों ने लगातार प्रोत्साहित किया है। लेकिन गरीब गांव के प्रवासियों को अत्यंत दु: खद परिस्थितियों में रहने की निंदा की जाती है - बेघर, सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में, या अस्थायी शरण में अनावश्यक स्थिति में पीने के पानी और स्वच्छता तक पहुंचे बिना। श्रमिकों को कम लागत वाली आवास या पारगमन आवास प्रदान करने में राज्य की असफलता के परिणामस्वरूप आवास की एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था हुई जिसमें झुग्गी-जुप्पदीस (गंदी बस्तियों) और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास हुआ। इनमें झुग्गी-जोपादी (जेजे) क्लस्टर शामिल हैं; जे.जे. पुनर्वास कालोनियों; झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों; नियमित-अनधिकृत कालोनियों; अनधिकृत कालोनियों और अधिसूचित झुग्गी क्षेत्र आज लगभग 65 प्रतिशत दिल्ली की आबादी ऐसी कालोनियों में रहती है (अनौपचारिक अनुमानों ने इस आंकड़े को 75 से 80 प्रतिशत के रूप में उच्च रखा क्योंकि आंकड़े परिभाषा पर निर्भर करते हैं और साथ ही सीमाओं के सीमांकन)। पश्चिम दिल्ली के कई क्षेत्रों में जे.जे. कालोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों में 9 5% जनसंख्या है। यद्यपि अनधिकृत और हाल ही में अधिकृत / नियमित कालोनियों में रहने वाले लोग अपेक्षाकृत अच्छी तरह से समूहों के लिए गरीबों के काम करने से सामाजिक समूहों के स्पेक्ट्रम से आते हैं, जो जे.जे. कॉलोनियों और मलिन बस्तियों की शेष श्रेणियों में रहते हैं, वे दिल्ली की आबादी

के सबसे गरीब समूह हैं और ज्यादातर प्रवासियों । जे जे कॉलोनियों में रह रहे लगभग साढ़े आठ से आठ लाख घरों में विध्वंस और निष्कासन की लहरों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों और स्थानीय राजनेताओं (हैज़र्ड सेंटर, 2007) द्वारा जारी किए गए किराये की मांग का सामना करना पड़ा है।

जेजे समूहों में 10 से 10 फीट के आकार वाले घरों के बड़े आकार वाले घरों के छोटे आकार के आकार होते हैं और इनमें मुख्य रूप से एक कमरे वाले घर होते हैं (जल सहायता भारत, 2005)। दिल्ली में आवास परिदृश्य दिखाता है कि शहर अपने गरीबों और प्रवासियों की बेहद वंचित स्थितियों को कैसे निंदा करता है। यह यह भी दिखाता है कि कैसे राज्य प्रवासी की आकांक्षाओं पर सरकार द्वारा तैयार की गई श्रेणियों की जगह बनाने की सीमा निर्धारित करता है और उसके अनुसार उनके अधिकारों का निर्णय करना। पुनर्वास कालोनियों में, एक गरीब परिवार को जमीन के उस छोटे पार्सल के लिए जीवन काल संघर्ष करने के बाद 18 वर्गमीटर तक की ज़मीन मिलती है। शहर में एक नए प्रवासी के लिए हाउसिंग सबसे बड़ी चुनौती है। इस स्थिति से निपटने के लिए, वह अपने सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करने के लिए शहर में प्रारंभिक पैर जमाने के लिए पसंद करते हैं। कुछ 6-8 लोग एक छोटे से, एक कमरे में रहने वाले रहते हैं और वर्ष के बाद एक ही त्रासदी को साझा करते हैं।

बढ़ते हुए प्रवासियों ने शहर में बसने के प्रयास किए हैं। अतीत में ऊंची जातियों के मामले में यह प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण थी। लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ हमारी चर्चा यह सुझाव देती है कि यह प्रवृत्ति अन्य सामाजिक समूहों में भी दिखाई दे रही है। इस परिवर्तन को कई दशकों तक निरंतर प्रवासन, एक सामाजिक समर्थन नेटवर्क का निर्माण, और मोबाइल फोन और रेल कनेक्टिविटी के लिए बेहतर संचार नेटवर्क धन्यवाद के संचित अनुभव जैसे कारकों से मदद मिलती है। एक स्पष्ट रूप से प्रवासियों के दो समूहों के बीच अंतर कर सकता है सबसे पहले वे लोग हैं जो एक दशक से कम समय के लिए प्रवास कर रहे हैं या हाल के वर्षों में दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या में शामिल हो चुके हैं और अपने गांव के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, त्यौहारों और सामाजिक अवसरों के दौरान नियमित रूप से यात्रा करते हैं, और अपने घर वापस कमाई का एक हिस्सा भेजते हैं। दूसरा, जो लोग दिल्ली में लंबे समय से रह रहे हैं, अपने परिवार लाए हैं, उपनिवेशों में बस गए हैं, और या तो प्रेषण नहीं भेजते हैं या कभी-कभी सबसे अच्छा भेजते हैं। धीरे-धीरे परिपत्र और बसने वाले प्रवासियों के बीच विभाजित लाइन धुंधली हो रही है।

भारत में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया ने क्षेत्रीय विकास के असमान स्तर का निर्माण किया है जो अपेक्षाकृत विकसित और कम-विकसित क्षेत्रों के बीच एक विभाजन पैदा करता है। विकसित क्षेत्रों में पूंजी विकास और विशाल गतिविधियों के केंद्र हैं, जो कि कम-विकसित क्षेत्रों से श्रम बल को आकर्षित करने और / या जबरन खींचने में सक्षम हैं, जिससे प्रवासन की घटनाएं पैदा हो रही हैं। शहरीकरण, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास और अनौपचारिक रोजगार की वृद्धि के लिए शहरों में श्रम की आवश्यकता होती है। नवउदार नीतियों के साथ, प्रवासन में अभूतपूर्व पैमाने की गति बढ़ गई है। इस प्रकार श्रमिकरण, स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों में उत्पादन के व्यापक सामाजिक संबंधों में स्थित होना चाहिए।

हालांकि, माइग्रेशन स्रोत और प्राप्त क्षेत्रों दोनों में श्रम और पूंजी के बीच एक निश्चित संबंध बनाता है। इस रिश्ते के दौरान श्रम हाशिए, विखंडन, हिंसा, कमजोरियों, सामाजिक सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच की कमी, विभिन्न स्तरों के अभाव, बहिष्कार और सौदेबाजी शक्ति की कमी के कारण होता है। श्रम शहरी गरीबों के थोक रूपों का निर्माण करता है प्रवासी शहरी गरीबों की अनिश्चित स्थिति मुख्य रूप से स्रोत क्षेत्रों में सामाजिक संरचना और उत्पादन संबंधों से प्रभावित होती है। परिपत्र प्रवासियों वे हैं जो गंतव्य पर मौसमी व्यवसायों में शामिल होते हैं। ये ज्यादातर कृषि मजदूर हैं, जिनमें से अधिकांश दलित जातियों और निम्न ओबीसी से आते हैं। जाति और वर्ग पदानुक्रम, भूमिहीनता, अल्प मजदूरी, पर्याप्त कार्य की कमी, 'कौशल' की कमी, खेती के उत्पादन का आंशिक मशीनीकरण, ऋण आदि स्रोत क्षेत्रों में उनकी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, स्थिति और शक्ति को आकार देते हैं। इन संरचनात्मक स्थितियों में ग्रामीण प्रवासियों के साथ, शहर में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रम के साथ जाल और गंतव्य पर स्थिति, स्थिति और शक्ति को दोहराने के लिए करते हैं। इस प्रकार, माइग्रेशन

परिणाम स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों को एक दुष्चक्र बनाने के लिए लिंक करते हैं। शहर में बसने वाले कुछ लोग अपनी स्थिति में मामूली रूप से सुधार कर सकते हैं और शायद अपने बच्चों के लिए बेहतर अवसर बना सकते हैं।

विस्तृत संदर्भ और पूर्ण पत्र के लिए कृपया देखें http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf.

Other MCRG Reports
Rohingyas : The Emergence of a Stateless Community
http://www.mcrg.ac.in/Rohingyas/Report_Final.pdf

Research on the Humanitarian Aspects along the Indo-Bangladesh Border
http://www.mcrg.ac.in/Indo_Bangladesh_Border/Report_on_Indo_Bangladesh_Border.pdf

Making Women Count for Peace: Gender, Empowerment and Conflict in South Asia
http://www.mcrg.ac.in/M_Women/A_Report_Making_Women_Count.pdf

Governance and Peace– Building http://www.mcrg.ac.in/Core/Guwahati_Core.pdf

Interrogating Forced Migration: A Research Workshop
http://www.mcrg.ac.in/WC_2015/Final_Report_on_Interrogating_Forced_Migration.pdf

Voices of the Internally Displaced in South Asia http://www.mcrg.ac.in/Voices.pdf

Eroded Lives http://www.mcrg.ac.in/Eroded_Lives.pdf

The Responsibility to Protect IDPs and Our National and State Human Rights Commissions
http://www.mcrg.ac.in/Responsibility_to_Protect.pdf

Annual Winter Course Report on Forced Migration (One to Ten)
http://www.mcrg.ac.in/rp_wc.asp

A Dialogue on Protection Strategies for People in Situations of Forced Migration
http://www.mcrg.ac.in/UNHCRconference/home.html

Gender, Media and Human Rights http://www.mcrg.ac.in/mediareport05.htm

Media and Displacement I, II, III http://www.mcrg.ac.in/rp_md.asp
Civil Society Dialogue on Human Rights and Peace http://www.mcrg.ac.in/rp_autonomy.asp

Research Papers under this Project

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor-I : Migration and the Urban Question in Kolkata
  http://www.mcrg.ac.in/PP72.pdf
- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor-II : Migration and the Urban Question in Mumbai
  http://www.mcrg.ac.in/PP73.pdf
- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor-III : Migration and the Urban Question in Delhi
  http://www.mcrg.ac.in/PP74.pdf
- Policing a Riot-torn City: Kolkata, 16-18 August 1946
  http://www.mcrg.ac.in/PP69.pdf

Reports of Other MCRG – Ford Foundation Projects

- A Research and Dialogue on Autonomy
  http://www.mcrg.ac.in/autonomy/autoreport.htm
- A Research & Dialogue Programme on Social Justice in India
  http://www.mcrg.ac.in/S_J_Report.pdf
- Development, Democracy, and Governance - Lessons and Policy Implications

http://www.mcrg.ac.in/Ford.pdf

Mahanirban Calcutta Research Group
GC-45, First Floor, Sector-III Salt Lake City, Kolkata-700 106, West Bengal, India
Phone: +91-33-23370408, Fax: +91-33-23371523
Email: mcrg@mcrg.ac.in;
Web: http://www.mcrg.ac.in

Other MCRG Reports

Rohingyas : The Emergence of a Stateless Community
http://www.mcrg.ac.in / Rohingyas / Report_Final.pdf

Research on the Humanitarian Aspects along the Indo - Bangladesh Border
http://www.mcrg.ac.in /Indo_Bangladesh_Border / Report_on_Indo_Bangladesh_Border.pdf

Making Women Court for Peace : Gender, Empowerment and Conflict in South Asia
http://www.mcrg.ac.in / M_Women / A_ Report_Making_Women_Court.pdf

Governance and peace - Building
http://www.mcrg.ac.in / Core / Guwahati_Core.pdf

Interrogating Forced Migration : A Research Workshop
http://www.mcrg.ac.in / WC_2015 / Final_Report_on_Interrogaing_Forced_Migration.pdf

Voices of the Internally Displaced in South Asia
http://www.mcrg.ac.in / Voives.pdf

Eroded Lives
http://www.mcrg.ac.in / Eroded_Lives.pdf

The Responsibility to Protect IDPs and Our National and State Human Rights Commissions
http://www.mcrg.ac.in / Responsibility_toProtect.pdf

Annual Winter Course Report on Forced Migration (One to Ten)
http://www.mcrg.ac.in / rp_wc.asp

A Dialogue on Protection Strategies for People in Situations of Forced Migration
http://www.mcrg.ac.in / UNHCR conference / home.html

Gender, Media and Human Rights
http://www.mcrg.ac.in / mediareport05.htm

Media and Displacement I, II, III
http://www.mcrg.ac.in / rp_md.asp

Civil Society Dialogue on Human Rights and Peace
http://www.mcrg.ac.in / rp_autonomy.asp

Research Papers under this Project

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - I : Migration and the Urban Question in Kolkata
  http://www.mcrg.ac.in / PP 72.pdf

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - II : Migration and the Urban Question in Mumbai
  http://www.mcrg.ac.in / PP 73.pdf

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - III : Migration and the Urban Question in Delhi
  http://www.mcrg.ac.in / PP 74.pdf

- Policing a Riot - torn City : Kolkata, 16 -18 August 1946
  http://www.mcrg.ac.in / PP 69.pdf

Reports of Other MCRG - Ford Foundation Projects

- A Research and Dialogue on Autonomy
  http://www.mcrg.ac.in / autonomy / autoreport.htm

- A Research and Dialogue Programme on Social Justice in India
  http://www.mcrg.ac.in / S_J_Report.pdf

- Development, Democracy, and Governance - Lessons and Policy Implications
  http://www.mcrg.ac.in / Ford. pdf

Mahanirban Calcutta Research Group

GC- 45, First Floor, Sector -III, Salt Lake City
Kolkata - 700 106, West Bengal, India
Phone : +91-33-23370408, Fax: +91-33-23371523
E-mail: mcrg@mcrg.ac.in; Web: http://www.mcrg.ac.in